R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 08
16 से 31 जनवरी 2025
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

महाकुंभ 2025

आस्था का महासंगम

144 साल बाद इस बार बना है ग्रहों का दुर्लभ संयोग

आत्म शुद्धि और मोक्ष की तलाश में विदेशी भी पहुंचे

प्रकृति के सम्मान का उत्सव
गौ-संरक्षण एवं संवर्धन के लिए
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
की अभिनव पहल
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
प्रदेशभर की
गौ-शालाओं में
गोवर्धन पर्व का
सामुदायिक आयोजन
प्रगति और पर्यावरण
के प्रति सजगता की
मिसाल बनता
मध्यप्रदेश
• प्रदेश में संचालित 1,500 से अधिक गौ-शालाओं में 3.30 लाख गौ-वंश का पालन। शीघ्र ही लगभग 2,500 नई गौ-शालाएं प्रारंभ होंगी जिनमें 4.50 लाख गौ-वंश का पालन हो सकेगा।
• गौ-वंश के बेहतर आहार हेतु प्रति गौ-वंश 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये की जा रही है।
• दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू। आगामी 5 वर्ष में लगभग 12,000 दुग्ध समितियां 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करेंगी।
• देश में सर्वाधिक 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती करने वाले मध्यप्रदेश में गौ-वंश को प्रोत्साहन देने की पहल से जैविक खेती उत्पादन बढ़ेगा।
• दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर ब्लॉक में एक 'वृंदावन ग्राम' बनेगा।
• गौ-शालाओं का बजट 150 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना में 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले CNG प्लांट की स्थापना।
मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी
आकल्पन : मध्यप्रदेश माध्यम/2024

इस अंक में

शराबबंदी

8 | पुलिस हैरान... पब्लिक परेशान

मप्र के कमाऊ विभागों में शामिल आबकारी विभाग ने जबसे अहाते बंद कर दिए हैं, उससे सरकार की आय तो कम हुई ही है, साथ ही पुलिस हैरान है और पब्लिक परेशान। दरअसल, अहाते बंद होने के कारण लोगों को...

डायरी

10-11 | कहां अटक गई तबादला...

मप्र में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार मंत्रालय से लेकर जिलों तक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग...

चौसर

13 | वनाधिकार और पेसा...

मप्र में भाजपा एक बार फिर से आदिवासियों पर फोकस करने जा रही है। प्रदेश के इस बड़े वोट को साधने के लिए भाजपा और प्रदेश सरकार वनाधिकार और पेसा कानून को धार देने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि भाजपा की नजरें विधानसभा की उन...

लालफीताशाही

15 | भर्ती परीक्षाओं की बढ़ेगी...

मप्र सरकार नए साल में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। इस खबर को सुनकर प्रदेश के लाखों युवा उत्साहित हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की चाह वाले युवाओं पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी हो रही है। यानी मप्र कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी इस साल...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

पौष पूर्णिमा यानि 13 जनवरी से आस्था के महासंगम महाकुंभ का शुभारंभ तीर्थराज प्रयागराज में हो गया है। 144 साल बाद इस बार ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है, इसलिए इस महाकुंभ का महत्व और बढ़ जाता है। महाकुंभ के पहले दिन ही करोड़ों लोगों ने संगम पर डुबकी लगाई। महाकुंभ का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की तलाश में विदेशी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

राजनीति

30-31 | खत्म होगा 26 साल...

भाजपा पिछले 26 साल से दिल्ली में सत्ता का वनवास झेल रही है। वो विधानसभा चुनाव-2025 में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके बाद भी भाजपा के लिए दिल्ली के सत्ता की राह आसान नहीं है।

महाराष्ट्र

35 | महाखेला की तैयारी

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अभिनंदन देवाभाऊ के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक...

बिहार

37 | नीतीश कुमार का फ्यूचर...

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार नाम का एक ऐसा हीरो या पात्र मौजूद है, जिसके इर्द-गिर्द ही बीते 20 सालों से बिहार की राजनीति घूमती रही है। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए हो या महागठबंधन सभी को नीतीश कुमार की जरूरत...

6 -7 अंदर की बात
40 विदेश
41 महिला जगत
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-08, पृष्ठ-48
16 से 31 जनवरी, 2025

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

राजदार सौरभ शर्मा...कब पकड़ा जाएगा?

शायर रउफ खैर का एक शेर है...

गिरफ्तारी के सब हरबे शिकारी ले के निकला है
परिंदा भी शिकारी की सुपारी ले के निकला है

ये पंक्तियां इन दिनों मप्र के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा और उसके खिलाफ जांच कर रही तीन एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सटीक बैठ रही हैं। दरअसल, लोकायुक्त के छापे के बाद सौरभ शर्मा के खिलाफ आयकर विभाग और ईडी ने भी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कथित तौर पर सौरभ शर्मा और उसके परिजनों के पास से काली कमाई का ऐसा भंडार मिला है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सौरभ शर्मा की काली कमाई इस बात का संकेत है कि प्रदेश के परिवहन विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार समाया हुआ है। सौरभ शर्मा से मंत्रियों, नेताओं और अफसरों को जोड़कर कई तरह की कहानियां गढ़ी और सुनाई जा रही हैं। ऐसे में सौरभ शर्मा एक ऐसी पहेली बन गया है, जिसे सुलझाने में तीन जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक वे तह तक नहीं पहुंच पाई हैं। सौरभ शर्मा की कमाई और उसके संबंधों की हकीकत तभी पता लग पाएगी, जब वह गिरफ्तार होगा। लेकिन काली कमाई और भ्रष्टाचार के बड़े राजदार सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो पाएगी, यह सवाल भी लगातार उठ रहा है। गौरतलब है कि जांच एजेंसियां उसे गिरफ्तार करने के लिए पूरे अस्त्र-शस्त्र के साथ जुटी हुई हैं। वहीं सौरभ शर्मा भी जमानत के लिए हाथ-पैर मार रहा है। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा दुबई में है। लेकिन असल में वह कहां है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उधर, राजदार सौरभ शर्मा को लेकर विपक्ष सत्तापक्ष पर लगातार हमला कर रहा है। अभी हाल ही में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सौरभ शर्मा मामले में बड़ा आरोप लगाया है और जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस केस की तीन एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले में न किसी की गिरफ्तारी हुई है और न किसी से पूछताछ। ऐसा लग रहा है कि जांच एक जगह आकर रुक गई है। इसके पीछे कौन है, यह पता लगाना जरूरी है। पटवारी ने जांच को जल्द और पारदर्शी तरीके से पूरा करने की मांग की, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पटवारी की आशंका वाजिब है। क्योंकि सौरभ शर्मा जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक उसकी आड़ में तरह-तरह की कहानियां गढ़-गढ़कर नेताओं और अफसरों को टारगेट किया जाता रहेगा। यही नहीं सौरभ शर्मा जब गिरफ्तार होगा, तब ही इस बात से पर्दा हट पाएगा कि उसकी काली कमाई के जिस साम्राज्य का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसमें कितनी सत्यता है और उसके पीछे कौन-कौन लोग हैं। दावा किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा के यहां लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 11 करोड़ रुपए नगद और 55 किलो सोना बरामद हुआ था। इस छापेमारी में एक डायरी का जिक्र हुआ था। दावा किया जा रहा है कि डायरी के इन 6 पन्नों में एक चेकपोस्ट से 1536 करोड़ रुपए का हिसाब है। दूसरा हिसाब 103 करोड़ और तीसरा हिसाब 155 करोड़ रुपए वन टाइम पेमेंट का हैं। तो फिर 66 पन्नों में क्या होगा। इन तमाम दावों की हकीकत क्या है, यह तो फिलहाल सत्यता से दूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में एक तरफ सरकार सुशासन का दम भर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार करने में अभी तक असफल रही है। सवाल उठता है कि अगर सरकारी व्यवस्था को घुन की तरह नष्ट करने वाले कानून व्यवस्था के लिए इसी तरह चुनौती बने रहेंगे तो सुशासन की परिकल्पना कैसे साकार होगी?

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

पानी से मिलेगी निजात

मप्र में जब भी सूखे की खबर आती थी, तो बुंदेलखंड का नाम सबसे पहले जहन में आता था। पानी की कमी से पलायन की मार झेल रहे बुंदेलखंड के किसानों की मुश्किलें अब खत्म होने वाली हैं। केन–बेतवा लिंक परियोजना से यहां के 10 जिलों को इस समस्या से निजात मिलेगी।

● **अनिरुद्ध भार्गव,** सागर (म.प्र.)

दुर्घटनाओं पर अंकुश कब?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट में मप्र के आंकड़े शॉकिंग हैं। मप्र चौथे नंबर पर है। मप्र में इतनी बड़ी तादाद में रोड एक्सीडेंट होने के पीछे खराब सड़कें, स्पीड, शराब पीना, मोबाइल पर बात करना प्रमुख कारण हैं। इस विषय में कोई नई नीति जरूर आनी चाहिए।

● **पिंकी यादव,** भोपाल (म.प्र.)

नदियां हो रहीं प्रदूषित

एमपीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार कान्ह सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। वहीं चंबल का पानी भी डी–कैटेगरी का है। चंबल नदी में उज्जैन के जूनानागदा, इटलावदा, गीदघर में पानी डी–कैटेगरी का है। सरकार को नदियों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **सुरभि दीक्षित,** इंदौर (म.प्र.)

कब मिटेगा कुपोषण...?

सरकार के तमाम वादों और दावों के बावजूद प्रदेश के आदिवासी इलाके कुपोषण के दंश से बेहाल हैं। प्रदेश के 15 लाख में से करीब 70 हजार बच्चे कुपोषण के दायरे में हैं। कुपोषण समाप्त करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कुपोषण की स्थिति कम नहीं हो पा रही है। इसका मुख्य कारण आंगनवाड़ी पर मिलने वाली सुविधाएं बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही हैं।

● **राहुल जैन,** मक्सी (म.प्र.)

परीक्षा शुल्क से मिले राहत

मप्र के सभी विभागों में खाली पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा कराता है। इसके अलावा मंडल द्वारा प्रवेश परीक्षाएं भी ली जाती हैं। भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं पर मंडल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क वसूला जाता है। खास बात यह है कि मंडल परीक्षा कैलेंडर के पालन में भी पिछड़ा हुआ है। न तो समय पर रिजल्ट जारी हो रहे है और न ही परीक्षाओं का आयोजन समय पर हो पा रहा है। परीक्षा प्रणाली में तमाम सुधार के बाद भी पेपर आउट हो जाते हैं और परीक्षाओं में भी गड़बड़ी हो रही है। वर्तमान में मंडल के पास 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की एफडी है। इसके बाद भी बेरोजगारों को शुल्क से राहत नहीं दी जा रही है।

● **मनीषा वर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

योगी पर सबकी नजर

लोकसभा चुनाव हों या विधानसभा चुनाव, योगी आदित्यनाथ का नाम भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। वे राजस्थान, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड से लेकर साउथ में तमिलनाडु और तेलंगाना तक चुनावी रैलियां कर चुके हैं। नवंबर में हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे का असर भी दिखा। आने वाले चुनावों में भी योगी आदित्यनाथ पर ही सबकी नजर बनी रहेगी। कई लोग उन्हें भविष्य में प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं।

● **नितेश कुमार,** बैतूल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

फिर रघुवर के हवाले झारखंड

झारखंड में भाजपा को सत्ता वापसी की पूरी उम्मीद थी लेकिन चुनाव नतीजे उसकी आशा के ठीक उलट आए और चुनावों से ठीक पहले ईडी की जांच में लपेटे गए, जेल गए हेमंत सोरेन पूरे दमखम के साथ वापस सत्ता में काबिज हो गए। अब रांची के राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवर दास राज्य की राजनीति में रीएंट्री करने जा रहे हैं। भाजपा आलाकमान ने 2023 में उड़ीसा का राज्यपाल बना झारखंड से दूर कर दिया था लेकिन खांटी राजनीतिज्ञ रघुवर दास को राजभवन की शानो शौकत सुहाई नहीं। अब यकायक ही उन्होंने राज्यपाल पद से त्याग पत्र देकर इन चर्चाओं को गर्मा दिया है कि वे वापस एक्टिव राजनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रघुवर दास पूरे गाजे-बाजे के साथ दोबारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ओबीसी नेता दास की राज्य में खासी जमीनी पकड़ बताई जाती है लेकिन उन पर 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहते आदिवासियों के हितों को नजरअंदाज करने का आरोप भी चस्पा है। इसी आरोप के चलते उन्हें राज्य की राजनीति से दूर कर दिया गया था। हालांकि उनकी बहू पूर्णिमा साहू को गत विधानसभा चुनाव में पार्टी ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से टिकट दिया और वह चुनाव भी जीतीं।

उद्धव के बदलते सुर

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद शिवसेना (उद्धव) के अध्यक्ष और बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे एक बार फिर भगवा खेमे में शामिल होने को आतुर दिखाई पड़ने लगे हैं। पांच बरस पहले मुख्यमंत्री बनने पर अड़े उद्धव ने भाजपा संग अपनी पार्टी के दशकों पुराने संबंध तोड़ लिए थे। इसके बाद लगातार ही शिवसेना का रुख भाजपा के प्रति कठोर होता चला गया। अब लेकिन शिवसेना के मुखपृष्ठ सामना में प्रकाशित एक आलेख ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर प्रशंसा कर इस बदलाव की बुनियाद रख दी है। महाराष्ट्र में इन दिनों चर्चा गर्म है कि उद्धव महाविकास अघाड़ी गठबंधन से दामन छुड़ा भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में इंट्री मारने का रास्ता तैयार करने में जुट गए हैं। कहा-सुना यह भी जा रहा है कि भाजपा नेतृत्व भी एकनाथ शिंदे के दबाव से मुक्त होना चाहता है और उसका इरादा भी येन-केन प्रकारेण उद्धव ठाकरे संग दोबारा दोस्ती करने का है।

उप्र भाजपा में घमासान

उप्र में भाजपा संगठन और योगी सरकार के मध्य तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। संगठन के वरिष्ठ नेताओं को योगी से शिकायत है कि वो नौकरशाहों के भरोसे सरकार चलाते हैं और संगठन के पदाधिकारियों और चुने गए जनप्रतिनिधियों की एक नहीं सुनते। पहले ऐसे आरोप बंद कमरों में भाजपाई लगाया करते थे, लेकिन अब खुलकर बयानबाजी होने लगी है। उप्र विधानपरिषद् के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने तो गत दिनों वरिष्ठ मंत्री नंद गोपाल नंदी पर खुला हमला ही बोल दिया। उन्होंने नंदी पर आपराधिक पृष्ठभूमि के अफसरों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाने का आरोप लगाकर लखनऊ के सत्ता गलियारों में सनसनी फैलाने का काम कर डाला। अभी इस विवाद का पटाक्षेप भी नहीं हुआ था कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल, जो स्वयं योगी सरकार में मंत्री हैं, ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर डाली जिसमें उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री योगी की सत्ता को चुनौती देते हुए कई गंभीर आरोप योगी के दो विश्वस्त अफसरों पर लगा डाले। बकौल पटेल योगी के करीबी अफसर और राज्य के सूचना निदेशक शिशिर शेखर और राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स के मुखिया अमिताभ यश उनकी छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं।

गिरिराज का नवीन प्रेम

भाजपा की उड़ीसा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। इसके बावजूद यहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी इन दिनों खासे परेशान बताए जा रहे हैं। कारण है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान। बीते छह महीनों में नवनियुक्त मुख्यमंत्री ने हर वो काम किया है जिससे राज्य में भाजपा का जनाधार मजबूत हो और बीजू जनता दल का वजूद ही समाप्त हो जाए। मुख्यमंत्री मोहन चरण लगातार पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद के अध्यक्ष नवीन पटनायक को उड़ीसा की बदहाली का जिम्मेदार ठहराकर कोसने का काम भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीते 24 बरस के दौरान लगातार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक ने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो राज्य और जनहित में हो। उनके इस स्टैंड से ठीक उलट गिरिराज सिंह ने गत दिनों नवीन पटनायक की जमकर प्रशंसा ही नहीं कर डाली, बल्कि केंद्र सरकार से उन्हें भारतरत्न से सम्मानित करने तक की गुहार लगा दी। उड़ीसा सरकार और प्रदेश भाजपा संगठन केंद्रीय मंत्री के इस बयान को न तो नकार पा रहा है और न ही स्वीकार कर पा रहा है।

टीम जेएनयू भरोसे प्रियंका

कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से लेकर सभी प्रदेशों के कांग्रेस मुख्यालयों में इन दिनों बड़ी चर्चा है कि वायनाड सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चारों तरफ वामपंथी विचारों वाले जेएनयू के पूर्व छात्रों का घेरा बन चुका है जिसे पार कर पाना आम और खास, दोनों प्रकार के कांग्रेसियों के लिए लगभग असंभव हो चला है। ऐसे पूर्व छात्र नेताओं में पहला नाम संदीप सिंह का है जो प्रियंका के इन दिनों बेहद करीबी सलाहकार बन चुके हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके संदीप सिंह की अक्खड़ मिजाजी से कई बड़े कांग्रेस नेता तक नाराज बताए जाते हैं। इसी प्रकार प्रियंका का सोशल मीडिया देख रहे मोहित पांडेय भी वामपंथी छात्र संगठन आइसा से जुड़े रहे हैं और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइसा से ही ताल्लुक रखने वाले एक अन्य पूर्व छात्र नेता अमित यादव भी टीम प्रियंका का हिस्सा हैं और उप्र में उनका काम देखते हैं। इतना ही नहीं आइसा के सदस्य रह चुके शहनवाज आलम भी प्रियंका की कोर टीम में शामिल हैं।

काम भी हो गया और दाग भी नहीं लगा

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में कई अफसरों के परिवारवाद की चर्चा अक्सर होती ही है। दरअसल, अफसर अपने परिजनों को आगे बढ़ाने के लिए कायदे-कानून को ताक पर रख देते हैं। लेकिन एक आईएएस अधिकारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को नौकरी भी दिलवा दी और कोई कायदा-कानून भी नहीं टूटा। यानि काम भी हो गया और दाग भी नहीं लगा। दरअसल, ये साहब वर्तमान में शिक्षा-दीक्षा वाले एक विभाग में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहां साहब के पास सुबह से ही दरबारियों का मजमा लग जाता है। साहब ने मौके की नजाकत को देखते हुए अपने विभाग से ही संदर्भित एक संस्था में किसी के माध्यम से अपनी पत्नी की नौकरी लगवा दी है। सूत्र बताते हैं कि साहब ने एक तीर से कई निशाने को साध लिया है। यानि पत्नी को ही खुश कर दिया है और उक्त संस्था पर भी कृपा बरसा दी है। इसको देखकर साहब के करीबी आश्चर्यचकित हैं और कह रहे हैं, काम भी हो गया और दाग भी नहीं लगा। यह फॉर्मूला तो सबसे सटीक है। यहां बता दें कि कुछ दिन पहले ही साहब की गाड़ी में से सांप निकला था। जिसकी चर्चा खूब हुई, लेकिन साहब द्वारा जुगाड़ लगाकर पत्नी को नौकरी दिलाने का मामला चर्चा में नहीं आ पाया।

ट्रेनिंग में ही मन गया हनीमून

शीर्षक पढ़कर आपको हैरानी तो हुई ही होगी, लेकिन ऐसा अजब-गजब वाले मप्र के अफसरों (महिला-पुरुष) ने कर दिखाया है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसरों द्वारा की गई इस हरकत की प्रशासनिक वीथिका में चटखारे ले-लेकर चर्चा हो रही है। सूत्रों का कहना है कि इन अफसरों ने अपने प्रदेश और देश में नहीं बल्कि विदेश में गुल खिलाया है। दरअसल, कानून व्यवस्था से जुड़े इन अफसरों की एमसीटीपी-4 ट्रेनिंग यूके में रखी गई थी। इस ट्रेनिंग में कई पुरुष और महिला अधिकारी शामिल हुए थे। ये लोग गए तो थे ट्रेनिंग पर, लेकिन इस दौरान जमकर मौज-मस्ती की। घूमने-फिरने के साथ ही इन्होंने जमकर शराब पी और पार्टी की। ऐसा लग रहा था कि सरकार ने इन्हें इसी के लिए भेजा है। इन्हीं में एक शादीशुदा पुरुष और एक महिला अधिकारी ऐसे थे, जो अंग्रेजी हवा लगते ही बहक गए। अपने-अपने परिवार से दूर जब ये लोग विदेशी धरती पर पहुंचे तो इस कदर स्वच्छंद हो गए कि इन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर लीं। सूत्रों का कहना है कि उम्र के ढलाव पर होने के बाद भी दोनों ने अपनी-अपनी शादी को भूलकर हनीमून तक मना लिया। भले ही इन लोगों ने चोरी-छिपे ऐसा किया, लेकिन बात कानोंकान चारों तरफ फैल गई है। अब सवाल उठ रहा है कि सरकार ने इन्हें ट्रेनिंग पर भेजा था या हनीमून मनाने के लिए।

मीटिंग-मीटिंग खेलकर बोर हो गए...

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में अफसरों की दिनचर्या इस कदर हो गई है कि वे उससे आजीज हो चुके हैं। दरअसल, अफसर घर से तैयार होकर मंत्रालय पहुंचते हैं कि विभाग के महत्वपूर्ण काम को अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन अक्सर उनके पास बड़े साहब की मीटिंग के लिए बुलावा आ जाता है। अपने विभाग के कक्ष में फाइलों को निपटाने में लगे अफसर आधा-अधूरा काम छोड़कर बड़े साहब के साथ मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। वहां मीटिंग का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि घंटों तक चलता रहता है। बड़े साहब मीटिंग में अफसरों को प्रशासनिक बारीकी, सुशासन, सतर्कता और सक्रियता का पाठ पढ़ाते रहते हैं और अफसर ऊंघते रहते हैं। आलम यह है कि बड़े साहब की मीटिंग से अफसर इस कदर बोर हो गए हैं कि वे अनमने ढंग से मीटिंग में शामिल तो होते हैं, लेकिन अधिकांश की कोशिश यही रहती है कि पीछे ही बैठा जाए। एक अफसर तो यहां तक कहते हैं कि साहब काम की बातों की जगह ज्ञान की बातें अधिक कहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है हम किसी बाबा के प्रवचन सुन रहे हैं। यही नहीं, एक अफसर तो यह कहते हैं कि साहब रोज नए-नए लक्ष्य तय करते हैं लेकिन पिछले लक्ष्य पर कभी चर्चा ही नहीं होती है। ऐसे में स्थिति ऐसी हो गई है कि न पहले के काम हो पा रहे हैं और न ही आज के। अधिकांश अफसरों की कोशिश यह रहती है कि वह कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा बोलें जिससे बड़े साहब खुश रहें।

दो अफसरों में तू-तू, मैं-मैं

ब्यूरोक्रेट्स के लिए कहा जाता है कि ये काफी शिष्ट होते हैं और अपने वरिष्ठों का आदर-सम्मान करते हैं। लेकिन मप्र कैडर के कुछ आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो अपने वरिष्ठों का मान-सम्मान रखना भूल जाते हैं। ऐसा ही एक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि एक विभाग में पदस्थ 2014 बैच की महिला आईएएस अधिकारी जो अपनी तल्खी और गर्ममिजाजी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने एक फाइल को लेकर अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ तू-तू, मैं-मैं कर लिया। दरअसल, विभाग के बड़े साहब ने एक फाइल मैडम के पास भेजी थी, जिसे मैडम को अप्रूव करना था। साहब ने इस संदर्भ में मैडम को निर्देशित किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना अधिकार जानती हूं और नियमों के तहत ही ये फाइल अप्रूव होगी। सूत्र बताते हैं कि मैडम का टका सा जवाब सुनकर साहब उनका मुंह ताकते रह गए। दरअसल, साहब किसी फायदे के लिए उक्त फाइल को जल्द से जल्द अप्रूव कराना चाहते थे, लेकिन मैडम का स्वभाव ही ऐसा है कि वे कायदे-कानून के बाहर जाकर कुछ नहीं करती हैं।

जमीन के लिए मचा संग्राम

प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी में एक भूखंड को लेकर सत्तापक्ष के नेताओं में इस कदर झगड़ा बढ़ गया है कि उसकी शिकायत प्रशासन के साथ ही संगठन तक पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार व्यावसायिक राजधानी में सत्तापक्ष के एक पार्षद की जमीन पर उनकी ही पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कब्जा कर लिया है। जब यह बात पार्षद को पता लगी तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन है, जिसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लेकिन कोई भी इसको बताने को तैयार नहीं था। काफी हाथ-पांव मारने के बाद उन्हें पता लगा कि उनकी जमीन पर पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष ने ही कब्जा किया है। जब पार्षद ने उक्त नेता से इस संदर्भ में बात की तो उन्होंने उस समय तो कब्जा हटा लिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उस पर कब्जा कर लिया। मामला इतना तूल पकड़ गया कि विवाद पार्टी संगठन के पास पहुंच गया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पार्षद की बजाय जमीन कब्जाने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष को अपना समर्थन दे रहे हैं। इसकी चर्चा प्रशासनिक वीथिका में भी हो रही है।

पुलिस हैरान... पब्लिक परेशान

मप्र के कमाऊ विभागों में शामिल आबकारी विभाग ने जबसे अहाते बंद कर दिए हैं, उससे सरकार की आय तो कम हुई ही है, साथ ही पुलिस हैरान है और पब्लिक परेशान। दरअसल, अहाते बंद होने के कारण लोगों को इधर-उधर सुनसान जगह पर बैठकर शराब पीना पड़ रहा है। ऐसे में कानून व्यवस्था के कारण पुलिस वालों को ऐसे लोगों की धरपकड़ करनी पड़ रही है। जिससे माहौल कभी-कभी बिगड़ भी जाता है। दरअसल, प्रदेश में अहातों को बंद करने के पीछे बड़ा राजनीतिक खेल हुआ है।

सूत्रों का कहना है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ तो कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी। यह सरकार 15 महीने ही चल पाई थी कि 2020 में भाजपा के रणनीतिकारों ने सत्ता परिवर्तन का अभियान चलाया और तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ लिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर सिंधिया को लंच के लिए बुलाया गया। इस लंच पॉलिटिक्स के बाद सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री के लिए उछला। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने कमान संभाली और दिल्ली दौड़ शुरू की। नरोत्तम का ही प्रभाव था कि सिंधिया को दरकिनार कर शिवराज को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवराज की इस सरकार में नरोत्तम मिश्रा गृहमंत्री बने। गृहमंत्री बनते ही उन्होंने अपने समधी लल्ला शिवहरे को आगे बढ़ाया और प्रदेशभर में शराब के ठेके उन्हें दिलवाए।

गृहमंत्री का समधी होने के कारण लल्ला शिवहरे ने शराब के ठेकों पर तैनात अपने कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया कि अगर कोई पुलिस वाला भी आकर वसूली करे तो उसका नाम और नंबर नोट कर लें। इसका असर यह हुआ कि हर महीने थाने वाले शराब दुकानों से जो राशि प्राप्त करते थे, वह उन्हें मिलनी बंद हो गई। यही नहीं, जब कभी कोई पुलिस वाला शराब दुकान वालों पर दबाव बनाता था तो मंत्री के पीए पांडे जी का फोन उसके पास पहुंच जाता था।

धीरे-धीरे यह बात सरकार तक पहुंचने लगी। ऐसे में कमलनाथ ने सरकार से शराबबंदी करने की मांग करनी शुरू कर दी। बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर ही कमलनाथ ने यह मांग उठाई। मामले को और हवा देने के लिए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को आगे कर दिया। उमा भारती ने राजधानी में कई शराब दुकानों पर जाकर हंगामा किया और पत्थरबाजी भी की। इसका परिणाम यह हुआ कि शराबबंदी का माहौल प्रदेशभर में बनने लगा। उमा भारती की आक्रामकता को बढ़ता देख नरोत्तम मिश्रा ने उनसे मुलाकात की और उनके निवेदन के बाद साध्वी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया।

सूत्र बताते हैं कि प्रदेशभर में लल्ला शिवहरे के बढ़ते साम्राज्य को देखते हुए अन्य राजनेता भी नरोत्तम मिश्रा से खार खाने लगे। ऐसे में प्रदेशभर में शराबबंदी की मांग जोर पकड़ने लगी। शराबबंदी के खिलाफ बहती हवा को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि नई आबकारी नीति में शराब दुकानों के साथ चलने वाले अहाते बंद किए जाएंगे। आंदोलन तेज होता देख मीडियाकर्मी जब शिवराज सिंह के पास गए तो उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा ने अहाते बंद करने की घोषणा की है। उसके बाद जब मीडियाकर्मी नरोत्तम के पास गए तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर मुख्यमंत्री के निर्देश पर नई आबकारी नीति बनाई गई और 1 अप्रैल 2023 को इसे लागू किया गया। इस नीति के तहत प्रदेशभर में अहाते बंद कर दिए गए।

जानकारों का कहना है कि दो नेताओं के बीच शराब की कमाई को लेकर छिड़ी यह जंग अहातों के बंद के बाद ही थमी। लेकिन अहाते बंद होने के बाद शराब पीने के आदी लोगों की फजीहत होने लगी। क्योंकि अहाते बंद होने के बाद लोग शराब की बोतल दुकानों से खरीदकर घर जाते तो वहां उन्हें पत्नी-बच्चों और अन्य परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ता। इसलिए लोग शराब की दुकानों के आसपास या गली-कूचों या सुनसान जगहों पर डेरा जमा लेते हैं। उधर, कानून व्यवस्था की आड़ में पुलिस वाले ऐसे लोगों को पकड़कर वसूली करती है या फिर चालान बनाकर कोर्ट से जमानत लेने को भेज देती है।

● कुमार राजेंद्र

राजस्व घटा, परेशानी बढ़ी

मप्र में अहाते बंद होने से सरकार के राजस्व में कमी तो आई ही, साथ ही लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मप्र में सरकार की आयकर का एक बड़ा साधन शराब है। प्रदेश सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि वह ऐसी आबकारी नीति बनाए, जिससे अधिक आय हो सके। लेकिन दो नेताओं के वर्चस्व की जंग का परिणाम यह हुआ है कि अहाते बंद होने के बाद पुलिस हैरान है और पब्लिक परेशान। शराब पीने के आदी लोग दुकानों से शराब की बोतल तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसे पीने के लिए उनके पास जगह नहीं होती है। ऐसे में लोग इधर-उधर बैठकर शराब पीते हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल पुलिस ने इधर-उधर बैठकर शराब पीने वाले शराबियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। सभी थानों के पुलिस बल को निर्देश दिया गया है कि जो भी सार्वजनिक जगह पर शराब का सेवन करते पाया जाए उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। साथ ही जो शराब पीकर वाहन चला रहा हो उसे भी चिन्हित कर उस पर भी कार्रवाई की जाए। इसका परिणाम यह हुआ है कि पहले से पुलिस की कमी का रोना रो रहे थानों को कुछ जवानों को शराब दुकानों के आसपास तैनात करना पड़ रहा है। जब तक दुकान बंद नहीं हो जाती, पुलिस वाले चाकरी करते रहे हैं।

कागजी जल जीवन योजना धरासायी

मशहूर शायर अदम गोंडवी ने लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं ऐ दावा किताबी है... शुद्ध पेयजल के लिए चर्चित जल जीवन मिशन की हर-घर नल से जल योजना पर भी यह लागू होता है। कागज में यह भी ठीक बताई जा रही है, जबकि हकीकत में इसका भी हाल ठीक नहीं है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अपर सचिव और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तत्कालीन निदेशक भरतलाल ने इसका खाका तैयार किया था। घर-घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के मकसद से 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई जल जीवन मिशन योजना अधर में लटकी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत करते हुए मार्च 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा था। और नारा दिया गया था कि देश ने ये ठाना है, 2024 तक प्रत्येक घर में नल से जल आना है।

लेकिन कागजी योजना बनाने और मिस मैनेजमेंट के कारण जल जीवन योजना आज अधर में लटक गई है। दरअसल, जिस समय योजना बनाई गई थी, उस समय इसका बजट 3.60 लाख करोड़ रुपए रखा गया था। लेकिन जब योजना धरातल पर उतरी तो इसका स्वरूप बढ़कर 8.33 लाख करोड़ रुपए का हो गया। आलम यह है कि अभी भी देश के अधिकांश क्षेत्रों में योजना आधी-अधूरी पड़ी हुई है। जानकारों का कहना है कि धरातल पर उतरे बिना ही अपर सचिव और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तत्कालीन निदेशक भरतलाल ने कागजों पर ही योजना का स्वरूप तैयार किया।

जानकारों का कहना है कि जब योजना को धरातल पर उतारा गया तो दुर्गम भूभाग और खासतौर पर पानी की कमी वाले इलाकों में योजना को अमलीजामा पहनाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन इलाकों तक पानी पहुंचाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ी। जिसमें काफी समय लगने लगा और केंद्रीय फंड की कमी और पहले से हो चुके काम का भुगतान न होने के कारण यह योजना अटक गई है। देरी से बजट 3.60 लाख करोड़ से बढ़कर 8.33 लाख करोड़ पहुंच गया है। केंद्र ने इस वित्त वर्ष में मप्र को मिशन के लिए 4,044 करोड़ रुपए और राज्य ने 7,671.60 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के मुताबिक वर्क ऑर्डर में केंद्र-राज्य का हिस्सा 50-50 प्रतिशत और व्यावसायिक गतिविधियों में 60-40 प्रतिशत होगा।

गौरतलब है कि पानी सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। पानी आने वाले दिनों में एक अधिक जरूरी राजनीतिक मुद्दा बनने जा रहा है। 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने इतिहास के सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है और लाखों लोगों की जान और आजीविका खतरे में है। वाटर ऐड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में भारत भू-जल का दुनिया का सबसे बड़ा यूजर है। यह चीन और अमेरिका दोनों को मिलाकर भी ज्यादा है। सरकार ने नवंबर 2019 में संसद को बताया था कि देश में भू-जल स्तर में 2007 और 2017 के बीच 61 प्रतिशत की गिरावट आई। अगर भारत एक साथ जल स्रोतों को मजबूत करने का प्रबंध करता है तो यह योजना काम करेगी। हम बैकएंड को ठीक करने के लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि इससे पानी का अधिक शोषण न हो। भारतीय गांवों में पीने के पानी की आपूर्ति के पिछले प्रयास काफी हद तक विफल रहे हैं। इसको देखते हुए मोदी सरकार ने जल जीवन मिशन की योजना बनाई। मोदी सरकार की इस योजना में गांवों, राज्यों और निजी कंपनियों के साथ काम करने का आह्वान किया गया है। इसकी शुरुआत में ही कुछ अच्छे नतीजे दिखने लगे। लेकिन जैसे-जैसे योजना आगे बढ़ती रही फंड की कमी समस्या बनती चली गई। केंद्र ने इस वित्त वर्ष में मप्र को मिशन के लिए 4,044 करोड़ रुपए और राज्य ने 7,671.60 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। जल जीवन मिशन की गाइडलाइन के मुताबिक वर्क ऑर्डर में केंद्र-राज्य का हिस्सा 50-50 प्रतिशत और व्यावसायिक गतिविधियों में 60-40 प्रतिशत होगा। बीते साल जल जीवन मिशन के तहत मप्र में 10,773.41 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। फिलहाल इस योजना के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक राशि का भुगतान रुका हुआ है। पुराने आंकड़ों को देखते हुए 2024-25 में राज्य में इस योजना के लिए कम से कम 17,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी।

● **लोकेश शर्मा**

अब मिशन बना सी-टर्न

जानकारों का कहना है कि योजना के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य था कि इससे ग्रामीण मतदाता थोकबंद तरीके से भाजपा को वोट देंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को जल जीवन मिशन योजना का कोई बड़ा लाभ नहीं मिला। इसलिए जल जीवन मिशन को अब सी-टर्न यानी चुनावी टर्न मानते हुए होल्ड पर रख दिया गया है। गौरतलब है कि शुरुआत में योजना का बजट 3.60 लाख करोड़ रुपए था। इसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 2.08 लाख करोड़ और राज्य की 1.52 लाख करोड़ रुपए रही। मिशन के आगे बढ़ने के साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा न होने के कारण लागत बढ़ती गई। संशोधित बजट बढ़कर 8.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह अनुमान के दोगुने से ज्यादा है। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 4.33 लाख करोड़ और राज्यों की 4.00 लाख करोड़ रुपए है। शुरुआत में ऐसे इलाके थे जहां भू-जल था, तो बजट की जरूरत कम थी। बाकी इलाकों में काम चुनौतीपूर्ण है, इसलिए बजट की ज्यादा जरूरत है। फंड की कमी से काम धीमा हो गया है। एजेंसियों को मटेरियल और कामगारों की सप्लाई बनाए रखने में दिक्कत आने लगी है। कोरोना में दो साल काम नहीं, पाइप की सप्लाई में भी देरी कोविड के चलते दो वर्ष काम नहीं हो सका। प्रोजेक्ट में लगने वाले डक्टाइल आयरन पाइप की भी कमी रही। इस पाइप को बनाने वाले भी सीमित हैं। पाइप की मांग अचानक बढ़ने से सप्लाई में देरी हुई है।

कहां अटक गई तबादला सूची

मप्र में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार मंत्रालय से लेकर जिलों तक बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि तबादले की सूची तैयार है, लेकिन यह कहां अटकी है, यह किसी को नहीं पता। गौरतलब है कि कई जिलों के कलेक्टर्स को बदला जाएगा। इसमें जिलों में अधिकारियों के परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। बता दें, सरकार मप्र का विजन डॉक्यूमेंट बना रही है। इसको सरकार ने आठ क्षेत्रों में बांटा है। इसके लिए सभी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। अब उनके परफॉर्मेंस को देखकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

दरअसल, प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम चल रहा था। इसके चलते कलेक्टरों को नहीं बदला जा रहा था। अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। प्रदेश में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी देने के लिए अब तक के उनके काम को देखा जाएगा। इसमें राजस्व महाभियान में अब तक का काम, सीएम मॉनिट और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निपटारे समेत उनके अन्य कामों को देखा जाएगा। इसमें खासतौर से उन शिकायतों को देखा जाएगा, जहां पर शिकायतों को बिना वैधानिक प्रक्रिया के संख्या कम करने के लिए बंद कर दिया गया और अब वहां से दोबारा शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसमें मंत्रालय में विभाग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर, उप सचिव से लेकर विभाग प्रमुख और संभाग और जिलों में पदस्थ अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे। वहीं, तीन साल से अधिक समय से जमे अधिकारियों को भी हटाया जाएगा।

शिकायत वाले अधिकारी भी हटेंगे

खाद वितरण व्यवस्था को बेहतर तरीके से वितरण व्यवस्था नहीं बनाने वाले अधिकारियों पर भी संकट हैं। वहीं, इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की तरफ से जिन अधिकारियों की सरकार को शिकायत मिली उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई जिलों में खाद्य एवं औषधि विभाग में सुरक्षा अधिकारी और औषधि निरीक्षक लंबे समय से फील्ड में काम कर रहे हैं। इनमें कुछ अधिकारियों को पांच से सात साल का समय हो गया है। उनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नापतौल, पंजीयन, उद्यानिकी, खनिज, पुलिस, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में भी लंबे समय से जमे अधिकारियों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

त्रिपाठी बने अतिरिक्त सचिव

केंद्र सरकार ने मप्र कैडर के दो आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। आईएएस आकाश त्रिपाठी को केंद्र सरकार ने ऊर्जा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी बनाया है, वहीं प्रमुख सचिव स्तर के अन्य आईएएस फैज अहमद किदवई को भी नई जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा माना जा रहा था कि

आकाश त्रिपाठी इसी महीने मप्र वापस लौट सकते हैं। मोहन यादव सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आकाश त्रिपाठी को मप्र वापस भेजने का आग्रह किया था। प्रमुख सचिव स्तर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी आकाश त्रिपाठी मप्र में इंदौर कलेक्टर रहने के साथ कई विभागों में उपसचिव और सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आकाश त्रिपाठी को अक्टूबर 2022 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मंत्रालय में माय जीओवी के सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसके अलावा मप्र कैडर के प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अफसर फैज अहमद किदवई को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में एडिशनल सेक्रेट्री का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले वे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेट्री थे। अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव बनने के बाद भारत सरकार में 3 वर्ष रहने के बाद सचिव के लिए इम्पेनलमेंट हो जाता है। त्रिपाठी को 2 वर्ष 3 महीने हुए हैं। इसलिए इन्हें सचिव बनने के लिए अभी और इंतजार करना होगा।

नेहा को मिलेगी जिले की कमान

जानकारी के अनुसार सरकार मैदानी अधिकारियों के बीच बड़ा फेरबदल करने जा रही है। जिसमें दो दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। वहीं सरकार ने इस बार तेजतर्रार एवं साफ छवि के अधिकारियों को मैदानी पदस्थापना करने का निर्णय लिया है। ढीले और खराब छवि के अधिकारियों को मंत्रालय वापस बुलाया जा सकता है। इस कड़ी में 2011 बैच की आईएएस अधिकारी नेहा मारव्या को कलेक्टरी मिल सकती है। प्रशासनिक मुखिया अनुराग जैन के कार्यकाल में मैदानी अधिकारियों की यह पहली बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होगी। अभी तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की वजह से जिलाधीश समेत अन्य जिला अधिकारियों के तबादलों पर चुनाव आयोग की रोक थी। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार, कलेक्टरों के तबादलों में 2014 एवं 2015 बैच को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। साथ ही 2016 बैच के अधिकारियों को भी जिलाधीश बनाया जा सकता है। ऐसे में 2009 एवं 2010 बैच के

अधिकारियों को मैदानी पदस्थापना से हटाया जा सकता है। साथ ही 2011, 2012 एवं 2013 बैच के कुछ अधिकारियों के जिले बदले जा सकते हैं। 2013 एवं 2014 बैच के ज्यादा अधिकारियों को दूसरे जिलों की कमान सौंपी जाएगी। कुछ अधिकारी व्यक्तिगत कारणों से भी जिलों से हटना चाहते हैं। इन्होंने बकायदा शासन से गुहार लगाई है। प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि मैदानी प्रशासनिक जमावट को लेकर मुख्य सचिव तैयारी कर चुके हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ अंतिम बैठक होना शेष है। इसके बाद मैदानी अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त एवं अन्य मैदानी अधिकारी भी बदले जाएंगे।

इनको बदले जाने की संभावना

सरकार की इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी में जिन कलेक्टरों को बदलने की संभावना है उनमें 2009 बैच के अकेले अधिकारी गुना के कलेक्टर डॉ. सतेंद्र सिंह सचिव के पद पर पदोन्नति हो चुके हैं। उनका हटना लगभग तय है। 2010 बैच के कौशलेंद्र सिंह भोपाल, आशीष सिंह इंदौर, दीपक सक्सेना जबलपुर, शीलेंद्र सिंह छिंदवाड़ा, कर्मवीर शर्मा खरगोन, संदीप माकिन दतिया और सुरेश कुमार को पन्ना से हटाया जा सकता है। वहीं, 2011 बैच तीन अधिकारी ग्वालियर-चंबल के शिवपुरी, भिंड और ग्वालियर में पदस्थ हैं। इनमें से शिवपुरी के रवींद्र चौधरी और भिंड के संजीव श्रीवास्तव प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह 2012 बैच के अधिकारियों में प्रवीण अढ़ायच सीहोर, अनुराग वर्मा सतना, प्रतिभा पाल रीवा, राहुल फटिंग हरिदास बड़वानी, अवधेश शर्मा टीकमगढ़, सुभाष द्विवेदी अशोकनगर, धर्णेंद्र जैन उमरिया, अरविंद दुबे रायसेन, नरेंद्र सूर्यवंशी बैतूल और राजेश बाथम रतलाम प्रभावित हो सकते हैं। इसी बैच के उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह को इंदौर या भोपाल की कमान मिल सकती है। वहीं, 2013 बैच के जिलाधीशों में प्रियंक मिश्रा धार, सोनिया मीणा नर्मदापुरम, अनूप भारतीय खंडवा, राघवेंद्र सिंह आगर-मालवा प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह 2014 बैच की शीतला पटले नरसिंहपुर, ऋषभ गुप्ता देवास, अंकित अष्ठाना मुरैना, भव्या मित्तल बुरहानपुर, रानी बातड़ मैहर, चंद्रशेखर सिंगरौली, अभय बेडेकर अलीराजपुर और सुधीर कोचर दमोह भी बदले जा सकते हैं।

● राजेंद्र आगाल

अग्रवाल और राव का सचिव के लिए होगा इम्पेनलमेंट

मप्र कैडर के विवेक अग्रवाल और हरिरंजन राव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में हैं। अब इनका सचिव के लिए इम्पेनलमेंट हो जाएगा। वहीं तन्वी सुद्रियाल ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए आवेदन किया है। गौरतलब है कि मप्र कैडर के आईएएस अफसरों का दिल्ली में लगातार दबदबा बढ़ रहा है। इस समय प्रदेश के तीन दर्जन से अधिक अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इनमें से अधिकांश केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि समय-समय पर मप्र कैडर के आईएएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती रही है। वर्तमान में मंत्रालय से लेकर पीएमओ तक ये महत्वपूर्ण काम संभाले हुए हैं। ऐसी ही स्थिति आईपीएस अफसरों की भी है। मप्र कैडर के आईपीएस अधिकारी वर्तमान समय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जानकारों का कहना है कि मप्र कैडर के आईएएस अफसरों की गिनती कर्तव्यनिष्ठ अफसरों में होती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मप्र संवर्ग के तीन दर्जन से अधिक अधिकारी इन दिनों केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। इन्हें भारत सरकार ने राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सचिव, उपसचिव और संयुक्त सचिव जैसे पदों के अलावा विश्व बैंक, पोर्ट, मसूरी स्थित प्रशासनिक अकादमी और अंतरिक्ष विभाग तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल हैं। जिन अधिकारियों को केंद्र में प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, उनमें निकुंज श्रीवास्तव का नाम सबसे ऊपर माना जाता है। 1998 बैच के आईएएस निकुंज श्रीवास्तव विगत वर्ष जुलाई माह से वाशिंगटन डीसी यूएसए में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसी प्रकार विजय कुमार जे, अंतरिक्ष विभाग, बैंगलुरू में उप सचिव हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर मप्र संवर्ग के हरिरंजन राव और उप सचिव पद पर चंद्रमोहन ठाकुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार आशीष श्रीवास्तव, केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार और डॉ. पवन शर्मा रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। गणेश शंकर मिश्रा और शणमुगा प्रिया मिश्रा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में उप निदेशक हैं। डॉ. पल्लवी जैन गोविल, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में महानिदेशक, आशीष भार्गव, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी में महानिदेशक, ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, सांता क्रूज विशिष्ट निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र मुंबई में विकास आयुक्त हैं। इसी प्रकार जेपी आईरिन सिंथिया, कामाराजार पोर्ट लिमिटेड में प्रबंध निदेशक, विकास नरवाल कोचीन पोर्ट ट्रस्ट केरला के एवं एस विश्वनाथन चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं।

कर्मवीर शर्मा खेल रहे लंबी पारी

हर आईएएस का सबसे पहला सपना होता है कि वह कलेक्टर बने। लेकिन विडंबना यह है कि मप्र में कई आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो कलेक्टर बने बिना ही रिटायर हो गए हैं। यही नहीं कई कलेक्टर बनने की आस लगाए हुए हैं। लेकिन एक आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो लगातार कलेक्टर बन रहे हैं। यह अधिकारी हैं 2010 बैच के कर्मवीर शर्मा। शर्मा वर्तमान में खरगोन जिले के कलेक्टर हैं। बता दें कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा इसके पहले जबलपुर, पन्ना, राजगढ़ कलेक्टर भी रह चुके हैं। एक तरफ जहां सरकार कुछ ही महीनों में कलेक्टरों को चलता कर देती है, वहीं दूसरी तरफ स्थिति यह है कि कर्मवीर शर्मा अंगद के पांव की तरह अपनी कलेक्टरी की पदस्थापना पर जमे रहते हैं। गौरतलब है कि जबलपुर में रहते हुए अपने एक फैसले को लेकर काफी सुर्खियों में आए थे। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में जबलपुर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में देरी के चलते उन्होंने कुछ कर्मचारियों के साथ अपना स्वयं का भी एक माह का वेतन रोकने का आदेश दिया था। जिला कोषाध्यक्ष को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने आदेश में शिकायतों को 100 दिनों से भी अधिक समय तक लंबित रखने पर अधिकारियों का एक माह का वेतन रोकने को कहा गया था। इसी आदेश को लेकर वह काफी चर्चा में रहे।

पन्ना में हीरे का अवैध खनन जोरों पर

भारत का वो शहर, जहां के अधिकतर लोगों के दिमाग में हर वक्त हीरा ही चलता रहता है। यहां के लोग पूरे परिवार समेत एक ही लक्ष्य रखते हैं और वो है हीरा। उन्हें एक ही आस है कि हीरा मिल जाए। जी हां, इस शहर की मिट्टी ही ऐसी है, जहां पत्थर की तरह हीरे मिलते हैं। यहां अभी तक कई लोगों की किस्मत खुल चुकी है और कई मजदूर सिर्फ एक दिन में ही करोड़पति बन गए। यहां इतनी ज्यादा संख्या में हीरे निकलते हैं कि सरकार समय-समय पर इनकी नीलामी करवाती है और देश-विदेश के व्यापारी इन्हें खरीदने के लिए आते हैं। ये शहर है मप्र का पन्ना।

हीरे की धरती पन्ना में हीरे का अवैध खनन जोरों पर है। पन्ना शहर के आसपास सरकोहा, जनकपुर, राधापुर, कृष्णा, कल्याणपुर, किटहा और रामखिरिया जैसे कई गांव हैं, जहां खेतों में खेती नहीं, खनन हो रहा है। एक अदद हीरा पाने की तलाश में किसानों ने उपजाऊ जमीन को पाताल तक खोद डाला है। किसान खेतों के अलग-अलग हिस्सों को ठेके पर दे रहे हैं। शर्त यही है कि हीरा मिलने पर उसकी कीमत की 30 से 35 फीसदी रकम जमीन मालिक को देनी होगी। इसके एवज में किसान भरोसा देते हैं कि खदान के लिए जरूरी पट्टा लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सहमति पत्र बनवाना पड़ेगा। पन्ना हीरा कार्यालय से 255 हीरा खदान के पट्टे आवंटित किए गए हैं, जबकि यहां सैकड़ों अवैध खदानें हैं। हीरा खनन के लिए अधिकतम 20 फीट तक जमीन खोदी जा सकती है, लेकिन यहां 100-100 फीट गहरे गड्ढे किए गए हैं। पन्ना के दक्षिण-पश्चिम में 20 किमी से अधिक क्षेत्र में फैले हीरा क्षेत्र की मॉनीटरिंग के लिए दो हीरा इंस्पेक्टर हैं। इनमें से एक हीरा पारखी है, जिसे इंस्पेक्टर का प्रभार दिया गया है। तीन सिपाही हैं, जो 6 महीने में सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

पन्ना शहर से 13 किमी दूर वन क्षेत्र से सटे गांव सरकोहा में 60 एकड़ से अधिक जमीन पर 150 से अधिक हीरा खदानें हैं। जमीन मालिकों के मुताबिक, पूरे क्षेत्र में 20 फीट और इससे नीचे खुदाई में हीरा मिलता है। इसलिए खेतों के अलग-अलग हिस्सों को खदान के लिए किराए पर दिया जाता है। इसी गांव में कुछ महीने पहले स्वामीदीन पाल को 32 कैरेट का हीरा मिला था। पन्ना के आसपास गांवों में चोरी-छिपे सैकड़ों खदानें चल रही हैं। पन्ना में किंबरलाइट के पत्थरों में हीरा मिलता है। यहां दो तरह की खदानें हैं। उथली खदानों में हीरा अलग-अलग माध्यमों से मिट्टी तक पहुंचा है, जिसके खनन के लिए पट्टे जारी किए जाते हैं। दूसरी तरह की खदान गहराई में की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) की खदान संचालित हो रही है। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने से ये खदान 2021 से बंद थी। अभी खनन शुरू हुआ है। यहां पत्थरों को मशीनों से क्रश कर हीरा निकाला जाता है। इसके अलावा निजी खदानों में मुड्डा तलाशा जाता है, इसमें भी 100 फीट तक गहरी खुदाई की जाती है। हालांकि नियम है कि 20 फीट से नीचे खुदाई नहीं की जाएगी। खदान बंद करने के बाद इसको मलबे से भरा जाएगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है।

हीरा अधिकारी रवि पटेल के मुताबिक, खदानों के लिए पट्टे जारी करते हैं। मॉनीटरिंग के लिए भी व्यवस्था है, पर हीरा छोटा होने से मॉनीटरिंग में दिक्कत होती है। अभी हमारे पास दो हीरा इंस्पेक्टर हैं। खेतों में अवैध खदानों पर भी कार्रवाई की जाती है। पन्ना से अजयगढ़ मार्ग पर आरामगंज के पास रुंझ नदी निकलती है। इसके उथले किनारों पर दोनों ओर दर्जनों लोग नदी से रेत और पत्थरों को छानकर हीरा तलाशते हैं। सुबह से देर शाम तक कई परिवार यहां छलनी समेत खुदाई के अन्य औजारों के साथ जुटते हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं, जो छतरपुर समेत पन्ना से 30 किमी दूर गांवों से आते हैं। पन्ना के दक्षिण-पश्चिम में 20 किमी से अधिक क्षेत्र में फैले हीरा क्षेत्र की मॉनीटरिंग के लिए दो हीरा इंस्पेक्टर हैं। इनमें से एक हीरा पारखी है, जिसे इंस्पेक्टर का प्रभार दिया गया है। तीन सिपाही हैं, जो 6 महीने में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। पन्ना हीरा कार्यालय के मुताबिक, अभी तक यहां 46 लोगों को दस कैरेट से अधिक का हीरा मिल चुका है। साल 2024 में 3 लोगों को 32, 19 और 16 कैरेट का हीरा मिला है। हालांकि अवैध खदानों में मिलने वाले हीरे अभी भी हीरा कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। हीरा कार्यालय में हीरा जमा करने पर 11.5 प्रतिशत रॉयल्टी और 1 प्रतिशत टीडीएस काटकर नीलामी में मिली राशि हीरा लाने वाले को दी जाती है।

● **जितेंद्र तिवारी**

200 रुपए में मिलता है पट्टा

खास बात ये है कि माइंस का पट्टा सिर्फ 200 रुपए में मिलता है और लोग 200 रुपए सालभर के देते हैं और फिर हीरा खोजते हैं। कोई भी शख्स ये पट्टा ले सकता है और ये पट्टा फोटो, आधार कार्ड और दो सो रुपए की फीस जमा करवाकर मिलता है। ये एक साल के लिए मिलता है और उसके बाद फिर पट्टा लेना होता है। इसके लिए 8 गुणा 8 मीटर की एक जगह अलॉट कर दी जाती है, जहां पर खुदाई की जा सकती है। बस शर्त ये होती है कि खुदाई की मिट्टी को वहां से नहीं ले जा सकते और काम होने के बाद उसे वहां ही डालना होता है। इसमें अलग-अलग तरह की जगह मिलती है, जिसमें खुदाई की जा सकती है। यहां लोग कई सालों से हीरा निकाल रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें लाइफ में एक भी बड़ा हीरा नहीं मिला और उनका काफी पैसा बर्बाद हो गया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें अभी तक 20 से ऊपर हीरे मिल चुके हैं। कोई हीरा 50 लाख का है तो कुछ हीरे 2-3 करोड़ में भी बिक रहे हैं। यहां की बड़ी आबादी को अब हीरे का नशा है और लोगों को हर सुबह आस रहती है कि आज कुछ हाथ लग सकता है। मगर अक्सर ये कहानी रोज की रहती है और वे निराश होकर घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पन्ना या आसपास के क्षेत्र के लोग ही यहां हीरा खोज रहे हैं, इनके अलावा दूसरे राज्यों के भी कई लोग एक रात में अमीर बनने के चक्कर में यहां रोज हीरा खोज रहे हैं। बेरोजगारी और कर्ज होने की वजह से यहां हर किसी को एकदम से अमीर बनने का ये ही ऑप्शन नजर आता है। घर में हर उम्र के लोग हीरा खोज रह हैं, जबकि कुछ घरों में एक शख्स तो सिर्फ हीरा ही खोजता है।

वनाधिकार और पेसा को धार देगी भाजपा

मप्र में भाजपा एक बार फिर से आदिवासियों पर फोकस करने जा रही है। प्रदेश के इस बड़े वोट को साधने के लिए भाजपा और प्रदेश सरकार वनाधिकार और पेसा कानून को धार देने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि भाजपा की नजरें विधानसभा की उन 82 सीटों पर हैं, जो अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 230 सीटों की विधानसभा में अनुसूचित जाति (अजा) की 35 और अनुसूचित जनजाति (अजजा) वर्ग के लिए 47 आरक्षित हैं। यह वर्ग थोकबंद वोट देता है। इसलिए भाजपा इस वर्ग को साधने की लगातार कोशिश करना चाहती है।

अपनी रणनीति के तहत भाजपा अब पेसा अधिनियम 1996 के प्रभावी क्रियान्वयन पर फोकस करेगी। इसका मकसद अनुसूचित जनजाति वर्ग में पार्टी की पैठ मजबूत करना है। मप्र में एक कारण यह भी है कि यहां अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों से विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसके अपेक्षित मत नहीं मिल सके थे, ऐसे में वह पेसा के माध्यम से अनुसूचित जनजातीय वर्ग को लुभाकर उनकी नाराजगी को दूर करना चाहती है। दरअसल, भाजपा की नजर मप्र विधानसभा की उन 47 सीटों पर है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 230 सीटों की विधानसभा में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले 31 सीटें थीं, लेकिन अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के मुंह मोड़ने से पार्टी के हाथ से सत्ता फिसल गई। वर्ष 2023 के चुनाव में भी भाजपा के साथ एसटी वर्ग वापस नहीं आया है। पेसा एक्ट में जनजातीय वर्ग को अपने स्थानीय स्वशासन से जोड़कर रखने और उसे सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों की ग्रामसभा को शक्तिशाली बनाकर उनमें आदिवासियों के पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार प्रशासनिक ढांचा विकसित किया गया है।

मप्र में सत्ता की चाबी आदिवासी मतदाताओं के हाथों में है, यह अतिश्योक्ति नहीं, बल्कि पिछले कई चुनावों के परिणामों का विश्लेषण बताता है। यही एक वजह है कि भाजपा ने पेसा पर अपना फोकस बढ़ाया है। पिछले चुनाव परिणामों को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था तो पार्टी 29 सीटों पर चुनाव जीती थी। वहीं, 2013 में भी आदिवासियों ने भाजपा का साथ दिया और दो सीट की वृद्धि के साथ 31 सीटों पर पहुंच गई, एक अन्य निर्दलीय भी भाजपा समर्थक ही था, लेकिन 2018 में आदिवासी सीटों ने ही मप्र की राजनीति की तस्वीर बदल दी थी, तब कांग्रेस ने 30 सीटें जीतकर मप्र में सरकार बनाई थी और भाजपा का आंकड़ा गिरकर 16 पर पहुंच गया था। वर्ष 2023 के चुनाव में विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षित 47 सीटों में भी भाजपा 24 सीट ही जीत पाई जबकि कांग्रेस को 22 और एक पर अन्य को विजय मिली है। यही वजह है कि आदिवासी वर्ग ने भाजपा की चिंता बढ़ाई हुई है। दूसरी वजह झारखंड के चुनाव परिणाम हैं, जहां आदिवासियों ने भाजपा को निराश किया। ये ऐसे कारण हैं कि भाजपा अब पेसा के बहाने ही अपनी पैठ मजबूत करना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पेसा कानून में प्रस्तुत समस्त दावों का निराकरण समय-सीमा निर्धारित कर प्राथमिकता पर किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने पेसा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग में पेसा सेल गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं में समस्त पात्र भाई-बहनों का शत-प्रतिशत सेचुरेशन सुनिश्चित किया जाए।

प्रदेश में वनभूमि पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) और पेसा नियमों के प्रभावी और टाइम बाउंड क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने दो माह पहले टास्कफोर्स गठित कर दी है। यह टास्क फोर्स मप्र की वन भूमि पर समुदाय के सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लंबित मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी सिफारिशें करेगा। इस टास्क फोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति बनाई गई है। दोनों ही समितियों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बनाया गया है। शीर्ष समिति में जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वन मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव अनुराग जैन को पदेन सदस्य सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य विभाग को पदेन सह सदस्य सचिव बनाया है। कार्यकारी समिति में सीएस, एसीएस पंचायत व ग्रामीण विकास, वन, जनजातीय कार्य विभाग व टीआरआई के अपर आयुक्त को पदेन सदस्य बनाया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

19 जिलों में खुलेंगे जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार

केंद्र सरकार के धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में मप्र के 51 जिलों के 11,377 जनजातीय बहुल गांव चिह्नित हुए हैं। इन गांवों का हर स्तर से विकास किया जाएगा। प्रदेश के 51 जिलों में 43 जनजातीय समुदायों के 18 लाख 58 हजार परिवार रहते हैं। इस अभियान का फायदा इन परिवारों के करीब 93 लाख 23 हजार लोगों को मिलेगा। जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देशभर में 100 ट्राइबल मल्टी पर्पज मार्केटिंग सेंटर्स (टीएमएमसी) तैयार करने की योजना है। इसे जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार भी कहा जा सकता है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को पहले आएं-पहले पाएं की तर्ज पर जो भी राज्य पहले अपने प्रस्ताव भेजेंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर टीएमएमसी आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए मप्र सरकार ने वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 19 जिलों में एक-एक टीएमएमसी बनाने का प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव को भेजा गया है। इसके अनुसार 2000 वर्ग मीटर में बनने वाले हर टीएमएमसी पर करीब एक करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टीएमएमसी को राज्य सरकार के जनजातीय कार्य विभाग संचालित करेंगे। इन्हें बनाने का बजट केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय देगा।

बिजली फिर मारेगी करंट

बिजली कंपनी दरें बढ़ाकर घरेलू उपभोक्ताओं पर बोझ डालना चाह रही है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 151-300 के बीच का स्लैब खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट वसूलने का प्रस्ताव मप्र विद्युत नियामक आयोग को दिया है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान मध्यवर्ग के उन उपभोक्ताओं को होगा जो सब्सिडी के दायरे से बाहर आते हैं। प्रदेश में ऐसे करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिन पर 50 पैसे प्रति यूनिट का बोझ डालने की तैयारी हो रही है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने इस संबंध में याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग में दी है। इस पर सुनवाई से पूर्व आयोग ने जनता से 24 जनवरी तक आपत्ति बुलाई है।

बता दें कि मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता 58744 करोड़ व वर्तमान दरों पर प्राप्त राजस्व 54637 करोड़ बताया है। कंपनी ने इस अंतर की राशि 4107 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए औसत 7.52 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में कंपनी ने घरेलू उपभोक्ता की बिजली खपत की चार श्रेणी को तीन में समेट दिया है। पहली श्रेणी 50 यूनिट, दूसरी श्रेणी 51 से 150 यूनिट और तीसरी श्रेणी 151 से ऊपर की रखी गई है। अभी 151 से 300 यूनिट की श्रेणी के लिए अलग दर तय थी। अब कंपनी 151 यूनिट के ऊपर एक दर तय करना चाह रही है। इससे 50 पैसे का बोझ प्रति यूनिट उपभोक्ता पर डालने का प्रस्ताव है। प्रदेश में अभी 1 करोड़ 27 लाख कुल घरेलू उपभोक्ता हैं। इसमें बिजली कंपनी करीब एक करोड़ उपभोक्ता को सब्सिडी देती है। ये उपभोक्ता 150 यूनिट मासिक खपत के दायरे में आते हैं। कंपनी 100 यूनिट के लिए 100 रुपए और अगली 50 यूनिट पर सामान्य दर से बिलिंग करती है, इससे उपभोक्ता को करीब 450 रुपए से अधिक की बचत होती है। इस बीच 25 लाख से ज्यादा ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिनकी मासिक खपत 151 से 300 यूनिट के भीतर रहती है। ऐसे उपभोक्ताओं को भी अब फ्लैट रेट पर बिल भरना होगा।

बिजली मामलों के जानकार एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि टैरिफ में बदलाव करने से मध्यम वर्ग के उपभोक्ता जिनकी मासिक खपत 151 यूनिट से 300 यूनिट के बीच है उन पर अधिक बोझ डाला जा रहा है। ये वर्ग सरकारी सब्सिडी के दायरे से बाहर होता है, इसलिए उन्हें बिजली की पूरी कीमत देनी पड़ती है। मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी के सीजीएम शैलेंद्र सक्सेना ने बताया कि कंपनी 151 से 300 यूनिट के स्लैब को खत्म कर एक दर तय करना चाहती है। ऐसी श्रेणी के उपभोक्ता से एक सामान्य दर से बिजली बिल लिया जाएगा।

कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव में घरेलू, कृषि, चार्जिंग स्टेशन, रेलवे, कोयला खदान, औद्योगिक, शॉपिंग मॉल से लेकर मेट्रो, सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र, सिंचाई व अन्य तमाम कार्यों के लिए ली जाने वाली बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं से ही दर वृद्धि के बाद 988 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय बिजली कंपनियों को होगी, तो गैर घरेलू से 218 करोड़ रुपए और सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्रों और स्ट्रीट लाइट से 104 करोड़, निम्न दाब उद्योगों से 62, कृषि संबंधित गतिविधियों से डेढ़ हजार करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होना है। इसी तरह कोयला खदानें, शॉपिंग मॉल और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं से बढ़ी हुई दरें वसूलकर 4107 करोड़ रुपए अतिरिक्त हासिल किए जाएंगे। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को अभी 151-300 यूनिट के मौजूदा टेरिफ स्लैब का लाभ मिलता है। उसे अब संशोधित कर 150 यूनिट तक ही सीमित किया जाएगा। यानी इससे अधिक बिजली जलाने वाले छोटे उपभोक्ताओं को भी बिजली की कीमत अधिक चुकानी पड़ेगी।

फिलहाल झुग्गी झोपड़ी समूह के लिए डीटीआर मीटर के माध्यम से जो टैरिफ अभी है उसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक कि घोषित और अघोषित अवैध कॉलोनियों में विद्युतीकरण के साथ सभी उपभोक्ताओं का मीटरीकरण नहीं हो जाता। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए सुबह 9 से 5 बजे ऑफ पीक अवधि के दौरान खपत की गई ऊर्जा के लिए सामान्य दर पर 20 फीसदी की टीओडी छूट प्रस्तावित की गई है। इसी तरह रात 10 से सुबह 6 बजे के दौरान टैरिफ की सामान्य दरों पर ही भुगतान करना पड़ेगा। हरित ऊर्जा शुल्क भी वर्ष 2025-26 के लिए दो तरह से प्रस्तावित किया गया है। पहला कार्बन चिन्ह को कम करने और दूसरा ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से बिजली हासिल करने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी में लिया जाएगा। वहीं एचवी-3 टैरिफ के तहत उच्च दाब उपभोक्ताओं को वर्तमान में लागू सभी छूट आगामी वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। इन याचिकाओं के खिलाफ 24 जनवरी तक आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। वहीं मप्र पावर मैनेजमेंट कंपनी ने लगातार घाटा होने का हवाला देते हुए बिजली की दर में वृद्धि का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है।

● **अरविंद नारद**

हर साल महंगी हो रही बिजली

बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 में बिजली का टैरिफ बढ़ाए जाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग में याचिका दायर की थी। इस याचिका में बिजली कंपनियों ने 1537 करोड़ का घाटा बताया था। इस घाटे की भरपाई के लिए बिजली कंपनियों ने आयोग से 3.20 फीसदी टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। उधर, विद्युत विनियामक आयोग ने जब बिजली कंपनियों के घाटे की जांच की, तो यह घाटा 795 करोड़ रह गया था, तब आयोग ने 1.65 फीसदी टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी थी। इसी तरह से इसके पहले वर्ष 2022-23 में बिजली कंपनियों ने 3916 करोड़ का घाटा बताया था। इस घाटे की पूर्ति के लिए बिजली कंपनियों ने आयोग से 8.71 फीसदी बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मांग की थी। तब आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं की जांच की। आयोग ने जांच के बाद साफ लिखा कि गहन जांच के बाद 1181 करोड़ का घाटा आ रहा है। यानी आयोग की जांच के बाद बिजली कंपनियों का घाटा आधे से भी कम रह गया था। तब आयोग ने बिजली के टैरिफ में 2.64 फीसदी का इजाफा किया था।

भर्ती परीक्षाओं की बढ़ेगी फीस

वन टाइम फीस का आदेश अधर में

मप्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से पहले अप्रैल 2023 में युवाओं को राहत देते हुए सरकारी भर्तियों के लिए अलग-अलग परीक्षाओं में अलग-अलग शुल्क देने से छूट दी थी। सरकारी नौकरी के लिए कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली सभी परीक्षाओं में उम्मीदवार से एक बार ही परीक्षा शुल्क लिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत अभ्यर्थी को नामांकन के लिए एक बार प्रोफाइल का रजिस्ट्रेशन करना होता था। उसके बाद पहली परीक्षा में आवेदन भरने के समय उसके लिए निर्धारित परीक्षा और पोर्टल शुल्क देना होता था। इसके बाद किसी अन्य परीक्षा में आवेदन करते समय उन्हें परीक्षा शुल्क नहीं देना होता था। इस आदेश में एक पॉइंट यह था कि यह एक साल के लिए प्रभावी है। इसकी मियाद 20 अप्रैल 2024 को खत्म हो गई लेकिन साल 2023 में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या साल 2022 के मुकाबले 8 लाख बढ़ गई।

मप्र सरकार नए साल में सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। इस खबर को सुनकर प्रदेश के लाखों युवा उत्साहित हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी नौकरी की चाह वाले युवाओं पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी हो रही है। यानी मप्र कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी इस साल आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। मंडल की जनवरी के तीसरे हफ्ते में होने वाली अर्द्धवार्षिक बोर्ड मीटिंग में परीक्षाओं की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा फीस में 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। खास बात ये है कि पिछले साल जुलाई में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की थी कि भर्ती परीक्षाओं में शुल्क को लेकर सरकार एक नई नीति बनाएगी। उधर, अधिकारियों का तर्क है कि साल 2012 से परीक्षा फीस नहीं बढ़ाई गई है। ईएसबी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इतनी कम फीस में परीक्षा कराकर खर्च निकालना संभव नहीं है।

कांग्रेस नेता पारस सकलेचा कहते हैं कि बेरोजगार युवाओं को 20 अलग-अलग परीक्षाओं के लिए 20 बार फीस देनी पड़ती है। कर्मचारी चयन मंडल व्यापारी की तरह दुकान चला रहा है। दिसंबर 2022 तक कर्मचारी चयन मंडल के पास 798 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था। वो भी तब जब परीक्षाओं के आयोजन के लिए उसने निजी एजेंसियों को पैसा दिया। जनवरी 2023 से 15 जून 2023 के साढ़े 5 महीने में कर्मचारी चयन बोर्ड ने 6 परीक्षाओं का आयोजन किया। इनमें 32.60 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा फीस के 107 करोड़ रुपए दिए। सकलेचा के मुताबिक, इस समय कर्मचारी चयन मंडल के पास 340 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट है। उनके बार-बार पूछने के बाद भी सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि ईएसबी इन अतिरिक्त रुपयों का क्या कर रही है? वहीं, जानकारों का कहना है कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले मप्र में परीक्षा फीस सबसे ज्यादा है। कर्मचारी चयन मंडल हर परीक्षा के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्रों से 500 रुपए तो रिजर्व कैटेगरी के छात्रों से 250 रुपए एग्जाम फीस लेता है। जनवरी में होने वाली बोर्ड मीटिंग में मौजूदा फीस को 10 से 20 फीसदी तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यदि 10 फीसदी फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर सहमति बनती है तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए फीस 550 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 275 रुपए होगी। इसी तरह 20 फीसदी फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को सहमति मिलने पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 600 रुपए तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 300 रुपए प्रति एग्जाम फीस चुकानी होगी। पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान, उप्र और छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं के मुकाबले मप्र में एग्जाम फीस पहले से महंगी है। नए प्रस्ताव के बाद ये और बढ़ जाएगी।

ईएसबी के पास 340 करोड़ रुपए सरप्लस पड़े हुए हैं। इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये किसी को नहीं पता। मंडल की अर्द्धवार्षिक बोर्ड मीटिंग में परीक्षाओं की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एग्जाम फीस में 10 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। व्यापमं पर सरकारी नौकरियों की परीक्षा आयोजित करने और एक दर्जन से ज्यादा परीक्षाओं में घोटाले, गड़बड़ी तथा अपात्र युवाओं का चयन करने के आरोप लग चुके हैं। इन आरोपों के चलते सरकार ने इसका तीसरी बार नाम बदलकर मप्र कर्मचारी चयन मंडल किया है। पिछले साल जुलाई में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की थी कि भर्ती परीक्षाओं में शुल्क को लेकर सरकार एक नई नीति बनाएगी। उधर, अधिकारियों का तर्क है कि साल 2012 से परीक्षा फीस नहीं बढ़ाई गई है। ईएसबी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। इतनी कम फीस में परीक्षा कराकर खर्च निकालना संभव नहीं है। वहीं, जानकारों का कहना है कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले मप्र में एग्जाम फीस सबसे ज्यादा है। ईएसबी के पास 340 करोड़ रुपए सरप्लस पड़े हुए हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान, उप्र और छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं के मुकाबले मप्र में एग्जाम फीस पहले से महंगी है।

कर्मचारी चयन मंडल के लिए परीक्षा आयोजित करवाना मुनाफे का सौदा है। मंडल छात्रों से वसूले परीक्षा शुल्क से हर साल करोड़ों रुपए की कमाई करता है जबकि परीक्षा कराने सहित दूसरे बंदोबस्त पर खर्च 250 रुपए प्रति छात्र आता है। बाकी पैसा बचत खाते में जाता है। साल 2011-12 में मंडल (व्यापमं) ने परीक्षा शुल्क से 98.30 करोड़ रुपए की कमाई की जबकि खर्च हुए 27.89 करोड़ रुपए। हर साल कमाई की ये रकम बढ़ती ही जा रही है। 2021 में बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं से 103 करोड़ रुपए की कमाई की और खर्चा मात्र 32.16 करोड़ रुपए हुआ। यानी बोर्ड को छात्रों से मिले परीक्षा शुल्क से करीब 71 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं, साल 2022 में एग्जाम फीस से ईएसबी को 62.43 करोड़ रुपए की कमाई हुई, खर्च हुआ 49.65 करोड़ रुपए। यानी करीब 13 करोड़ रुपए का मुनाफा। 2023 में वन टाइम फीस ली गई थी। इस वजह से कमाई से ज्यादा खर्च हुआ। साल 2024 में नौ परीक्षाओं की फीस से ईएसबी ने 18.16 करोड़ रुपए की कमाई की और इन परीक्षाओं पर 15.23 करोड़ रुपए खर्च हुए।

● **विकास दुबे**

मिशन से बनेगा स्वर्णिम मप्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सपना है स्वर्णिम मप्र। स्वर्णिम मप्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जातियों-गरीब, युवा, किसान और महिला के सशक्तिकरण पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि वर्ष 2025 में स्वर्णिम मप्र की परिकल्पना साकार हो। इसके लिए मप्र सरकार ने तैयारियां शुरु कर दी हैं। सरकार चारों वर्गों के लिए अलग-अलग योजनाएं शुरु कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो परिकल्पना की है, उसे हर हाल में साकार कर मप्र को सशक्त राज्य बनाया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विकास के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को आधार बनाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष-2025 में मप्र के सर्वांगीण विकास को आकार देने के संकल्प के साथ चारों मुख्य स्तंभों के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला सशक्तिकरण मिशन को पूरा करने के लिए अलग-अलग ब्लू-प्रिंट तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन सशक्तिकरण मिशनों का जनवरी माह से शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि इन चारों स्तंभों को सशक्त बनाकर मप्र के विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा सकेगा। युवा शक्ति मिशन युवा पीढ़ी को उभरती प्रौद्योगिकियों, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में कौशल प्रदान करेगा। इससे उन्हें बदलते हुए नौकरी बाजार के लिए तैयार किया जा सकेगा, साथ ही उनमें सक्षम नेतृत्व के गुण विकसित होंगे। महिला सशक्तिकरण मिशन उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता, शैक्षिक अवसर और उद्यमिता के अवसर और प्रोत्साहन देगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगीं और प्रदेश में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। किसान कल्याण मिशन उद्देश्य विविधीकरण के साथ ही पशुपालन एवं मछली पालन जैसे सहायक व्यवसायों को एकीकृत करने और कृषि-आधारित उद्यमिता जैसे प्रगतिशील उपायों को वित्तीय सहायता और तकनीकी परामर्श देकर प्रोत्साहित कर खेती को मुनाफे का सौदा बनाने पर फोकस्ड है। गरीब कल्याण मिशन में सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को वित्तीय सहायता, भूमि संबंधी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर गरीबी के कुचक्र को तोड़ने में मदद करेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में सिर्फ चार जातियां होने की बात कहते हुए उनके विकास पर ध्यान देने की बात कही है। इसी राह पर प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार युवा, महिला, किसान व गरीबों के उत्थान और विकास के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इनके लिए सरकार मिशन मोड पर काम करेगी। एक जनवरी से युवा शक्ति, किसान, कल्याण, गरीब कल्याण और नारी सशक्तीकरण के नाम से चार मिशन प्रारंभ हो गए हैं। इनके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में अतिरिक्त राशि का प्रविधान भी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक

महिला सशक्तिकरण मिशन

महिला सशक्तिकरण मिशन राज्य में महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन का मकसद महिलाओं को पुरुषों के ही समान अवसर उपलब्ध करा प्रदेश जेंडर इक्वालिटी लाना है ताकि प्रदेश में समावेशी समाज की स्थापना हो सके। मिशन के अंतर्गत उनमें शिक्षा और कौशल विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे उनकी रोजगार प्राप्त कर पाने की क्षमता और संभावनाएं बढ़ेंगीं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होगी। मिशन महिला उद्यमिता को भी बढ़ावा देगा, उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने और उसके सुचारू संचालन के संसाधन, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी लैंगिक मुद्दों से निपटने के कार्यक्रम भी शामिल होंगे। यह मिशन महिलाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाएगा और एक सहायक वातावरण तैयार करेगा। साथ ही महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, काउंसलिंग और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण मिशन यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित हो जिससे वे स्थानीय स्तर पर कुशल नेतृत्व करते हुए मप्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

क्षेत्र में मजबूत करना है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायत, स्वसहायता समूहों को मदद और कौशल विकास की योजनाएं चलाई जाएंगी। इसके माध्यम से सरकार का लक्ष्य युवाओं को इस तरह से तैयार करना है कि वह स्वरोजगार की दिशा में जा सकें। रोजगार और कौशल विकास पर भी जोर रहेगा। प्रदेश के युवा को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। खेल और स्टार्टअप पर विशेष जोर रहेगा। तकनीकी शिक्षा को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश के गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान रहेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित होंगे। गरीबों को छोटे व्यवसाय के लिए कर्ज की विशेष सुविधा दी जा सकती है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं प्रारंभ की जा सकती हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास होंगे। अधिक दाम देने वाली फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रदेश में सिंचित क्षेत्र अभी 50 लाख हेक्टेयर है जिसे पांच वर्ष में एक करोड़ हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। दूध उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास होंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि युवा शक्ति मिशन युवाओं के सशक्तिकरण की मजबूत बुनियाद सिद्ध होगा। मिशन से युवा में शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक सेवा की भावनाएं विकसित होंगी। साथ ही वह आधुनिक तकनीक के कुशल प्रयोग में सक्षम बनेगा। परिणामस्वरूप युवाओं में सफल व सक्षम नेतृत्व के गुण भी विकसित होंगे। युवा शक्ति मिशन के सफल क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौशल विकास के पाठ्यक्रम युवाओं को सहजता से उपलब्ध हो सकें और वह उन्हें आसानी से समझ सकें, इसके लिए सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। इसका लाभ यह भी है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को इसकी सुविधाएं समान रूप से सुलभ होंगी। मिशन की सफलता के लिए सरकार ने सोशल-मीडिया के माध्यमों का भी

प्रभावी उपयोग करने की रणनीति बनाई गई है, जिससे युवाओं को मिशन से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराई जा सके। इससे युवाओं में मिशन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसी तरह से युवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार ने सभी 55 जिलों में प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस कॉलेज स्थापित किए हैं, जिनमें छात्रों के लिए आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न संभागों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने और औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आज की तारीख में मप्र सरकार 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने और तीन लाख अन्य के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के मिशन पर काम कर रही है। कुल मिलाकर मप्र श की मौजूदा सरकार राज्य के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजनाओं से लेकर शैक्षिक सुधारों और महिला सशक्तिकरण तक, सरकार ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समृद्धि और अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई तरह की पहल की हैं, जिसका अंतरिम लक्ष्य समाज के वंचित और पीड़ित वर्ग की जनता का कल्याण है।

गरीब कल्याण मिशन, मप्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली एक अभिनव पहल है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक सेवाएं उन तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह मिशन समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को सशक्त बनाने की महत्वपूर्ण रणनीति का हिस्सा है। मिशन का मुख्य उद्देश्य गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है, ताकि वंचित वर्ग को कठिन समय में आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, मिशन इस वर्ग को रोजगार से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सक्षम योजनाओं का लाभ दिलाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े, जरूरतमंदों को मिशन में वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करेगा। बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास तक पहुंच में सुधार किया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो सकें। गरीब कल्याण मिशन का उद्देश्य वंचित वर्ग को आर्थिक रूप से समुन्नत बनाकर मप्र में आर्थिक विषमता दूर करना है, जिससे गरीब वर्ग भी प्रदेश के विकास में समान रूप से योगदान दे सकें।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

किसान कल्याण मिशन

किसान कल्याण मिशन का उद्देश्य कृषि को उन्नत कर खेती को मुनाफे का सौदा बनाना है, जिससे किसानों का जीवन स्तर सुधरे और वे मप्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। खेती और किसान अर्थव्यवस्था की मजबूती के महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह मिशन सुनिश्चित करेगा कि किसान समृद्ध हों और कृषि क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता आए। मिशन का मुख्य उद्देश्य खेती को लाभप्रद बनाना है। इसके लिए मिशन के अंतर्गत कृषि विविधीकरण, जैविक खेती, खेती में पशुपालन, मछली-पालन जैसे व्यवसायों का एकीकरण और उन्हें बाजारोन्मुखी बनाकर उपज की बाजारों में पहुंच सुनिश्चित करने के साथ किसानों में कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। मिशन, किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों और स्थानीय मेलों का भी आयोजन करेगा, जिससे वे अपनी उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। किसानों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए मिशन के तहत उन्हें बीज, उर्वरक और उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी दी जाएगी, जिससे उनके खर्चे कम होंगे और आय में वृद्धि होगी। मिशन, किसान उत्पादक संगठनों की स्थापना को बढ़ावा देकर किसानों में सहकारिता को प्रोत्साहित करेगा ताकि कृषि क्षेत्र संगठित स्वरूप लेकर आगे बढ़ सके। साथ ही मिशन में किसानों को कृषि तकनीकों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा।

मप्र में नासूर न बन जाएं नक्सली!

बालाघाट जिले में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान नक्सली अपना सामान छोड़कर भाग निकले। हॉक फोर्स ने मौके से नक्सलियों का राशन और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया है। वहीं अब क्षेत्र में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। बता दें कि सूलसूली पुलिस चौकी क्षेत्र के माताघाट और धारमारा के जंगलों में हॉक फोर्स और नक्सलियों का आमना-सामना हुआ। दरअसल, हॉक फोर्स की टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। तभी जवानों और नक्सलियों की ओर से एक्सचेंज ऑफ फायर किया गया। हालांकि, नक्सली भागने में सफल रहे। बताया जा रहा है कि 10 से 12 की संख्या में सशस्त्र नक्सली थे। वहीं इस वारदात के बाद पेट्रोलिंग की कार्रवाई जारी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ और मप्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

दरअसल, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर लगातार हो रहे प्रहार से उनकी कमर टूटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब कार्रवाई से बचने के लिए नक्सली मप्र के जंगलों में अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। नक्सलियों के नए ठिकानों को लेकर आईबी की गोपनीय रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सलियों के मूवमेंट को लेकर मप्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 2 बटालियन की मांग की है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार नक्सली मप्र के बालाघाट, डिंडौरी, मंडला में नक्सलियों का नया कैडर तैयार किया जा रहा है। 20 से 25 नक्सलियों का मूवमेंट सीधी-सिंगरौली से लगे माड़ा जंगल और मंडला के कान्हा नेशनल पार्क के कोर एरिया में देखा जा रहा है। आईबी के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। आईबी की रिपोर्ट में बताया गया है कि आसपास के ग्रामीणों ने कुछ संदिग्धों को देखा है। गांव वालों का कहना है ये नए चेहरे हैं इन्हें पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद माओवादियों की कमर टूट गई। लगातार चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है। कई नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब नक्सली बड़ी संख्या में मप्र को अपने छिपने का ठिकाना बना रहे हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिलने के बाद मप्र सरकार सतर्क हो गई है। दरअसल, जब भी नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की मुठभेड़ होती है वे अपने लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं। नक्सली छत्तीसगढ़ में होने वाली कार्रवाईयों के बाद सेफ जोन के तौर पर मप्र के इन इलाकों का इस्तेमाल करते हैं। नक्सलियों ने साल 2015-16 में महाराष्ट्र, मप्र और छत्तीसगढ़ (एमएमसी) क्षेत्र बनाया था।

तीन राज्यों का सीमावर्ती इलाका होने से बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर और सिंगरौली जिले नक्सलियों के लिए न केवल बड़ा गलियारा बने, बल्कि इनका घना जंगल नक्सलियों के लिए मुफीद भी साबित हुआ है। हालांकि बालाघाट के अलावा इन जिलों में कभी कोई बड़ी नक्सली वारदात सामने नहीं आई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बालाघाट में नक्सलियों ने अलग-अलग स्थानों में वारदात कर 29 सालों में 87 लोगों को मौत के घाट उतारा है। वहीं पुलिस मुठभेड़ में अब तक 17 नक्सली मारे गए हैं, जबकि 170 गिरफ्तार हुए हैं। पिछले 10 साल में यहां नक्सली गतिविधियां कम जरूर हुईं, लेकिन थमी नहीं। 2013 के बाद नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी ने एक बार फिर बालाघाट पर फोकस किया और महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ व मप्र के सीमावर्ती इलाके में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एमएमसी जोन तैयार किया।

बालाघाट में नक्सली राजनांदगांव (अब छत्तीसगढ़ में) व महाराष्ट्र के भंडारा से घुसे थे। आज भी नक्सली बालाघाट आने के लिए इन्हीं सीमावर्ती इलाकों का रास्ता पकड़ते हैं। छत्तीसगढ़ में वारदात के बाद नक्सली बालाघाट के घने जंगलों और यहां की बसाहट के बीच अपने छिपने के ठिकाने तलाशते हैं। इतना ही नहीं इसके लिए वे उन क्षेत्रों का चयन करते हैं। जहां पुलिस आसानी से न पहुंच सके। सूचना और संपर्क से दूर बसे गांवों में नक्सलियों की दहशत उनके लिए सुरक्षित ठिकाना बनती है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 5 जनवरी 1990 को नक्सलियों ने जिले में पहली दस्तक दी थी। नक्सली महाराष्ट्र के सालेकसा थाना अंतर्गत अदारी गांव से जिले के सीमावर्ती गांव मुरकुटा में पहुंचे थे। आजाद उइके के नेतृत्व में नौ नक्सलियों ने जिले की सीमा में प्रवेश किया था। इसके बाद से बालाघाट में शुरू हुई नक्सली गतिविधियां थम नहीं पाई हैं।

● **बृजेश साहू**

कई बड़ी नक्सली वारदातों की योजना बनी बालाघाट में

महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ सीमा से लगे इलाकों में सक्रिय मलाजखंड दलम, तांडा दलम व गढ़चिरौली में सेंट्रल कमेटी ने नक्सलियों की संख्या बढाई है। देवरी दलम से कुछ सदस्य शामिल हुए हैं। बड़े नक्सली नाम गुहा, संपत, जमुना, पहाड़ सिंह, दीपक के दलम में शामिल होने और दलम की कमान संभालने के बाद से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ही नहीं झारखंड, ओडिशा व आंध्रप्रदेश में भी वारदात की योजना में बालाघाट कहीं न कहीं शामिल रहा। नक्सली नेता गुहा व रसूल की गिरफ्तारी के बाद मप्र, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में कमजोर पड़ी अपनी पकड़ को मजबूत करने नक्सली लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। एमसीसी (माओवादी कम्युनिस्ट कमेटी) व पीडब्ल्यूजी (पीपुल्स वार ग्रुप) अपना ढांचा मजबूत करने फिर जंगलों में बसे लोगों में नक्सली विचारधारा का बीज बोने की कवायद कर रहे हैं। वहीं मप्र के अन्य जिलों में भी दलम का विस्तार कर रहे हैं।

33 के फेर में उलझी फुल पेंशन

33 साल की सेवा का दायरा नहीं छू पा रहे कर्मचारी

अब कर्मचारियों का कहना है कि 33 साल की सेवा का दायरा हजारों साथी नहीं छू पा रहे हैं और वह रिटायर्ड हो रहे हैं। जिससे उन्हें भारी आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में वर्ष 2000 के पूर्व सेवा में आने की आयु अधिकतम 33 साल थी। उस दौरान 20 से लेकर 30 साल की आयु में ही अधिकांश लोग सेवा में आ जाया करते थे। मौजूदा समय में पुरूष वर्ग में 40 तो महिलाओं के लिए 45 साल की सीमा आयु सेवा में आने के लिए रखी गई है। इस कारण अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी 20 या 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद भी 60 साल के होकर रिटायर्ड हो रहे हैं। कर्मचारी यही तर्क रखते हुए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डीके यादव का कहना है कि अधिवार्षिकीय आयु 20 साल होना चाहिए। सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। लाखों कर्मचारी बिना फुल पेंशन लाभ लिए रिटायर्ड हो रहे हैं। इस पर सोचना होगा। प्रदेश में कर्मचारियों का कहना है कि 33 साल की सेवा का दायरा कम होने से रिटायर्डमेंट के बाद पेंशन की पूर्ण राशि नहीं मिल पा रही है। जब सेवक रिटायर्ड होता है तो मूल वेतन की 50 फीसदी राशि दी जाती है। इसमें डीए (डियरनेस एलायंस) यानि महंगाई भत्ता और डीआर (डियरनेस रिलीफ) महंगाई राहत जोड़ी जाती है। तब फिक्सेशन राशि का फुल पेंशन के रूप में भुगतान होता है। अब दिक्कत यह है कि यदि सरकार के नियम अनुसार 33 साल की सेवा पूरी नहीं होती है तो यह कर्मचारी पूर्ण पेंशन राशि से वंचित हो रहे हैं।

मप्र में सरकार ने फुल पेंशन के लिए 33 साल की सर्विस पूरी होने का प्रावधान कर रखा है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद फुल पेंशन के लिए पात्र नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे में मप्र में अधिवार्षिकीय आयु 33 वर्ष में फुल पेंशन का फार्मूला शासकीय सेवकों की सिरदर्दी बढ़ा रहा है। दरअसल, इस दायरे तक पहुंचने के पूर्व ही अधिकांश अधिकारी-कर्मचारी सेवानिवृत्ति के नजदीक आ रहे हैं। जबकि छठवें वेतनमान आयोग की अनुशंसा में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू कर चुकी है। राज्य सरकार द्वारा फुल पेंशन के लिए तय प्रावधान के मुताबिक इनकी 33 साल की सर्विस पूरी नहीं होगी, तभी पूरी पेंशन मिलेगी। इनमें से जो कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं उन्हें भी पूरी पेंशन नहीं मिल रही है। दरअसल मप्र में पूरी पेंशन पाने के लिए 33 वर्ष की अहर्तादायी सेवा जरूरी है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतनमान के साथ इस अहर्ता को घटाकर 25 वर्ष कर दिया था। इसका मतलब है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी 25 साल की सर्विस पूरी करते हैं उन्हें पूरी पेंशन मिलेगी। मप्र राज्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है जब देश में छठवां वेतन आयोग गठित हुआ था तब यह आयु 33 से घटाकर 20 साल की गई थी। केंद्र 20 साल की सेवा में फुल पेंशन दे रहा है। जबकि मप्र में कर्मचारी नुकसान उठा रहे हैं।

सरकार के इस प्रावधान के अनुसार सबसे ज्यादा नुकसान उन कर्मचारियों को हो रहा है जो किसी दूसरे विभाग में थे, उनके विभाग का दूसरे विभाग में संविलियन हो गया। इस कारण उनकी वरिष्ठता की गणना संविलियन के बाद से की गई। इस कारण 35 साल या उससे ज्यादा की नौकरी करने के बावजूद इनकी सेवा अवधि 7 साल कम हो गई। दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मचारी के बाद कर्मचारी जबसे नियमित हुए तबसे उनकी सेवा अवधि की गणना की गई। इस कारण इन्हें वरिष्ठता में 6 से 10 साल तक का नुकसान हुआ। सरकारी नौकरी करने वाले माता-पिता की मृत्यु होने के बाद जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिली, उनकी सेवा अवधि की गणना भी नियुक्ति दिनांक से ही की जा रही है। प्रदेश में वर्ष 2008 के दौरान जब छठवां वेतनमान लागू हुआ था, तब उसमें लोक सेवकों की अधिवार्षिकीय आयु को 20 वर्ष तय किया गया था। यानि कि इतने साल की सेवा करने के उपरांत कर्मचारी फुल पेंशन के लिए पात्र रहेगा। इस रिकमंडेशन के बाद केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए बीस साल का फार्मूला तय कर दिया था।

छठवें वेतनमान आयोग की अनुशंसा में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए यह व्यवस्था लागू कर चुकी है। अन्य तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश सहित अन्य राज्य भी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मप्र में सरकार ने इस गंभीर विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली सहित असम, नागालैंड, मेघालय सहित अन्य राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की सेवा पूर्ण करने पर फुल पेंशन का पात्र माना जा रहा है। जबकि मप्र में 33 साल की सेवा पूरी करने पर यह प्रासंगिक सुविधा दी जा रही है। अब राजकीय कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि काम और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनका निरंतर योगदान है तो आखिर यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तर्क दिया है कि वैसे भी प्रतिस्पर्धी इस दौर में कोई भी बेरोजगार 30 के बाद 35 या 40 साल की आयु में सेवा में आता है, 20 या 25 साल की सेवा करने के बाद उसकी रिटायर्डमेंट उम्र 60 साल हो रही है, वह सेवानिवृत्त हो जाता है। ऐसे में कैसे वह 33 साल की सेवा पूर्ण कर सकता है। फुल पेंशन का लाभ 20 साल की सेवा में पाने के लिए प्रदेश के कर्मचारी पिछले पांच साल से सरकार के समक्ष पक्ष रख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्मचारियों के संगठनों ने संवाद के दौरान यह समस्या बताई। पूर्व मुख्य सचिव के सामने भी यह समस्या रखी गई। तब उन्होंने विधि से विभाग से सलाह लेने की बात कही थी। यह अभिमत आज तक सरकार के समक्ष नहीं पहुंच पाया है। गौरतलब है कि एक तरफ कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा तय मापदंड तक नहीं पहुंच पा रहे, वहीं दूसरी तरफ पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए घातक सिद्ध हो रही है। इसलिए पुरानी पेंशन लागू की जाए।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है। 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इसको देखते हुए दिल्ली चुनाव में वादों और गारंटियों की बौछार हो रही है। अभी तक की स्थिति में दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला यानि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला दिख रहा है। लेकिन पार्टियों को अपने से अधिक अपनी घोषणाओं पर भरोसा है। इसलिए मतदाताओं को साधने के लिए पार्टियों ने तरह-तरह के प्रलोभन देना शुरु कर दिया है। देखना यह है कि किसका वादा अन्य पर हावी होता है।

वादों और गारंटियों की जंग...

विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली तैयार है। तारीखों का ऐलान हो गया है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने के लिए भाजपा और कांग्रेस दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। आप की कोशिश है कि राष्ट्रीय राजधानी में चौथी बार सरकार बनाई जाए। जबकि कांग्रेस अपनी 11 साल पुरानी हार का बदला लेने के लिए जोर लगा रही है। भाजपा भी 26 साल का सूखा खत्म करना चाहती है। फिलहाल, दिल्ली चुनाव को लेकर आप से लेकर कांग्रेस ने अपनी गारंटी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। हालांकि, भाजपा का पिटारा खुलना अभी बाकी है। आप में अरविंद केजरीवाल सीएम फेस हैं। जबकि भाजपा और कांग्रेस ने अपने चेहरे का ऐलान नहीं किया है। जानिए किस दल ने अब तक क्या-क्या वादे किए हैं? सबसे पहले बात करते हैं सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल महीनेभर से लगातार चुनावी वादे और घोषणाएं कर रहे हैं। केजरीवाल ने एक-एक कर बड़े ऐलान के जरिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। आधी आबादी से लेकर बुजुर्ग, ऑटो ड्राइवर और पुजारी-ग्रंथी तक को साधने के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है।

आप ने बुजुर्गों को लेकर संजीवनी स्कीम का ऐलान किया है। आप का दावा है कि सरकार बनी तो 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। सरकारी हो या प्राइवेट... हर हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज मुफ्त होगा। फिलहाल, खर्चे की लिमिट तय नहीं की गई है। योजना की पात्रता में इनकम लिमिट की बाधा भी आड़े नहीं आएगी। ये योजना केंद्र की आयुष्मान भारत से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आप सरकार है और रोचक यह है कि यहां केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है। भाजपा आरोप लगाती है कि केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम को लागू नहीं होने दे रही है। ऐसे में आप सरकार अब भाजपा के दावों को काउंटर करने के लिए संजीवनी योजना लेकर आई है। इस योजना को बड़ा गेमचेंजर भी माना जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा मिलती है। आप के चुनावी दफ्तरों में इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा काउंटर खोले गए हैं और केजरीवाल कवच ऐप में डिटेल सब्मिट की जा रही है। एक सिंबोलिक कार्ड देकर जनता के बीच भरोसा पैदा करने की कवायद की जा रही है।

आप ने दूसरा बड़ा वादा महिलाओं से जुड़ा किया है। आप का कहना है कि सरकार बनी तो महिला सम्मान योजना लागू करेंगे और प्रत्येक महिला को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा और इसकी पात्रता की शर्तें हैं। आप अपने चुनावी दफ्तरों में महिलाओं के रजिस्ट्रेशन भी कर रही है और उनकी जानकारी केजरीवाल कवच में अपलोड कर रही है। इसके लिए महिलाओं के वोटर कार्ड की जानकारी ली जा रही है। एटीएम की तरह जो कार्ड दिया जा रहा है, उसमें केजरीवाल कवच कार्ड लिखा है और कार्ड नंबर भी लिखा गया है। पार्टी ने दावा किया कि इस योजना के लिए 22 लाख से ज्यादा महिलाएं रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं।

केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए के बीमा की घोषणा की है। उन्होंने ऑटो चालकों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। साल में दो बार 2,500 रुपए वर्दी भत्ते का वादा किया है और ऑटो चालकों के बच्चों के लिए निशुल्क कोचिंग का ऐलान किया है।

झुग्गी झोपड़ियों में वोटबैंक

चूंकि, दिल्ली में बड़ी आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है और यह वोटर्स आप का परंपरागत आधार माना जाता है। सवाल उठ रहा है कि क्या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिए फ्लैट दिल्ली की प्रमुख 20 सीटों पर भाजपा के लिए गेमचेंजर साबित होंगे? दिल्ली की 750 झुग्गियों में 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से आधे रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो आप और अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूत वोटबैंक हैं। यही वो वोटबैंक है जिस पर अब भाजपा सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जनवरी को दिल्ली में भाजपा के लिए चुनावी बिगुल फूंका और झुग्गीवासियों को करीब 1,675 फ्लैटों की चाबियां सौंपी। इसे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। 2020 में करीब 61 प्रतिशत गरीबों ने आप को वोट दिया था, जिससे उसे 62 सीटें जीतने में मदद मिली थी। 2015 में 66 प्रतिशत गरीबों ने केजरीवाल की पार्टी को वोट दिया, जिसके दम पर पार्टी ने रिकॉर्ड 67 सीटें जीतीं थीं।

ऑटो रिक्शा को सवारी उपलब्ध कराने के लिए पूछो ऐप पर लाया जाएगा। शहर के ऑटो रिक्शा चालक आप की स्थापना के बाद से ही पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन आधार रहे हैं। केजरीवाल खुले मंच से यह बोल रहे हैं कि जैसे मैंने मुफ्त बिजली दी, वैसे ही इन योजनाओं को भी लागू करेंगे। कुछ लोग इसे रेवड़ियां बांटना कहते हैं, लेकिन मैं इससे अपने लोगों को सशक्त बनाना कहता हूं।

30 दिसंबर को केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर आगामी चुनाव में आप फिर सत्ता में आती है तो मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। केजरीवाल का कहना है कि पुजारी और ग्रंथी हमारे धार्मिक रीति-रिवाजों के संरक्षक रहे हैं। वे समाज की निस्वार्थ सेवा करते रहे हैं। दुर्भाग्य से किसी ने कभी उनकी आर्थिक भलाई पर ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी वादा किया है। उन्होंने कहा है कि आप जीती तो बढ़े हुए पानी के बिल माफ कर देंगे। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से पानी के बढ़े हुए बिलों का भुगतान नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 12 लाख परिवारों को जीरो राशि का बिल मिला है। आप सरकार दिल्ली के घरों को 20,000 लीटर मुफ्त पानी मुहैया करा रही है। इसके अलावा, केजरीवाल ने दिल्ली वालों से मुफ्त पानी और मुफ्त बिजली की सुविधा भी लगातार जारी रहने का वादा किया है। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार का भरोसा दिया है। आप ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं।

दिल्ली चुनाव में आप को टक्कर देने के लिए कांग्रेस भी बड़ी घोषणाओं और वादों से पीछे नहीं हटना चाहती है। दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक वाला प्लान तैयार किया है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने पर दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में कर्नाटक की तरह महिलाओं को लाभ देंगे। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली की सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में इस योजना

को लागू किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर इसी मॉडल पर गृह लक्ष्मी योजना लागू की है। दिल्ली के लिए प्यारी दीदी योजना नाम दिया गया है।

कर्नाटक चुनाव की तरह कांग्रेस ने दिल्ली में भी पांच गारंटी देने की तैयारी की है। पार्टी सिलसिलेवार तरीके से घोषणाएं कर रही है। राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी कांग्रेस ने हेल्थ सेक्टर में चिरंजीवी योजना की तरह जीवन रक्षा योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत कांग्रेस ने 25 लाख के हेल्थ बीमा का वादा किया है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस जो पांच गारंटी देने जा रही है, उनमें प्यारी दीदी योजना (महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर), जीवन रक्षा योजना (स्वास्थ्य बीमा), युवाओं को नौकरी की गारंटी, लेबर क्लास इनकम गारंटी स्कीम और सभी के लिए राशन योजना का ऐलान भी कर सकती है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा, हमने गृह ज्योति और गृह लक्ष्मी की गारंटी को पूरा किया है। कर्नाटक में महिलाओं को 2,000 रुपए मिल रहे हैं। वे बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं और मुफ्त राशन पा रही हैं। हम बेरोजगार लोगों को 3,000 रुपए दे रहे हैं। कुल 1 करोड़ 22 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कांग्रेस जहां भी और जो भी वादा करती है, हमेशा उसे पूरा करती है। हम बाकी गारंटियों की घोषणा बाद में करेंगे। 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को दिल्ली में हार मिली है। 2015 और 2020 में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका। पार्टी ने 1998 से 2013 तक यानी 15 साल राष्ट्रीय राजधानी में सत्ता संभाली और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहीं। हालांकि, अब तक आप और कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां अपने घोषणा पत्र को लॉन्च करेंगी। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन कहते हैं कि पिछले 11 सालों में दिल्ली ने कूड़े के ढेर, प्रदूषित यमुना, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था सभी को प्रभावित होते देखा है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जब लोग कोविड के बीच मर रहे थे, तब केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा बनाने में व्यस्त थी और केजरीवाल शीशमहल बनाने में व्यस्त थे। दिल्ली चुनाव में भाजपा भी दमखम के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी ने चुनाव से पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं और सत्तारूढ़ आप को घेरने के लिए कई फ्रंट खोल रखे हैं। आप की योजनाओं से लेकर भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा जल्द ही अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। हालांकि, भाजपा का चुनावी एजेंडा क्या रहेगा और क्या घोषणाएं की जा सकती हैं? यह भी लगभग साफ होने लगा है।

● **सुनील सिंह**

शीश महल के मुद्दे पर घेरने की तैयारी

प्रधानमंत्री मोदी भी शीशमहल का मुद्दा उठा चुके हैं। यहां तक कि वे अपनी जीवनशैली और केजरीवाल की लाइफस्टाइल के बीच तुलना भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं शीशमहल बना सकता था, लेकिन मेरा सपना यह था कि मेरे देशवासियों को पक्के घर मिलें। देश अच्छी तरह जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। हालांकि, पिछले 10 वर्षों में गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं, जिससे उनके सपने पूरे हुए हैं। दरअसल, भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें पर्दे पर 1 करोड़ रुपए और फर्श पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली चुनाव के आंकड़े देखें तो पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है और सभी सातों संसदीय सीटें जीतीं। लेकिन जब विधानसभा चुनावों की बात आती है तो दिल्ली के वोटर्स आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, जिसने पिछले एक दशक से दिल्ली में शासन किया है। दिल्ली में 1998 से सत्ता से बाहर चल रही भाजपा अब इस सूखे को खत्म करने की कोशिश में है।

फंदेबाज शिकारियों पर नकेल

मप्र में 10 हाथियों की मौत के बाद वन विभाग की फजीहत हो चुकी है। इस घटना ने पूरे महकमे की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। महकमे से ही जुड़े कई लोग इस घटना को लेकर शिकारियों पर भी संदेह व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश के वनों में वन्यप्राणी सुरक्षित नहीं हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार हो रहीं बाघों की मौत और हाल ही में हुई हाथियों की मौत के बाद वन विभाग शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है। इस अभियान के दौरान वनों में फंदा और बिजली के तार डालकर शिकार करने वालों की पहचान कर उन पर नकेल कसी जा रही है।

मप्र में सरकार की सख्ती के बावजूद वन्य जीवों के शिकार का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आलम यह है कि किसी मामले में जब भी शिकारी पकड़े जाते हैं, वे कमजोर कानूनों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। इसे लेकर वन इकाइयों को एडवाइजरी जारी की गई है। जिसके अनुसार वन्यजीवों के शिकार में अब आरोपित को जमानत न मिल पाए इसके लिए वन विभाग आरोपित का प्रकरण मजबूती के साथ न्यायालय में रखेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश के वनों में फंदा और बिजली के तार डालकर सबसे ज्यादा शिकार किए जा रहे हैं। शिकारी छोटे वन्यप्राणियों का शिकार करने इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें कई बार बड़े वन्यप्राणी फंस जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। प्रदेश के वनों में साल 2014 से 2024 तक 3614 अवैध शिकार की घटनाएं सामने आईं हैं। इनमें सबसे ज्यादा शिकार फंदा और बिजली के तारों से हुए हैं। शिकार की इन घटनाओं को रोकने के लिए अब वन विभाग ऑपरेशन चलाने जा रहा है। गौरतलब है कि टाइगर स्टेट प्रदेश में बाघों की मौत भी सबसे ज्यादा हो रही है। प्रदेश के वनक्षेत्रों में इस साल अब तक 35 से ज्यादा टाइगर की मौत हो चुकी है। यह देश के दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। शिकार की बढ़ती घटनाओं को रोकने वन विभाग कड़े नियम बनाकर कार्रवाई करेगा। वनों में बिजली के तार और फंदे से सबसे ज्यादा 885 शिकार हुए हैं। इनमें 311 जंगली सुअर, 116 नीलगाय, 91 तेंदुए, 77 चीतल, 48 सांभर, 35 बाघ व 17 मोर की मौत हो गई। घटनाओं को देखते हुए वन विभाग अभियान चला रहा है। प्रदेश में पिछले 11 साल से शिकार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सरकार की सख्ती के बावजूद शिकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 2014 में 434 वन्य प्रणियों के शिकार हुए थे। वहीं 2015 में 401, 2016 में 171, 2017 में 245, 2018 में 324, 2019 में 266, 2020 में 498, 2021 में 376, 2022 में 480, 2023 में 321 और 2024 में अब तक 98 वन्य प्राणियों के शिकार हुए हैं।

वन्य जीव हमले से मृत्यु पर 25 लाख मुआवजा

मप्र में पिछले कुछ साल से वन्य जीवों के हमले बढ़ गए हैं। दरअसल, वन क्षेत्रों के आसपास बसे गांवों में पहुंचकर हाथी, बाघ, तेंदुओं के हमले बढ़ने के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। ऐसे में वन्य जीव के हमले से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आठ लाख रुपए के स्थान पर अब 25 लाख रुपए देने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वन विभाग मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के अनुसार जंगलों में वन्यप्राणी के हमले में मरने वाले व्यक्तियों को 25 लाख रुपए हर्जाना देने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें आर्थिक सहायता दो किस्त में दी जाएगी। गौरतलब कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले महीने 10 हाथियों की मौत हो गई थी। इसके बाद हाथियों के हमले से दो युवकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री ने सहायता राशि 25 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की थी। वन्यप्राणी के हमले पर व्यक्ति की मृत्यु पर उसके स्वजन को तुरंत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शेष 15 लाख रुपए की बैंक में एफडी की जाएगी। इसमें 10 लाख रुपए की एफडी पांच साल बाद और शेष पांच लाख रुपए की एफडी 10 साल बाद तोड़ी जाएगी। यह राशि मृतक के वारिसों को ब्याज सहित भुगतान की जाएगी। प्रदेश में बाघ तेंदुआ सहित अन्य मांसाहारी वन्यप्राणियों के जंगल से बाहर निकलकर नजदीक की बस्ती में पहुंचने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे मानव-वन्यप्राणी द्वंद की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले पांच साल में वन्यप्राणियों के हमले में 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

वनक्षेत्रों में शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए गश्ती की जाएगी। 15 डॉग स्क्वाड और मैटल डिटेक्टर के साथ वन अधिकारी, कर्मचारी गश्ती करेंगे। वन मंडल-टाइगर रिजर्व, वन विकास मंडल इकाई में गश्त दिन व रात चलेगी। सप्ताह में न्यूनतम 3 दिन संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ, 2 दिन डीएफओ और एसडीओ और एक दिन सीसीएफ और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर शामिल होंगे। गश्ती के दौरान वन-राजस्व सीमा से लगे वन क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र की बागड़, फेंसिंग में सर्चिंग की जाएगी। गश्ती के दौरान शिकार के लिए प्रयुक्त फंदे में वन्यप्राणी फंसा हुआ पाए जाने की स्थिति में तत्काल निकटतम रेस्क्यू स्क्वाड की सहायता से वन्यप्राणी के उपचार की उचित व्यवस्था की जाएगी तथा विधिवत जप्ती कर अपराध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा एवं अपराध में संलिप्त अपराधी का पता लगाकर तत्काल कार्रवाई करनी होगी। वन भूमि अथवा वन्यप्राणी विचरित क्षेत्र से जाने वाली विद्युत लाइन के नीचे गश्ती करना होगी तथा साथ में आवश्यकतानुसार विद्युत विभाग के अमले को भी साथ रखना होगा। गश्ती के दौरान संबंधित ग्राम, नगर में पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों की जानकारी लेकर उसे वन परिक्षेत्र में संधारित आरोपी निगरानी पंजी में भी दर्ज करना होगा। विगत 10 वर्षों में फंदे एवं बिजली लाइन में तार बिछाकर वन्य जीवों के शिकार से संबंधित 750 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिसमें 35 टाइगर के शिकार प्रकरण भी शामिल हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर अब वन विभाग के आला अधिकारी सतर्क हो गए हैं। इस संबंध में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ वीएन अंबाड़े ने सभी वन इकाइयों को निर्देश भी जारी किए हैं।

● **धर्मेंद्र कथूरिया**

तेजी से उजड़ रहा बुंदेलखंड का वन क्षेत्र

बुंदेलखंड में दिनों-दिनों कम हो रहा वन क्षेत्र अब चिंता का विषय बन रहा है। सरकार वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पौधरोपण अभियान चलाकर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। इसके बावजूद बीते सालों में प्रदेश के बुंदेलखंड में जंगल जमकर जमीन में तब्दील हुए हैं। इसका खुलासा भारतीय वन स्थित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में हुआ है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार विंध्य क्षेत्र में शामिल ऊर्जा राजधानी सिंगरौली सर्वाधिक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले जिलों में अग्रणी बनकर उभरा है। बीते 2 सालों में यहां 34.83 प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। इसके बाद यहां के शहडोल में 13.67 और उमरिया में 5.07 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं, मालवा के बुरहानपुर में सर्वाधिक 31.4 प्रतिशत और धार-बड़वानी में 19-19 प्रतिशत वन क्षेत्र कम हुआ है। हरदा में यह कमी 8.86 प्रतिशत दर्ज की गई है।

कभी बुंदेलखंड का इलाका एक घने वन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। लोगों के जीवन का आधार वृक्ष थे। अचार, महुआ, तेंदू, आम और आंवला ऐसे वृक्ष थे जो यहां के लोगों की आय के मुख्य श्रोत थे। वनों में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां लोगों के हर मर्ज की दवा थी। लेकिन बुंदेलखंड इलाके में वनों के विनाश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वनों के विनाश का ही परिणाम है कि जलस्तर में तेजी से गिरावट हुई, बीहड़ों का विस्तार हुआ। अतीत में जो हरियाली लोगों को लुभाती थी आज उसकी जगह वीरानी छाई है। भूमि की नमी समाप्त हो गई है और मानव व अन्य जीव बूंद-बूंद पानी के लिए मोहताज है।

भारतीय वन स्थित सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बीते दो सालों के दौरान प्रदेश में जहां 25 प्रतिशत तक वनाच्छादित क्षेत्र में कमी आई है, वहीं दमोह और सागर जिलों में तो 85.29 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 की मानें तो मप्र के वनाच्छादित क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दमोह जिले में 85.29 प्रतिशत जंगल कम हुआ है। इसके बाद 71.38 प्रतिशत कमी के साथ इस अंचल का संभागीय मुख्यालय सागर रहा है। जबकि 2021 के सर्वेक्षण के मुकाबले यहां के छतरपुर में महज 12.02 प्रतिशत जंगलों में कमी आई है। इतना ही नहीं छिंदवाड़ा जिले में 21.58, कटनी 32.22 और सिवनी में 34.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ महाकौशल क्षेत्र भी जंगलों की बर्बादी के केंद्र के तौर पर उभरकर सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के 14 जिलों में सघन वन क्षेत्र समाप्त हो गए हैं। इनमें ग्वालियर चंबल में आने वाले मुरैना, भिंड और दतिया के साथ मालवा के धार, बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, नीमच, शाजापुर और उज्जैन भी शामिल हैं। प्रदेश के राजगढ़ और रतलाम जिले को भी सघन वन क्षेत्रों की सूची में स्थान नहीं दिया गया है। भोपाल संभाग की बात करें तो जंगलों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक राजधानी के पड़ोसी विदिशा और रायसेन जिले साबित हुए हैं। हालांकि भोपाल में ही 0.54, सीहोर 4.17, होशंगाबाद 0.70 और राजगढ़ में 1.02 प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र में कमी आई है। बावजूद इसके विदिशा में 25.42 और रायसेन में 23.23 प्रतिशत वनाच्छादन क्षेत्र कम हो गया है। इन सबके बावजूद भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2023 के अनुसार, मप्र ने एक बार फिर देश में सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले राज्य का स्थान बरकरार रखा है। राज्य का कूल वन और वृक्ष आवरण 85,724 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही वनावरण क्षेत्र 77,073 वर्ग किलोमीटर के साथ मप्र अग्रणी रहा है।

वनों के विनाश में खनिजों के वैध और अवैध उत्खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हरी-भरी पहाड़ियां जो जैव विविधिता के महत्वपूर्ण केंद्र थे उनको समतल मैदान और गहरी खाइयों में बदल दिया गया। विनाश के इस विकास में सरकार, प्रशासन, पॉलिटिशियन और खनिज माफियाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पत्थर खदान के नाम पर, क्रेशर बेशकीमती मिनिरल्स के नाम पर सरकार ने खनन के कारोबार को बढ़ाया किंतु इसमें पर्यावरण के नियमों की जमकर अनदेखी की गई। खनन के इस खेल में मिट्टी मुरम और रेत के खनन में तो जैसे वैध-अवैध का कोई भेद ही नहीं रह गया। जिसकी जहां मर्जी वहां से रेत निकालता और बाजार में बेच आता। केन नदी की रेत पर तो जैसे माफिया राज ही चलता है। रेत के इस अवैध खनन में सियासत के नामधारी लोग भी लिप्त हैं, जो रेत के परिवहन के लिए अवैध पुल का निर्माण कर रेत उप्र के इलाकों में बेचते हैं। खजुराहो सेंड के नाम से यह रेत रीवा-गोरखपुर तक पहुंचती है। सवाल यही खड़ा होता है कि आमजन मानस पर्यावरण के मुद्दे पर कितना सजग और कितना चेतना शून्य है। आज गांवों से भी प्रकृति से जुड़े दोना-पत्तल गायब हो गए हैं, कुल्हड़ तो देखने को नहीं मिलते।

● **सिद्धार्थ पांडे**

जंगलों में बबूल के पेड़ों ने किया कब्जा

बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो अधिकतर जंगलों में फलदार पेड़ कम होते जा रहे हैं। यहां विलायती बबूल के पेड़ों ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन इन्ही पेड़ों की वजह से बुंदेलखंड में कुछ हरियाली दिखाई दे रही है। वरना स्थिति और बदतर हो सकती थी। हालांकि विदेशी बबूल के जंगली जीव-जंतुओं की मौत का कारण भी है। इनके कांटों की वजह से कई जानवरों की मौत हो जाती है। बुंदेलखंड में सरकार का पौधरोपण कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है। जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं उनके महज 10 से 15 प्रतिशत ही तैयार हो रहे हैं। वहीं इससे ज्यादा मात्रा में पेड़ों का कटान हो रहा है। इसलिए वन क्षेत्र बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं। बुंदेलखंड की जमीन क्षारीय गुणों से युक्त है इसलिए यहां मुख्यतः आम, बेर, इमली, जामुन, महुआ, शीशम, पीपल, बरगद और आवंला जैसे पौधों को विकसित होने में कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते इनकी देख-रेख की जाए। पानी का समुचित उपाय किया जाए और छुट्टा जानवरों से इन्हें बचाया जाए। हमीरपुर जिले के जंगलों में इन पेड़ों का औसत करीब 2.25 प्रतिशत ही है। वरना यहां बबूल और कांटे वाले पेड़ों ने जंगलों में कब्जा जमा लिया है। गौरतलब है कि बुंदेलखंड के जिलों में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जीव-जंतु पाए जाते हैं।

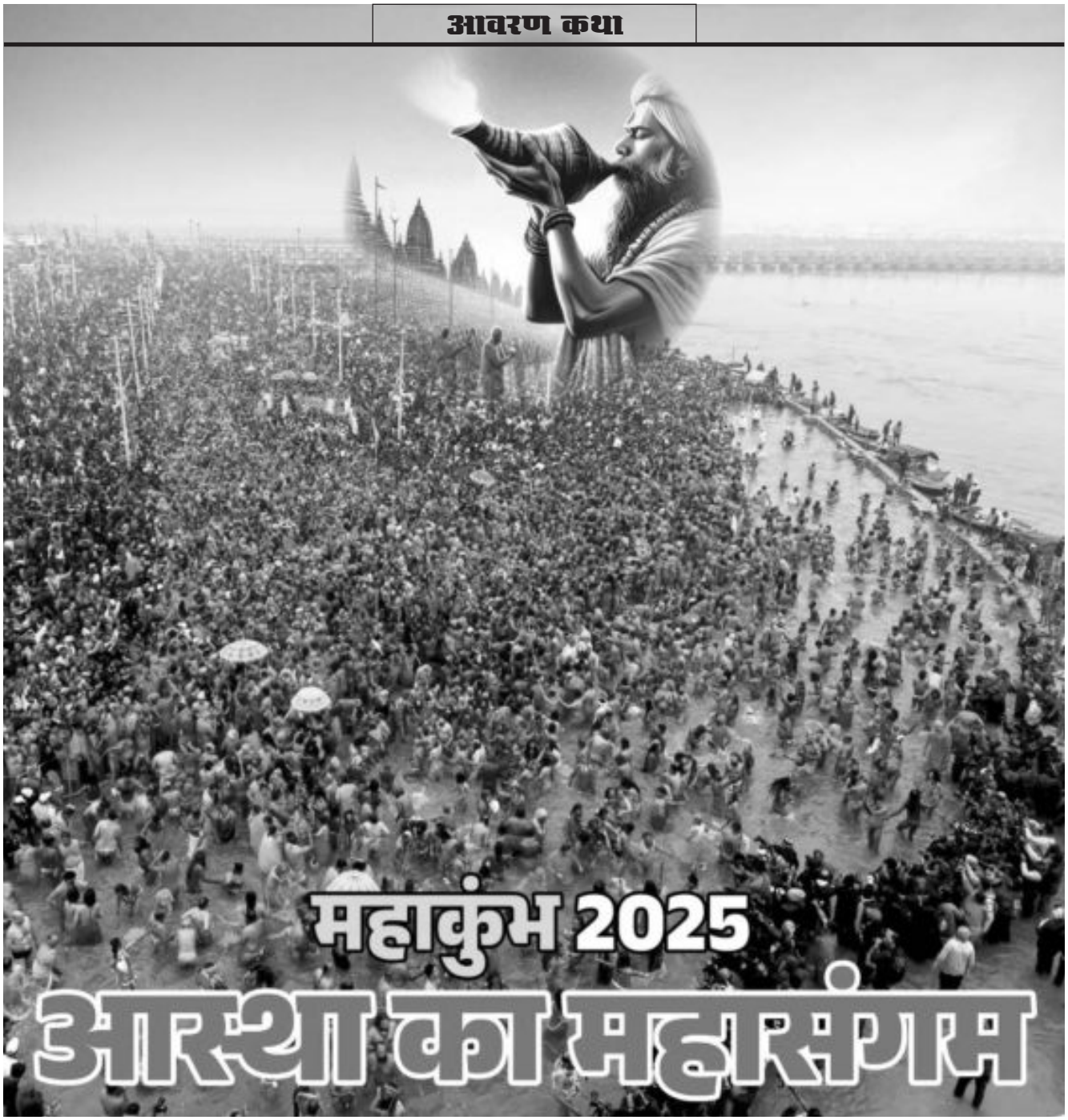

पौष पूर्णिमा यानि 13 जनवरी से आस्था के महासंगम महाकुंभ का शुभारंभ तीर्थराज प्रयागराज में हो गया है। 144 साल बाद इस बार ग्रहों का दुर्लभ संयोग बना है, इसलिए इस महाकुंभ का महत्व और बढ़ जाता है। महाकुंभ के पहले दिन ही करोड़ों लोगों ने संगम पर डुबकी लगाई। महाकुंभ का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि आत्मशुद्धि और मोक्ष की तलाश में विदेशी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

सनातन परंपरा का सबसे बड़ा मानव समागम महाकुंभ आज अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय आस्था का महापर्व बन गया है। ठंड और कोहरे से लिपटा त्रिवेणी का तट ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सृष्टि ने खुद को इस अद्वितीय आयोजन के स्वागत में संवार लिया हो। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की धाराओं का मिलन स्थल दिव्यता का ऐसा केंद्र बन गया, जहां हर सांस में श्रद्धा और हर पल में ऊर्जा का संचार हो रहा था। आंखों में सूरमा, भस्म से लिपटा तन, जटाजूट की वेणी और हाथों में त्रिशूल व डमरू लिए नागा साधुओं का दृश्य मानो युगों पुरानी कहानियों को जीवंत कर रहा था। त्रिवेणी के तट पर ये साधु किसी देवदूत की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो अपनी तपस्या और आस्था के साथ इस अद्वितीय स्नान के लिए तैयार थे। यह दृश्य भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।

विश्व के लिए जिज्ञासा बना महाकुंभ

प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा मेला सजा है। लाखों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड के बावजूद कुंभ का आनंद ले रहे हैं। महाकुंभ देश-विदेश के अनगिनत श्रद्धालुओं की जिज्ञासा है। भारत का चित्त और विवेक सनातन धर्म से प्रेरित है। इसी धर्म से संचालित भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष के अनुभवों का परिणाम है। संस्कृति और परंपरा अंधविश्वास नहीं हैं। ये विशेष प्रकार के इतिहास हैं। इतिहास में शुभ और अशुभ साथ-साथ चलते हैं। शुभ को राष्ट्रजीवन से जोड़ना और लगातार संस्कारित करना संस्कृति है। राष्ट्रजीवन में बहुत कुछ करणीय है और बहुत कुछ अकरणीय। यहां धर्म, दर्शन, संस्कृति, परंपरा और आस्था राष्ट्रजीवन के नियामक तत्व हैं।

ये पांच तत्व राष्ट्रजीवन को ध्येय और शक्ति देते हैं। कुंभ मेला इन्हीं पांचों तत्वों की अभिव्यक्ति है। लाखों श्रद्धालुओं का बिना किसी निमंत्रण प्रयाग पहुंचना आश्चर्य पैदा करता है। करोड़ों लोग आस्थावश आए हैं। तमाम जिज्ञासावश आए हैं और लाखों आश्चर्यवश। महाकुंभ समागम संस्कृति प्रेमियों का महाउल्लास है।

यह यज्ञ, साधना, योग और आत्मदर्शन का पुण्य क्षेत्र रहा है। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां गले मिलती हैं। ऋग्वेद के ऋषि इमे गंगे यमुने सरस्वती... गाकर स्तुति करते हैं। कुछ लिबरल छद्म सेक्युलर सरस्वती को स्वीकार नहीं करते। सरस्वती का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। तीनों संगम में मिलती हैं। तब तप, यज्ञ और योग की तपोभूमि प्रयाग हो जाती है और प्रयाग हो जाता है तीर्थराज।

कुंभ मेले से 45 हजार परिवारों को मिल रहा रोजगार

साल 1906 के कुंभ मेले में ब्रिटिश सरकार ने सिर्फ 10,000 रुपए कमाए थे। 200 सालों से ज्यादा समय में कुंभ का स्वरूप और इससे होने वाली कमाई कई गुना बढ़ गई है। 2013 के प्रयाग कुंभ मेले में 12,000 करोड़ की कमाई हुई थी, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोगों को काम मिला था। इस बार यह संख्या और बढ़ने की संभावना है। 13 जनवरी 2025 को उप्र के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो गया है, महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को आखिरी स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। कुंभ में 13 अखाड़ों के साधु-संतों सहित लाखों श्रद्धालु जमा हो रहे हैं। केंद्र सरकार सहित कई राज्यों की सरकारें कुंभ के लिए एक साथ काम करती हैं। 2019 के अर्धकुंभ में 15 राज्यों की सरकारों ने 261 प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। राज्य सरकारों के 28 विभाग और केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों पर अर्धकुंभ को आयोजित करने की जिम्मेदारी थी। मेले के लिए जमीन तैयार की जाती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, साफ-सफाई की व्यवस्था की जाती है। मेडिकल सर्विसेज, हेल्पडेस्क, कैंप में लाखों लोगों के रहने की व्यवस्था, स्टाल वगैरह के लिए अलग-अलग संस्थानों को जगह का अलॉटमेंट किया जाता है। साल 2013 के प्रयाग कुंभ के लिए खासतौर पर कुंभ नगरी की बैंक खोली गई। मेले से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए अस्थायी कोर्ट खोला गया, कुंभ नगरी के लिए अलग से एक एसपी और एक डीएम की तैनाती हुई थी।

आस्था और संस्कृति का मेल

कुंभ आस्था है। सांस्कृतिक प्रतीक है। वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। सूर्य की 12 राशियों में एक राशि का नाम कुंभ है। मांगलिक कार्यों एवं तप साधना के दौरान सर्वप्रथम कुंभ कलश की स्थापना होती है। पुराणों के अनुसार कलश के मुख में विष्णु हैं। ग्रीवा में रुद्र और मूल में ब्रह्मा हैं। सप्तसिंधु, सप्तद्वीप ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण ज्ञान भी कुंभ कलश में है। पौराणिक आख्यान के अनुसार एक समय सागर मंथन हुआ था। मंथन से प्राप्त विष महादेव शंकर पी गए, लेकिन मंथन से निकले अमृत कुंभ पर युद्ध हो गया। स्कंद पुराण के अनुसार अमृत घट चार जगह हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में गोदावरी के तट पर गिरा था। इन्हीं चार स्थानों पर कुंभ के आयोजन होते हैं। अमृत मिले तो अनंतकाल का जीवन। विश्व के किसी भी विद्वान ने अमृत की चर्चा नहीं की थी। केवल भारतीय दृष्टि में ही अमृत की प्यास है। अमृत की प्रीति भी अमृत है। सूर्य अमर हैं। उगते हैं। अस्त होते हैं। मास, वर्ष, युग बीतते हैं। नदियां प्रवाहमान रहती हैं। कुंभ मेले में सहस्त्रों साधु, योगी और मंत्रवेत्ता आए हैं। उनके चित्त में घर-गृहस्थी की चिंता नहीं है, लेकिन लाखों गृहस्थ भी समागम में हैं। सबका विश्वास है कि कुंभ में स्नान और पुष्पार्चन जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाएगा।

संस्कृति ही प्रत्येक देश की साधना, उपासना और कर्म को गति देती है। संस्कृतियों की भिन्नता प्रत्येक राष्ट्र की पहचान होती है। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखा है, भारत में अध्यात्म को, यूनान में सौंदर्य तत्व को, रोम में न्याय और दंड व्यवस्था को, चीन में विराट जीवन के आधारभूत नियमों को, ईरान ने सत् और असत् के द्वंद्व को, मिस्र में भौतिक जीवन

की व्यवस्था और संस्कार को और सुमेर जातियों ने दैवीय दंड विधान को अपनी दृष्टि से आदर्श रूप में स्वीकार किया है और उनकी प्रेरणा से संस्कृति का विकास किया है।

भारतीय संस्कृति और परंपरा में प्रतीक गढ़ने और प्रतीकों को लोकप्रिय बनाने की अद्भुत क्षमता है। संस्कृति, परंपरा, धर्म और दर्शन का प्रतीक है कुंभ। ऐसे प्रतीक अल्प समय में नहीं बनते। ओउम् संपूर्णता का प्रतीक है। स्वास्तिक प्रतीक भी लोकप्रिय है। मूर्तियां और मंदिर भी ऐसे ही प्रतीक हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि कुंभ मेला सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना है। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने सम्राट हर्षवर्धन के शासन में संपन्न कुंभ मेले का वर्णन किया है। कुंभ मेलों में शास्त्रार्थ होते थे। आध्यात्मिक दार्शनिक विषयों पर चर्चा होती थी। शंकराचार्य ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया था। कुंभ सारी दुनिया को विश्वबंधुत्व, लोककल्याण एवं विश्वशांति का संदेश दे रहा है। मेले का संदेश सुस्पष्ट है। धर्म, परंपरा, संस्कृति, दर्शन और आस्था के संरक्षण संवर्धन के लिए हम भारत के लोगों को अतिरिक्त श्रम करना चाहिए।

एकता का प्रतीक

महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर 12 साल में चार पवित्र स्थानों (प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक) में आयोजित होता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाने और मोक्ष प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ का आयोजन धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणनाओं और ऐतिहासिक परंपराओं पर आधारित है। यह केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है, जो देश-विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पौष पूर्णिमा पड़ती है। यह पौष मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि का नाम है। इस दिन पूर्ण चंद्र दिखाई देता है इसलिए पूर्णिमा की पवित्र तिथि होती है। इस दिन सूर्य एवं चंद्र की पूजा एवं आराधना तथा गंगा में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौष पूर्णिमा से ही कल्पवास का प्रारंभ होता है। इस दिन कल्पवास का संकल्प लिया जाता है, जो माघी पूर्णिमा तक एक महीने की कठिन आध्यात्मिक तप तथा श्रद्धा को प्रदर्शित करता है।

दुनिया का सबसे बड़ा मेला

महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है, जिसमें देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से साधु-संतों समेत 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। महाकुंभ में दुनियाभर के संत-साधु व भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस धार्मिक आयोजन में शाही स्नान का विशेष महत्व है, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाही स्नान के दौरान पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से पापों का प्रायश्चित होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान लोगों को आध्यात्मिकता के करीब लाता है। प्रयागराज का महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर फैला है और इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। उप्र शासन ने महाकुंभ मेला परिक्षेत्र को राज्य का 76वां जिला घोषित किया है। इस साल का महाकुंभ बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि ज्योतिषियों के मुताबिक 144 साल बाद ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा, शनि और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है। बताया जा रहा है कि ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग समुद्र मंथन के दौरान बना था।

महाकुंभ के लिए प्रशासन ने संगम तट पर कुल 41 घाट तैयार किए हैं। इनमें 10 पक्के घाट हैं, जबकि बाकी 31 घाट अस्थायी हैं। संगम

पानी से हवा तक हाईटेक सुरक्षा

महाकुंभ-2025 के सिक्योरिटी प्लान ने अब तक हुए सुरक्षा इंतजामों को काफी पीछे छोड़ दिया। खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नू समेत कई आतंकवादी संगठनों के निशाने पर महाकुंभ की भीड़ हो सकती है। ऐसे में सिक्योरिटी प्लान केंद्रीय एजेंसियों के साथ मंथन के बाद फाइनल हुआ। 40 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में हाईटेक सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स से पूरे मेले को लैस किया गया है। आतंकी गतिविधियों, खासकर ड्रोन अटैक के बढ़ते खतरों को देखते हुए पहली बार महाकुंभ में इजराइली एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी हो रही है। साथ ही न्यूक्लियर, केमिकल, जैविक, रेडियोलॉजिकल और एक्सप्लोसिव हमले से निपटने के हाईटेक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहली बार सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किए गए हैं। गंगा-यमुना की लहरों के बीच अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे निगरानी करेंगे। नदी की 100 से 200 मीटर तक गहराई में इसके कैमरे हर गतिविधियों को कैद करेंगे और अलर्ट जारी करेंगे। महाकुंभ में 16 अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल होगा। अभी 8 आए हैं। 8 ड्रोन महज संगम नोज के इलाके को कवर करेंगे। बाकी अन्य घाटों के इर्द-गिर्द होंगे। इन ड्रोन पर गंदे पानी से फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन बाद कुछ वक्त के लिए ऊपर लाकर फिर पानी में प्रवेश करा सकते हैं। इसके साथ ही पहली बार सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जाल है। एआई-संचालित कैमरे आईसीसीसी और पुलिस कंट्रोल रूम में सीधे लाइव होंगे। मेला क्षेत्र के साथ ही शहरों के प्रवेश मार्ग और रेलवे स्टेशन पर भी एआई सेटअप किया गया है। महाकुंभ में बेहद शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है। इसे इजराइली कंपनी ने बनाया है। मेला क्षेत्र में सिस्टम 3 दिशाओं में तैयार है, जो पानी वाले इलाकों को भी कवर करेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट अपनी पोजिशन ले चुके हैं। सभी मेला क्षेत्र में उड़ने वाले ड्रोन नजर रख रहे हैं। इन्हें 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है। अगर कोई ड्रोन उड़ाने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल रूम में रेड सिग्नल आएंगे। लोकेशन ट्रेस होगी। कौनसा ड्रोन है, उसमें क्या है, दूरी कितनी है, किस साइड से हवा में जाने की कोशिश की गई, ये सारा डेटा टीम को पल भर में पता चल जाएगा। सिस्टम में ड्रोन को डि-एक्टिवेट करने की क्षमता होती है। वहीं, एंटी ड्रोन सिस्टम को मानवरहित एरियल सिस्टम भी कहा जाता है। यह सेंसर आर्किटेक्चर की तरह है। इसका उद्देश्य ड्रोन हमलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। इसके जरिए ड्रोन (ड्रोन और ऑपरेटर के बीच लिंक के बिना उड़ान भरने वाले) का पता लगाया जाता है। हालांकि ड्रोन को ट्रेस करने के लिए रडार सबसे अच्छा विकल्प है।

घाट प्रयागराज का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण घाट है। यहां गंगा, यमुना और सरस्वती (अदृश्य)- तीन पवित्र नदियों का संगम होता है। इसीलिए इसे त्रिवेणी घाट के नाम से भी जानते हैं।

महाकुंभ में अखाड़े आकर्षण का प्रमुख केंद्र होते हैं। अखाड़ों की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या में निपुण साधुओं के संगठन बनाए थे। अभी कुल 13 अखाड़े हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों- शैव, वैष्णव और उदासीन में बांटा गया है। शैव संप्रदाय के कुल 7 अखाड़े हैं, इनके अनुयायी भगवान शिव की पूजा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, इनके अनुयायी भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करते हैं। उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, इनके अनुयायी ओउम् की पूजा करते हैं। ओउम् अनंत शक्ति का प्रतीक है। इस बार महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। न सिर्फ पूरे देश बल्कि दुनियाभर से आने वाले श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ मेले में साधु-संतों, नागा बाबाओं के अलग-अलग रंग और रूप देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे करतब से अभिभूत कर रहा है तो कोई अपने अनूठे संकल्पों, प्रणों और हठ योग के कारण चर्चा में है।

महाकुंभ 2025 में पहला शाही स्नान मकर संक्रांति पर हुआ। इस दिन 3.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ में शाही स्नान की अन्य तिथियां- 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि हैं। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा।

7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था

किसी विपरीत परिस्थिति में साधु-संतों और श्रद्धालुओं को त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक सेक्टर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल के अलावा 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी बनाया गया है। स्नान के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी घाटों पर 300 से अधिक गोताखोरों को तैनात किया गया है। कई वाटर एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। महाकुंभ में एनएसजी कमांडो और उप्र पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। महाकुंभ मेले में भीड़ के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के लिए एआई संचालित कैमरे, ड्रोन और एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। महाकुंभ में संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए स्पॉटरों के अलावा सिविल पुलिस के 15 हजार जवानों को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए 7 प्रमुख मार्गों पर 102 चौकियां स्थापित की गई हैं। संगम और उसके आसपास के जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और निगरानी के लिए 113 ड्रोन तैनात किए गए हैं।

महाकुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार

प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर चल रहे महाकुंभ से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार उत्पन्न होने का अनुमान है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार, महाकुंभ से नाममात्र और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 1 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है। उप्र सरकार को इस कार्यक्रम में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों सहित लगभग 40 करोड़ आगंतुकों के आने की उम्मीद है। सरकारी अनुमानों के अनुसार, अगर 40 करोड़ आगंतुकों में से प्रत्येक औसतन 5,000 रुपए खर्च करता है, तो महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि प्रति व्यक्ति औसत व्यय बढ़कर 10,000 रुपए हो सकता है, जिससे कुल आर्थिक प्रभाव 4 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। इस बीच, भारत और विदेश की कंपनियां 45 दिवसीय आयोजन के दौरान अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए जगह पाने की होड़ में हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) से लेकर फार्मास्युटिकल सेक्टर और मोबिलिटी प्रदाताओं से लेकर डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म तक, व्यवसाय अपने मार्केटिंग बजट को कम कर रहे हैं। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, महाकुंभ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने महाकुंभ मेला 2025 में विभिन्न संरचनाओं के निर्माण के लिए लगभग 45,000 टन स्टील की आपूर्ति की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य के अधिकारियों का अनुमान है कि महाकुंभ 2025 सरकारी राजस्व में 25,000 करोड़ रुपए का योगदान दे सकता है। इसके परिणामस्वरूप 2 ट्रिलियन रुपए का आर्थिक लाभ हो सकता है। इस आयोजन से स्थानीय स्वसहायता समूहों, कारीगरों, होटल व्यवसायियों, होमस्टे मालिकों, रेस्तरां संचालकों और खाद्य विक्रेताओं को लाभ होने की उम्मीद है। डाबर, मदर डेयरी और आईटीसी जैसे प्रमुख ब्रांडों द्वारा 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है।

उप्र सरकार के मंत्री कहते हैं कि तीर्थयात्रियों को उनके स्थान की पहचान करने और बिजली के मुद्दों से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने में सहायता के लिए 25 सेक्टरों में फैले महाकुंभ मेला क्षेत्र में बिजली के खंभों पर 50,000 से अधिक क्यूआर कोड लगाए गए हैं। उप्र के शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि बिजली के खंभों पर 50,000 से अधिक क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के भीतर अपना लोकेशन निर्धारित करना आसान हो जाएगा।

केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि महाकुंभ में 15 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी मेहमानों को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद, योग और पंचकर्म जैसी सुविधाएं प्रदान करने वाला एक टेंट सिटी स्थापित की है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में 10 एकड़ में कलाग्राम बनाया गया है, जहां भारतीय सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित

किया जाएगा। कलाग्राम महाकुंभ मेले के मुख्य आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। इसमें चार धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृति वाला एक भव्य प्रवेश द्वार, एक अनंत कुंभ प्रदर्शनी और देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाले 7 सांस्कृतिक प्रांगण होंगे। 230 से अधिक शिल्पकार भारत के पारंपरिक कला का प्रदर्शन करेंगे। अगले 45 दिनों से अधिक समय तक कलाग्राम, गंगा पंडाल, झूंसी, नागवासुकी और अरैल सहित विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मेला प्रशासन का अनुमान है कि सर्वाधिक 21 प्रतिशत लोगों के जौनपुर रूट से महाकुंभ पहुंचने की संभावना है, जबकि रीवा और बांदा मार्ग से 18 प्रतिशत श्रद्धालु आएंगे। इसी तरह, वाराणसी मार्ग से 16 प्रतिशत, कानपुर मार्ग से 14 प्रतिशत, मिर्जापुर मार्ग से 12 प्रतिशत श्रद्धालु आ सकते हैं। लखनऊ मार्ग से 10 प्रतिशत और प्रतापगढ़ मार्ग से 9 प्रतिशत लोगों के आने की संभावना है। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और निजी वाहन से आने वाले लोग इन्हीं रास्तों से होते हुए संगम पहुंचेंगे।

पर्यटन की व्यवस्था

महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मेला प्रशासन की तरफ से ठहरने की व्यापक व्यवस्था की गई है। मेला क्षेत्र में 10 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप लग्जरी व्यवस्था चाहते हैं तो संगम के ही किनारे ही डोम सिटी में रुक सकते हैं। इसका किराया प्रतिदिन का 80 हजार रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक है। इसके आसपास 2000 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है। यहां ठहरने के लिए आपको 3 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक देने होंगे। इसके लिए बुकिंग भी पहले करानी होगी। प्रयागराज शहर में 42 लग्जरी होटल हैं। सभी की अपनी वेबसाइट है, जिसके जरिए आप उनके बारे में जान सकते हैं और बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेला

क्षेत्र में 100 आश्रयस्थल हैं, हर आश्रयस्थल में 250 बेड हैं। 10 हजार से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था की है। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं और प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं, तो स्टेशन के आसपास 50 होटल हैं, जहां ठहर सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन के बाहर प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरे बनाए हैं। उसमें ठंड से बचाव की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं।

संगम के आसपास कुल 3000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। महाकुंभ जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस, 90 धर्मशालाएं हैं, सभी में ठहरने की व्यवस्था है। संगम के आसपास के इलाके में घरों को पीजी हाउस में बदला गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग दी है। आप यहां ठहर सकते हैं। महाकुंभ मेले में घूमने के लिए श्रद्धालु मैप का सहारा ले सकते हैं। इस बार गूगल मैप ने मेले के लिए अलग व्यवस्था की है। मेला क्षेत्र के लिए सभी पुलों, आश्रमों, अखाड़ों, सड़कों तक सबकुछ दिखाया गया है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक त्रिवेणी संगम में स्नान और मेला घूमने के बाद प्रयागराज के अन्य पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। इनमें लेटे हनुमान जी का मंदिर, अक्षयवट, पातालपुरी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, नागवासुकी मंदिर, शंकर विमानमंडपम महाकुंभ मेला क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा शहर में आप चंद्रशेखर आजाद पार्क, स्वराज भवन, खुसरो बाग, निषादराज पार्क इत्यादि जगहों पर जा सकते हैं।

महाकुंभ जिला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में कुल छोटी और बड़ी 102 पार्किंग बनाई हैं। इनमें 70 प्रतिशत पार्किंग स्नान घाट से 5 किलोमीटर के दायरे में हैं। बाकी 30 प्रतिशत पार्किंग 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में हैं। 24 सैटेलाइट पार्किंग हैं, इनमें से 18 मेला क्षेत्र में और 6 प्रयागराज शहर में बनाई गई हैं। यहां पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक इलाज, पब्लिक एड्रेस सिस्टम मौजूद है। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए 3000 स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं। ये ट्रेनें 13 हजार से अधिक फेरे लगाएंगी। प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब-स्टेशन बनाए गए हैं। ये सब-स्टेशन रेलवे के तीन जोन- उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे में बांटे गए हैं।

दुनिया में सनातन का असर बढ़ा...महाकुंभ की मुस्लिम देशों में सर्चिंग

महाकुंभ अब सिर्फ भारतीय आयोजन नहीं रहा, यह एक वैश्विक पर्व बन गया है। तीर्थराज प्रयागराज में 13 जनवरी को महाकुंभ का भव्य शुभारंभ हो चुका है। ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों के श्रद्धालु भी प्रयागराज पहुंचने लगे हैं। यह आयोजन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को दिखा रहा है। खास बात यह है कि पाकिस्तान और अरब समेत इस्लामिक देश भी महाकुंभ में रुचि दिखा रहे हैं। गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, इस्लामिक देशों में योगी सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे महाकुंभ के आयोजन को खूब सर्च किया जा रहा है। महाकुंभ को सर्च करने वाले देशों की सूची पर नजर डालें तो पहला नाम सबसे ज्यादा चौंकाता है जो कि पाकिस्तान का है। भारत के परस्पर विरोधी देश में लोग महाकुंभ के आयोजन और यहां जुट रही व्यापक भीड़ को खूब सर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाद कतर, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने महाकुंभ में गहरी रुचि दिखाई है। इसके अलावा, नेपाल, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन, थाईलैंड और अमेरिका जैसे देशों के लोग भी महाकुंभ के बारे में पढ़ और खोज रहे हैं। महाकुंभ में अंतरराष्ट्रीय तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या यह दिखाती है कि सनातन संस्कृति का प्रभाव तेजी से फैल रहा है। संगम में डुबकी लगाने वाले सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशों से आए लाखों श्रद्धालु भी इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन रहे हैं। इस रिपोर्ट के नतीजे बताते हैं कि महाकुंभ 2025 ने दुनिया को एक बार फिर भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सनातन धर्म की अद्भुत शक्ति का अहसास कराया है।

दिल्ली की सियासत से बसपा का प्रयोग

बसपा संस्थापक कांशीराम ने अस्सी के दशक में दलित और शोषितों के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। दलित सियासत का ऐसा राजनीतिक प्रयोग किया कि बसपा ने उप्र में चार बार सरकार बनाई। दलित वोटों पर मायावती का लंबे समय तक एकछत्र राज कायम रहा, लेकिन दलितों के मुंह मोड़ने के बाद से बसपा का सियासी ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जीरो पर सिमट जाने के बाद बसपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में नया सियासी प्रयोग करने जा रही, लेकिन मायावती अपने करीब सिपाहसलारों के साथ चुनावी बागडोर अपने हाथों में रखेंगी? दिल्ली की सत्ता पर भले ही बसपा कभी काबिज न हुई हो, लेकिन उसकी धमक शुरू से ही रही है। बसपा को कई सीटों पर अच्छा खासा वोट मिलता रहा है। आम आदमी पार्टी के गठन और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक उदय के बाद से बसपा से दलित वोट पूरी तरह खिसक गया, जिसे 2025 के चुनाव में वापसी के लिए मायावती ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। इसे लेकर उन्होंने सियासी कसरत शुरू कर दी है और दिल्ली चुनाव उनके देखरेख में होगा।

हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद ही मायावती ने पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद के हाथों में सौंपी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि दिल्ली में बसपा प्रत्याशी के चयन से लेकर रणनीति तक बनाने का जिम्मा उनके हाथों में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही मायावती ने दिल्ली को पांच जोन में बांटकर अपने सिपाहसलारों को जिम्मा सौंप दिया है। बसपा ने सुदेश आर्या, सीपी सिंह, धर्मवीर अशोक, रंधीर बेनीवाल और सुजीत सम्राट जैसे नेताओं को सौंपी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों को बसपा प्रमुख मायावती ने 5 हिस्सों में बांटा है और 5 जोनल प्रभारियों को उन क्षेत्रों की सीट सौंपी है। रंधीर बेनीवाल को हरियाणा बॉर्डर से लगी हुई 10 सीटें सौंपी हैं, जो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के प्रभारी रहे हैं। सुदेश आर्या को 16 सीट दी गई है। जिसमें नांगलोई जिले की और चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र की सीटें शामिल हैं। सुजीत सम्राट को 12 विधानसभा सीटों की कमान सौंपी गई है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी सिंह को तीन विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है और धर्मवीर अशोक को 20 विधानसभा सीटें सौंपी हैं। बसपा के ये पांच नेता दिल्ली में उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उन्हीं के कंधों पर जीत की जिम्मेदारी होगी। बसपा प्रमुख मायावती ने खुद भी 15 जनवरी को लखनऊ से दिल्ली में आकर अपना डेरा जमा लिया है। मायावती ने 15 जनवरी को दिन में लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाया और शाम को वे दिल्ली पहुंच गई। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव तक मायावती दिल्ली में ही रहेंगी। माना जा रहा है कि मायावती के दिल्ली आने के बाद बसपा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। इस बार पार्टी का फोकस महिलाओं और युवाओं पर है। दागी छवि वाले नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। मायावती ने स्वच्छ छवि वाले नेताओं को टिकट देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में यह देखना है कि मायावती के फॉर्मूले को बसपा के दिल्ली जोनल प्रभारी कितना जमीन पर उतार पाते हैं, क्योंकि पार्टी में टिकट वितरण को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं? दिल्ली के प्रभारी नेशनल को-ऑर्डिनेटर आकाश आनंद बनाए गए थे तो माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने का काम भी करेंगे, लेकिन मायावती के द्वारा 5 जोनल प्रभारी बनाए जाने के बाद अब उम्मीदवारों का फैसला आकाश आनंद के हाथों में नहीं रह गया। आकाश आनंद के जिम्मे दिल्ली में बसपा के सियासी माहौल बनाने की कमान सौंपी गई है। बसपा सुप्रीमो के निर्देश पर आकाश आनंद दिल्ली में लगातार जनसभाओं को संबोधित कर बसपा के लिए सिर्फ माहौल बनाएंगे। 5 जनवरी को दिल्ली के कोंडली स्थित अंबेडकर पार्क में आकाश आनंद ने एक रैली से दिल्ली चुनाव अभियान का आगाज किया। बसपा के जनाधार बढ़ाने के लिए डोर-टू-डोर जनसंपर्क अभियान भी चलाने की रणनीति है। दिल्ली में दलित बस्तियों और कॉलोनियों में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर-घर जाकर बसपा की नीतियों के बारे में बताएंगे। संविधान और आरक्षण को लेकर भाजपा व कांग्रेस की राजनीति से जनता को अवगत कराने के निर्देश मायावती ने दिए हैं। ऐसे में साफ है कि आकाश आनंद दिल्ली चुनाव में बसपा उम्मीदवारों का फैसला नहीं करेंगे, लेकिन जीत के लिए उनके पक्ष में माहौल बनाने की जिम्मेदारी होगी। इस तरह आकाश आनंद के सिर फिर कांटों भरा ताज सौंप दिया गया है, जहां पर हार और जीत दोनों का ही श्रेय उनके सिर मढ़ा जाएगा। आम आदमी पार्टी के राजनीतिक वजूद में आने के बाद बसपा दिल्ली की सियासत में गुमनाम हो गई। दलित समाज का विश्वास बसपा के बजाय अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ हो गया। ऐसे में बसपा का सियासी दारोमदार दिल्ली में दलित वोटों पर ही टिका है, जो फिलहाल केजरीवाल का कोर वोटबैंक बना हुआ है। इसीलिए पिछले दिनों डॉ. आंबेडकर पर अमित शाह के द्वारा दिए गए कथित टिप्पणी को लेकर केजरीवाल ने मोर्चा खोल दिया था। अमित शाह के बयान को लेकर बसपा दिल्ली की सड़कों पर उतरी थी। आकाश आनंद ने खुद दिल्ली की सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया था, जिनके निशाने पर भाजपा से लेकर अमित शाह तक थे।

● **रजनीकांत पारे**

बसपा का ट्रैक रिकार्ड

बसपा की दिल्ली की सियासत में एक समय अच्छी-खासी धमक रही है। बसपा के बीस सालों के चुनाव ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो साफ पता चलता है कि एक समय उसका वोट शेयर कैसे 14 फीसदी के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन मौजूदा दौर में एक फीसदी से भी कम है। 2003 में बसपा 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में बसपा एक सीट भी नहीं जीत सकी थी, लेकिन वोट 5.76 फीसदी मिला था। इसी तरह से 2008 के विधानसभा चुनाव में बसपा दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसे दो सीटों पर जीत मिली थी और वोट शेयर 14.05 फीसदी था। बसपा गोकलपुरी और बदरपुर सीट जीतने में कामयाब रही थी। गोकलपुरी सीट रिजर्व सीट थी, जबकि बदरपुर सीट नॉन रिजर्व थी। बसपा ने 2013 के विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जिसमें से एक भी सीट उसे नहीं मिली, लेकिन 5.35 फीसदी वोट शेयर जरूर था। ऐसे ही 2015 के विधानसभा चुनाव में बसपा सभी 70 सीटों पर लड़ी और उसका वोट शेयर घटकर 1.13 फीसदी पर पहुंच गया। इसके बाद बसपा ने 2020 के चुनाव में भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि आप की लहर में पार्टी एक भी सीट जीतने में सफल नहीं रही। उसे मात्र 0.71 फीसदी वोट मिले थे।

खत्म होगा 26 साल का वनवास?

भाजपा पिछले 26 साल से दिल्ली में सत्ता का वनवास झेल रही है। वो विधानसभा चुनाव-2025 में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए उसने पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके बाद भी भाजपा के लिए दिल्ली के सत्ता की राह आसान नहीं है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के बीच शह-मात का खेल शुरू हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा बहाल होने के बाद 1993 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद से राजधानी में सात बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। भाजपा महज एक बार साल 1993 में ही जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 1998 में उसके हाथों से सत्ता गई तो फिर वापसी नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली का दिल भाजपा क्यों नहीं जीत पाती है और 2025 में क्या सियासी ग्रहण को दूर कर पाएगी।

भाजपा पिछले 26 साल से दिल्ली में सत्ता का वनवास झेल रही है। भाजपा 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो सकी। शीला दीक्षित के बाद से 11 साल से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आगे पस्त नजर आई है। अब फिर से दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ गई है। भाजपा 2025 में होने वाले विधानसभा में हर हाल में दिल्ली में कमल खिलाना चाहती है, जिसके लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। इसके बाद भी भाजपा के लिए दिल्ली के सत्ता की राह आसान नहीं है। मोदी-शाह की जोड़ी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा के लिए जीत हासिल करने की गारंटी बन गई थी। ऐसे में देखते ही देखते देश के एक के बाद एक राज्यों में भाजपा अपनी जीत का परचम फहराती रही। उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्वोत्तर राज्यों तक भाजपा की जीत का डंका बजने लगा। भाजपा की जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिया गया लेकिन केंद्र सरकार के नाक के नीचे दिल्ली में 2015 और 2020 में दो बार चुनाव हुए। इन दोनों ही चुनावों में मोदी-शाह की जोड़ी केजरीवाल के सामने अपना असर नहीं दिखा सकी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है, जिसके चलते भाजपा दिल्ली की जंग फतह नहीं कर पा रही?

दिल्ली के सियासी मिजाज को भाजपा समझ नहीं पा रही है। देश के दूसरे राज्यों के फॉर्मूले पर दिल्ली का विधानसभा चुनाव नहीं जीता जा सकता है। दिल्ली जाति और धर्म की सियासत को कभी तवज्जो नहीं देती है। इसके अलावा दिल्ली के लोग नकारात्मक चुनाव प्रचार को अहमियत नहीं देते, क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा तबका कारोबारियों का है। दिल्ली में तीन तरह के चुनाव होते हैं और तीनों में वोटिंग पैटर्न अलग-अलग हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की पसंद भाजपा रही तो विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दौर में भी ऐसा ही था, जब विधानसभा में कांग्रेस को

केंद्र के जरिए दिल्ली को साधने का गणित

केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी दिल्ली की सियासत को वैसे ही डील करती है, जैसा वह चाहती है। कांग्रेस और भाजपा अपने किसी भी नेता को दिल्ली में बहुत ज्यादा स्पेस नहीं देती। दिल्ली में किसी खास नेता को स्पेस देने का मतलब है उसकी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाना और कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ऐसा करना नहीं चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी खुद को पार्टी के अंदर स्थापित किया था। उन्हें पार्टी की तरफ से कोई बढ़ावा नहीं मिला। ठीक उसी तरह भाजपा भी दिल्ली के नेताओं को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती। यही वजह है कि वो केजरीवाल के सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं उतार सकी। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके चलते केंद्र में रहने वाली पार्टी के पास काफी अधिकार हैं। इसीलिए सीधे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के बजाय केंद्र की सत्ता के जरिए समीकरण साधने की कवायद की है। सत्ता में जो भी होता है, उसे दिल्ली की सत्ता की बहुत ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती है, क्योंकि राजधानी की कानून व्यवस्था और मास्टर प्लान बनाने का काम केंद्र सरकार के पास ही होता है।

अखिलेश के कदम से कांग्रेस की बढ़ी टेंशन

अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अखिलेश यादव के उतरने से कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव काफी मुश्किल भरा हो सकता है। कांग्रेस पहले से ही दिल्ली में पिछले दो चुनाव से खाता नहीं खोल सकी और अब 2025 की चुनावी राह में भी कांटे बिछ गए हैं। अखिलेश और केजरीवाल के बीच सियासी केमिस्ट्री बनने के बाद आम आदमी पार्टी यह संदेश देने में सफल होगी कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। अखिलेश के चलते ममता बनर्जी सहित इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी उनके साथ जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए दिल्ली चुनाव आसान नहीं होगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन इंडिया गठबंधन में साइडलाइन होने को लेकर है। कांग्रेस के नेतृत्व करने के सवाल पर इंडिया गठबंधन की कई छोटी-बड़ी पार्टियों ने आपत्ति जताई है। राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर लालू यादव, ममता बनर्जी और अखिलेश खुले तौर पर ऐतराज जता चुके हैं। ऐसे में अगर केजरीवाल और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ीं, तो जाहिर तौर पर नए फॉर्मूले भी बन सकते हैं। अखिलेश की मदद से उप्र में केजरीवाल को फायदा हो सकता है। केजरीवाल की मदद से अखिलेश भी दिल्ली में साइकिल चलाने की कोशिश कर सकते हैं।

कामयाबी मिली थी तो लोकसभा में भाजपा को। एमसीडी चुनाव में पहले भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का है।

दिल्ली के चुनाव में पार्टी से ज्यादा नेता का व्यक्तित्व मायने रखता है। साल 1993 में भाजपा ने मदनलाल खुराना को आगे कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन सिर्फ पांच साल के दौरान भाजपा को तीन बार मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की जनता के बीच भाजपा की तरफ से गलत राजनीतिक संदेश गया और इसका खामियाजा उसे 1998 के चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके बाद से भाजपा दिल्ली की सियासत में अपना कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं कर सकी, जो शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती पेश कर सके। 1998 के चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने वाली शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। शीला दीक्षित ने खुद को कांग्रेस पार्टी के समानांतर खड़ा किया था। दिल्ली में उन्होंने विकास का अपना एक मॉडल बनाया, जिसके दम पर वो 1998 से 2013 तक एकक्षत्र राज करती रहीं। भाजपा इन 15 सालों तक कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सकीं और न ही कभी भी शीला के कद का कोई अन्य नेता उनके सामने खड़ा कर पाई। इसके बाद 2013 में अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने पहली बाजी जीतने के बाद ऐसा खूंटा गाड़ा कि उसे भाजपा नहीं उखाड़ सकी। केजरीवाल के सामने भाजपा ने कई प्रयोग किए, लेकिन चुनौती नहीं खड़ी कर सकी।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो गया है। संघ ने दिल्ली चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। कोशिश ये है कि इससे भाजपा का दिल्ली में रास्ता आसान हो जाए। महाराष्ट्र और हरियाणा के तर्ज पर आरएसएस संगठन दिल्ली चुनाव में भाजपा की मदद के लिए उतरेगा। संघ पूरी दिल्ली में हजारों छोटी-छोटी बैठकें कर लोगों को विकास के मुद्दे पर जागृत करेगा और एक राष्ट्रवादी सरकार के गठन के लिए लोगों को वोट करने के लिए प्रेरित करेगा। संघ और भाजपा के शीर्ष पदाधिकारियों के बीच इसकी तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान आरएसएस ने इसी तरह की रणनीति अपनाई थी। उस चुनाव में ये रणनीति काफी सफल रही थी। अब दिल्ली में भी उसी तरह के प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। इस पहल के लिए एक रोडमैप पार्टी कार्यालय में आरएसएस और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच हुई बैठक में तय किया गया है। इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। इसके तहत मुख्य संगठन के सीधे सामने आने की बजाय अनुषांगिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों को छोटी-छोटी बैठकें करने का निर्देश दिया गया है। इस तरह की बैठकों का आयोजन शुरू हो गया है। इन बैठकों में राष्ट्रीय स्तर के लोगों को बुलाया जा रहा है और उनके साथ सामाजिक महत्व के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की जा रही है। आरएसएस के आला पदाधिकारी के अनुसार इन बैठकों में किसी दल या पार्टी के विषय में बात नहीं हो रही है, बल्कि बैठक में कहा जा रहा है कि वे मतदान करने से पहले राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के विषयों पर जरूर ध्यान रखें। इसके तहत दिल्ली में आरएसएस डेढ़ लाख छोटी-छोटी गोष्ठियां करेगी, हर बूथ में करीब 10 से ज्यादा गोष्ठियां करने की योजना है। देशभर से कार्यकर्ता दिल्ली में डेरा डालेंगे और दिल्ली के सभी 13033 बूथों में जाकर डोर-टू-डोर संपर्क करेंगे। इतना ही नहीं आरएसएस के कार्यकर्ता साढ़े पांच लाख घरों में जाकर भी राष्ट्रवादी सरकार की जरूरत समझाएंगे। इतना ही नहीं संघ के जमीनी कार्यकर्ता भाजपा के वर्कर्स को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं की बैठकों में इस बात का प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस वर्ग की बैठकों में भाजपा के कार्यकर्ताओं को कौन से मुद्दे उठाने हैं। आरएसएस के तमाम कैडर जो उतरेंगे वो सभी मतदान के दिन तक सक्रिय रहेंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के बाद अब अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने की मुहिम में जुट गई है। गत दिनों त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने महिला अदालत का आयोजन किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शिरकत की थी। इस दौरान जिस तरह से अखिलेश और केजरीवाल की सियासी केमिस्ट्री दिखी है, उसे लेकर कांग्रेस की सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है? आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने से इनकार कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव के कदम ताल करने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से दिल्ली के सियासी रण में अलग-थलग पड़ गई है।

● **विपिन कंधारी**

टकराव की राजनीति...

पिछले कुछ समय से इंडिया गठबंधन में उथल-पुथल सी मची हुई है। यह उथल-पुथल सबसे अधिक कांग्रेस को असहज कर रही है। इंडिया गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं, इसका पहला संकेत हाल में तब मिला, जब तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने कहा कि वह गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। उनका यह बयान उस समय आया, जब कांग्रेस अडाणी मामले को लेकर संसद में हंगामा करने में लगी हुई थी।

नए वर्ष का स्वागत अनेक आशाओं के साथ अवश्य किया गया, लेकिन बीता वर्ष बता रहा है कि इस नए वर्ष में टकराव की राजनीति जारी रहेगी। शायद आपसी तल्खी और बढ़ जाए। 2024 राजनीतिक विरासत ही कुछ ऐसी छोड़ कर गया है। वैसे राजनीतिक टकराव की नींव वर्ष 2023 में ही तब पड़ गई थी, जब दो दर्जन विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडाणी के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया, जिनकी साख भाजपा की सबसे बड़ी पूंजी रही है। बीच-बीच में उजागर अंतर्विरोधों के बावजूद इंडिया 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को अकेले दम बहुमत पाने से वंचित करने में सफल भी रहा, पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे मित्रों की बदौलत मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। फिर भी लगातार दो लोकसभा चुनावों में पस्तहाल रहे विपक्ष को संजीवनी तो मिल ही गई। उसका असर भी नई संसद के पहले सत्र में दिखा, जब विपक्ष ज्यादा आक्रामक दिखा, पर फिर समीकरण बदल गए। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में प्रचंड जीत से भाजपा ने विपक्ष के उत्साह की हवा निकाल दी। संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा के आक्रामक तेवर भी लौट आए तो इंडिया गठबंधन में तकरार दरारों में तब्दील होती दिखी। संसद के बीते सत्र में भीमराव आंबेडकर का मुद्दा भी जुड़ गया।

यह तय है कि नए वर्ष में वक्फ बोर्ड और एक देश-एक चुनाव विधेयक पर भी जोर आजमाइश जारी रहेगी और समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भी राजनीति गरमाएगी। इस सबकी छाया वर्ष 2025 पर पड़ेगी ही। आंबेडकर मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान भाजपा-कांग्रेस सांसदों में हुई धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह मामला पिछली लोकसभा में मानहानि मामले में राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति के बाद भाजपा-कांग्रेस में चले टकराव के दूसरे संस्करण का रूप ले सकता है।

भाजपा मामले को कानूनी रूप देना चाहेगी, जबकि कांग्रेस राजनीतिक। हालांकि अडाणी और ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अकेली पड़ती दिख रही है, लेकिन आंबेडकर के मुद्दे को वह फिर गेम चेंजर बनाना चाहेगी। साझा लाभ देखकर इंडिया भी आंबेडकर के मुद्दे पर एक स्वर में बोलता नजर आएगा। इसकी पुष्टि इससे होती है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भगवान का अपमान बताते हुए आंबेडकर के नाम पर स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान कर दिया है। निसंदेह भाजपा भी शांत नहीं बैठने वाली। जाहिर है इस मसले पर टकराव आगे भी देखने को मिलेगा। किसी की प्रतिबद्धता मापने का कोई पैमाना न भी हो, पर ऐसे भावनात्मक मुद्दों के चुनावी दोहन का मौका कोई नहीं चूकना चाहता।

नया साल शुरू होते ही फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। देश की राजधानी में सत्ता की हैट्रिक करने वाली आप चौथी बार जनादेश मांगेगी, जबकि 27 साल से विपक्ष में बैठी भाजपा दिल्लीवासियों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह राजनीतिक शोध का विषय है कि पिछले तीन लोकसभा चुनावों में भाजपा को सभी सात सीटें जिताने वाली दिल्ली उसे विधानसभा

संविधान संशोधन पर रार

अब तक 100 से अधिक संविधान संशोधन यही दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय चुनौतियों के अनुरूप संशोधित होते रहे हैं। झूठे प्रचार के इस खेल में संविधान के साथ मनुस्मृति को लेकर संसद जाना और मनुस्मृति को संविधान के विकल्प के रूप में पेश करने का नाटक अनुचित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आरक्षण के रक्षोपाय संविधान निर्माताओं ने ही पारित किए थे। आवश्यकतानुसार संशोधन भी हुए हैं। आरक्षण की अवधि बढ़ाने का विषय भी संवैधानिक संशोधन से ही जारी है। अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर सभी दलों ने सहमति दी है। तब आरक्षण समाप्त करने के दुष्प्रचार का औचित्य क्या है? सभी सरकारों ने आवश्यकतानुसार संविधान संशोधन कराए हैं। आपातकाल में सारे विपक्षी नेता जेल में थे। उस समय 53 संशोधन एकसाथ हुए थे। संविधान का 42वां संशोधन राष्ट्र की आवश्यकता नहीं था। आपातकाल को वैध ठहराने एवं सत्ता बनाए रखने के लिए यह संशोधन हुआ था। इस संशोधन में न्यायपालिका के अधिकारों में भी कटौती हुई थी। जनता पार्टी सरकार ने संशोधनों के बड़े हिस्से को समाप्त कर दिया था। क्या 2025 में हम अनुकूल एवं सौहार्दपूर्ण परिवेश बनाने में कामयाब होंगे? क्या राजनीति में मर्यादा का पालन होगा? संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने जैसे राजनीतिक झूठ आगे नहीं चलेंगे।

चुनावों में क्यों नकारती रही है? नए साल में दिल्ली के दिल में किसके लिए क्या है, वह तो चुनाव परिणाम बताएंगे, पर यह स्पष्ट है कि भाजपा और आप के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंचेगा। टकराव कांग्रेस और आप के बीच भी बढ़ने वाला है। लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ीं कांग्रेस और आप विधानसभा चुनाव अकेले तो लड़ेंगी ही, एक-दूसरे पर तल्ख आरोप भी लगाएंगी। इसकी शुरूआत हो चुकी है।

दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता अजय माकन ने आप से दोस्ती को गलती मानते हुए केजरीवाल को देश विरोधी करार दे दिया है। आप ने माकन के विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने पर गठबंधन से ही कांग्रेस को बाहर करने के लिए अन्य घटक दलों से बात करने की चेतावनी दे दी है। इंडिया की बदौलत ही 99 सीटों पर पहुंच पाई कांग्रेस के लिए गठबंधन की राह लगातार मुश्किल होती दिख रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसने किसी घटक दल को भाव नहीं दिया तो महाराष्ट्र में बड़ा भाई बन बैठी। ऐसे में हार का ठीकरा सबसे ज्यादा उसी पर फूटा। ममता बनर्जी ने गठबंधन के नेतृत्व के लिए दावेदारी जताई तो शरद पवार से लेकर लालू यादव तक ने उनका समर्थन करने में देर नहीं लगाई।

उप्र के 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट न देकर अखिलेश यादव भी अपनी मंशा जता चुके हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ईवीएम मुद्दे पर कांग्रेस को चुनाव परिणाम स्वीकार करने की नसीहत दे चुके हैं, तो उपमुख्यमंत्री पद मांग रही कांग्रेस से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खुश नहीं दिखे। पिछली बार 70 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 19 सीटें जीतकर गठबंधन में सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई थी। इसलिए 2025 के अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में लालू-तेजस्वी भी उसे हद में रखना चाहेंगे। बेलगावी अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे होने पर वहां आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 2025 को कांग्रेस के सशक्तीकरण का वर्ष बताया है, लेकिन मित्र दलों से उसके बढ़ते टकराव से तो गठबंधन में बिखराव की आशंका गहरा रही है।

साल 2024 की अनेक उपलब्धियां हैं। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वाभिमान बढ़ा है, तो ऐसी उपलब्धियों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार भी हुई है। हालांकि राजनीति में बीत रहे साल बड़ा अवमूल्यन हुआ है। संसद में बहुत कुछ अच्छा नहीं घटा। संसदीय भाषा की कटुता से देश आहत है। इस साल आठ राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। थोक के भाव दल बदल हुए। दल बदल से संबंधित संविधान की दसवीं अनुसूची का पालन नहीं हुआ। अनेक स्वप्न पूरे हुए। अनेक टूट गए। अनेक प्रतीक्षित हैं, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा झूठ संविधान और आरक्षण समाप्ति को लेकर था। विपक्षी दलों ने प्रचारित किया कि भाजपा सत्ता में आते ही संविधान बदलेगी और आरक्षण समाप्त करेगी। भाजपा की तरफ से बार-बार सफाई दी गई कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बेशक राजनीति में सबके अपने सत्य और अपने झूठ होते हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता भी अर्धसत्य या असत्य का सहारा लेते हैं, लेकिन संविधान बदल देने और आरक्षण समाप्त करने संबंधी झूठ निंदनीय हैं। इससे देशभर में भ्रम फैला। संसद में भी यह झूठ बोला गया है। पूरे देश में इसी झूठ को प्रचारित किया गया, जबकि कृषि, जनस्वास्थ्य, रोजगार और ऐसे ही अनेक मुद्दों पर सार्थक विमर्श नहीं हुआ। याद रहे कि संविधान जड़ नहीं है। यह राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तनीय है।

संविधान निर्माताओं ने संशोधन प्रक्रिया भी संविधान में ही लिखी। डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था, जो संविधान से असंतुष्ट हैं, उन्हें सिर्फ दो तिहाई बहुमत प्राप्त करना है। यदि वह वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित संसद में दो तिहाई बहुमत भी नहीं पा सकते तो यह समझ लेना चाहिए कि संविधान के प्रति असंतोष में जनता उनके साथ नहीं है। संशोधन वाला अनुच्छेद-368 ध्यान देने योग्य है। कुछ सामान्य विषयों पर संविधान के उपबंधों का संशोधन संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। ऐसे संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत तो संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधायी सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन प्रत्येक सदन में जाएगा। उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और सदन में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा, लेकिन इसे संविधान का बदलाव नहीं कहा जा सकता है। संविधान बदलने और यथाआवश्यक संशोधन करने में मूलभूत अंतर है।

● **इन्द्र कुमार**

कांग्रेस के लिए कठिनाईयों का दौर

बीते दिनों कांग्रेस की कठिनाई तब और बढ़ गई, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के कुछ कांग्रेसी नेताओं पर आरोप लगाया कि वे भाजपा के साथ मिलकर उसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर इसलिए भड़के, क्योंकि अजय माकन ने केजरीवाल को फर्जीवाल करार देते हुए कहा कि वह उन योजनाओं के जरिए लोगो को धोखा दे रहे हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। अजय माकन ने यह भी कहा कि 2013 में आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर उसकी सरकार बनवाना कांग्रेस की भूल थी। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी से समझौते को भी सही नहीं माना। अजय माकन ने केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी भी कहा। उनके इस बयान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो आम आदमी पार्टी गठबंधन के दलों से यह मांग करेगी कि वे कांग्रेस को बाहर करें। यह हास्यास्पद मांग है, लेकिन इससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के घटकों में तनातनी बढ़ रही है। जब कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था तो यह माना गया था कि यह गठबंधन अपनी वैकल्पिक नीतियों और विचारों के जरिए भाजपा का मुकाबला करने के साथ ही देश को राजनीतिक दिशा देने का भी काम करेगा, लेकिन वह वैकल्पिक विचार देने में असमर्थ रहा। इंडिया गठबंधन अपना कोई प्रभावी दृष्टिकोण अथवा न्यूनतम साझा कार्यक्रम देश के सामने नहीं रख सका। उसने कांग्रेस के नेतृत्व में केवल यह माहौल बनाया कि भाजपा संविधान बदलना चाहती है। ऐसे माहौल के चलते जब कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में 99 सीटें मिलीं और भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई तो ऐसा प्रचारित किया गया, जैसे विपक्षी गठबंधन की जीत हुई है।

नक्सलियों के सबसे बड़े दुश्मन डीआरजी

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में राज्य पुलिस की एक यूनिट के 8 जवान शहीद हो गए। ये जवान डीआरजी या डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का हिस्सा थे, जिन्हें एंटी-नक्सल ऑपरेशन से लौटने के दौरान निशाना बनाया गया। इस टीम का गठन ही खासतौर पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए किया गया था। सालों पहले जब छत्तीसगढ़ सरकार को लगा कि सुरक्षाबल माओवादियों का सफाया करने के लिए काफी नहीं हैं, तो डीआरजी के रूप में राज्य पुलिस में एक नई यूनिट बनाई गई थी।

छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार ने तय किया कि नक्सलियों के बीच से ही एक फोर्स बनाई जाए। यानी इसमें ऐसे लोग शामिल किए जाएं जो नक्सलियों को करीब से जानते हों, क्योंकि ऐसे लोग ही उनके नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। उन दिनों नक्सलियों का नेटवर्क हर गली-मोहल्ले में था। कहीं भी कुछ भी हो, नक्सलियों को तुरंत इसकी खबर मिल जाती थी। नक्सली बड़े-बड़े हमले और नरसंहार करके भाग जाते थे। उन्हें पकड़ना मुश्किल होता था। इसलिए सरकार ने डीआरजी (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) का गठन किया। सबसे पहले इसका गठन नारायणपुर में 2008 में हुआ था। इसके बाद साल 2008 में और जवानों की भर्ती की गई। आखिरी भर्ती 2013 में सुकमा दंतेवाड़ा और बीजापुर में हुई थी। बता दें कि डीआरजी फोर्स में स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाती है। ये युवा स्थानीय भाषा और भौगोलिक स्थिति से परिचित होते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी डीआरजी में भर्ती किया जाता है, ताकि वे अपने पुराने साथियों की रणनीति जान सकें। फिलहाल डीआरजी में करीब 2 हजार जवान हैं। ये लगातार जंगलों में माओवादियों की तलाश करते रहते हैं। जब भी मुठभेड़ होती है, डीआरजी सबसे आगे खड़ी रहती है।

बीजापुर में ताजा हमले को लेकर बस्तर रेंज के आईजी पी सुंदरराज ने बताया, पिछले 3 दिनों से नारायणपुर जिले, दंतेवाड़ा और बीजापुर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था। इस अभियान के दौरान हमने 5 नक्सलियों के शव बरामद किए थे और एक जवान शहीद हो गया था। जब टीम वापस लौट रही थी, तो बीजापुर के अंबेली इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इस हमले में दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि यह नक्सलियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर पिछले दो वर्षों में सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले 26 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे काफिले में एक वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया था, जिसमें 10 पुलिसकर्मी और एक नागरिक चालक की मौत हो गई थी।

देश के विभिन्न नक्सल प्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे शांति देखी जाने लगी है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड आदि में अब पहले की तरह नक्सली हमलों में कमी दर्ज हुई है। मगर छत्तीसगढ़ अब भी नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है। उन पर काबू पाने के लिए राज्य और केंद्र के अभियान लगातार चलाए जाते हैं। इसमें अक्सर नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आती रहती हैं। मगर इससे नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम लगा पाना अब भी चुनौती बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि अगले साल तक नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ के सघन वनों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिए गए हैं। मगर सुरक्षाबलों की कार्रवाई के जवाब में नक्सली भी बड़े हमले करने की साजिशें रचने में कामयाब देखे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुआ ताजा नक्सली हमला इसी का एक उदाहरण है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सुरक्षाबलों के अभियान के जवाब में नक्सलियों ने यह हमला किया। जब दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त दल तलाशी अभियान से वापस लौट रहा था, तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने उनके वाहन पर हमला कर दिया। इसमें 8 सुरक्षाकर्मी और एक वाहन चालक मारे गए।

इस हमले में आईईडी विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इसकी शक्ति आम विस्फोटकों से कई गुना अधिक होती है। सरकार अक्सर दावा करती है कि नक्सलियों का लगभग सफाया कर दिया गया है और अब वे कुछ सीमित इलाकों तक सिमटकर रह गए हैं। मगर यह समझना मुश्किल है कि इतनी चौकसी के बावजूद नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटक किस तरह और कहां से पहुंच पा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में सघन जंगल होने की वजह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान में मुश्किलें आती हैं। उनकी तलाशी और उन पर नजर रखना कठिन है। यही इलाका नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है और सबसे अधिक इसी क्षेत्र में वे सुरक्षाबलों पर हमले करने में कामयाब होते हैं। मगर यह समस्या कोई नई नहीं है। इसके लिए हेलीकाप्टर से टोह लेने की योजना बनी थी। वैसे भी आजकल इतने अत्याधुनिक टोही उपकरण उपलब्ध हैं कि उनसे जंगलों में चल रही गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद अगर नक्सली सुरक्षाबलों की योजनाओं और गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रख पा रहे हैं, विस्फोटक और हथियार हासिल करने में कामयाब हो जा रहे हैं, तो इससे सुरक्षाबलों को अपनी रणनीति में बदलाव की अपेक्षा की जाती है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

2000 के बाद नक्सलवाद में दिखा उभार

1967 से शुरू हुए इस उग्रवाद को कई चरणों में देखा जा सकता है। देश के कई हिस्सों में इसका प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन साल 2000 के बाद से नक्सलवाद का सबसे वीभत्स रूप सामने आने लगा। 1 अक्टूबर 2003 को नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर हमला किया था। इसके बाद आंध्र सरकार ने राज्य में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा था। इसी साल आंध्र प्रदेश में 246 नक्सलियों की मौत हुई थी। हालांकि, इसके बाद कई राज्यों में नक्सलियों ने एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। नक्सल का विरोध करने वालों को निशाना बनाया गया। बम धमाकों के जरिए पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बनाया गया। कई बड़े नेताओं की भी नक्सली हमले में मौत हुई।

महाखेला की तैयारी

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस के फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य की राजनीति तेजी से बदल रही है। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में अभिनंदन देवाभाऊ के बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक गरमाई हुई है। चर्चा है कि समंदर की तरह फिर लौटकर आए देवेंद्र फडणवीस के लिए 2025 का साल काफी नई संभावनाओं वाला है। चर्चा है कि राज्य में अगर सबकुछ ठीक रहा तो एक बार फिर से बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फडणवीस के सिर पर जहां महायुति की जीत का सेहरा बंधा है तो अब विपक्षी दलों की तारीफ ने उनके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बने अभी सिर्फ एक महीना हुआ है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना मे जिस तरह से उनकी तारीफ हुई। उसने राजनीतिक पंडितों के कान खड़े कर दिए हैं। सवाल है क्या अंदरखाने कुछ चल रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषक दयानंद नेने कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी शत्रु और मित्र नहीं होता है बल्कि परिस्थितियां सबकुछ तय करती हैं। आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ा घटनाक्रम हो जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। एक प्रमुख उद्योगपति कथित तौर पर एक ही राजनीतिक परिवार की दो प्रतिद्वंद्वी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी फिर से एकजुट होने की संभावना तलाश रही है। यदि ऐसा होता है, तो निश्चित तौर पर नया खेला होगा, ऐसी स्थिति सरकार में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री के लिए गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने को भी लेकर चर्चा हो रही है। बीच में जब राज ठाकरे से उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे मिली थीं तो सवाल खड़ा हुआ कि भाभी होकर दो भाईयों के टूटे रिश्ते के धागों को वह जोड़ पाएंगी? पिछले दिनों अजित पवार की मां ने खुद ही पूरे परिवार के एकजुट होने से जुड़ा बयान दिया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उन्होंने इसके लिए भगवान से प्रार्थना की है। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बारे में कहा था कि वे हमारे लिए देवता जैसे हैं। इसके बाद सुप्रिया सुले ने जो भी बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि परिवार के तौर पर कोई संघर्ष नहीं है, विचारधारा की चुनौती है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाचा-भतीजे का एक साथ आना मुश्किल हैं लेकिन असंभव नहीं है। महाराष्ट्र चुनावों के दौरान आशा पवार का कहना था कि एक मां होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे अजित को मुख्यमंत्री होना चाहिए। लोगों की तरह मैं भी अजित पवार को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती हूं। आगे क्या होगा, ये तो मैं नहीं बता सकती, देखते हैं। बारामती के सभी लोग हमारे अपने हैं। हर कोई अजित से प्यार करता है। अब देखना यह है सामना में तारीफ के बाद जो सियासत गरमाई है वह कहां तक पहुंचती है।

महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले क्या केंद्र में मंत्री बनेंगी? राज्य की राजनीति में पवार फैमिली के एक होने की अटकलों के बीच यह सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अजित पवार की मां आशाताई पवार ने पिछले दिनों साफ कहा था कि वह चाहती हैं कि पवार परिवार एक हो जाए। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़ों के साथ आने की कवायद पर्दे के पीछे जारी है। अगर यह कोशिश परवान चढ़ती है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। इतना ही नहीं उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। पिछले दिनों यह चर्चा सामने आई थी। राज्य के एक बड़े उद्योगपति की इच्छा के अनुसार एक ही परिवार के दो प्रतिद्वंद्वी पाटियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। चर्चा यह भी है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी, क्यों शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास आठ सांसद हैं, हालांकि अजित पवार की मां आशाताई पवार ने परिवार के एकजुट होने की बात कही थी तब उन्होंने कहा था कि अजित पवार जब तक भाजपा के साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि अजित पवार और शरद पवार का मिलन थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। लोकसभा चुनावों में अजित पवार की पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। जबकि शरद पवार को 10 सीटों पर लड़ने के बाद आठ पर जीत मिली थी। पिछले दिनों जब शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें देवाभाऊ लिखा गया था। उसके बाद सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। सुले ने यहां तक कह दिया था कि वह इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं तो जो राज्य में सक्रिय हैं। सुले ने कहा था कि एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व गृहमंत्री आरआर पाटिल भी गढ़िचरौली जाते थे, ऐसे में फडणवीस का गढ़चिरौली जाना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो। यह कौन नहीं चाहता है। राजनीतिक हलकों में सुले का बयान नए राजनीतिक समीकरण बनने की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है।

● **बिन्दु माथुर**

पवार के सामने है कठिन चुनौती

अगर शरद पवार भाजपा के साथ आते हैं तो उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं विधानसभा चुनावों में अजित पवार की पार्टी को अधिक सीटें मिलने के बाद शरद खेमा काफी दबाव में है। चर्चा यहां तक है कि अगर पवार कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करते हैं तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी फिर से टूट सकती है। एनसीपी के दोनों धड़ों के पास राज्य में 20 फीसदी जितने वोट हैं। शरद पवार खेमे के लिए अगले पांच साल तक बगैर सत्ता के रहना काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) शरद पवार की पार्टी एनसीपी (एसपी) में फिर से फूट डालने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने कहा कि एनसीपी शरद पवार की पार्टी के सांसदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इसके नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का प्रलोभन दिया जा रहा है।

पिक्चर अभी बाकी है...!

राजस्थान की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा है। राजे के समर्थक विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। भाजपा सरकार के एक साल पूरे होने पर यह बदलाव लगभग संभव है। ऐसे में राजे ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। जानते हैं 40 मिनट की इस मुलाकात के बाद कैसे हलचल तेज हो गई। भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर जमकर सियासी हलचल मची हुई है। इस बीच वसुंधरा राजे की दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात से सियासत में हलचल है। इस मुलाकात को मंत्रिमंडल में हो रहे बड़े बदलाव की संभावना से जोड़ा जा रहा है। इधर, पाली में मीडिया से वसुंधरा राजे ने अपनी इस मुलाकात का खुलासा करते हुए बड़ा सियासी संकेत दिया।

जब से वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में मुलाकात करके आई हैं, तब से राजस्थान की सियासत में तेजी से हलचल मची हुई है। उनकी इस मुलाकात को किसी बड़े बदलाव की संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब वसुंधरा राजे से प्रधानमंत्री मोदी की 40 मिनट की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, जो भी हुआ है, अच्छा ही हुआ है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात और मीडिया में दिए गए बयान के बाद सियासत में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इधर, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे काफी आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही हैं। माना जा रहा है कि उनकी इस मुस्कान की छाप अब मंत्रिमंडल के बदलाव में देखने को मिल सकती है। वर्तमान में भजनलाल सरकार में वसुंधरा राजे के खेमे का एक भी विधायक शामिल नहीं है। इस बीच सियासत में चर्चा है कि मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में अब वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों की भी एंट्री हो सकती है। राजस्थान के सियासी गलियारों में भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के उस ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है, जिसमें वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बधाईयां देते नजर आ रहे हैं। ये मौका दिल्ली में वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का था, जिस पर भाजपा नेता की प्रतिक्रिया के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन बाद उन्होंने खुद ही इस पर चुप्पी तोड़ दी है और बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? एक इंटरव्यू में राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, मैं जबसे राजस्थान आया हूं वसुंधरा राजे के साथ काम कर रहा हूं। मैं उन्हें राजस्थान की एक हैसियत और शख्सियत मानता हूं। मैं भाजपा के उस दौर को खराब मानता हूं, जिसमें उनकी सक्रियता कुछ घटी थी। लेकिन आज अगर वो वापस सक्रिय हैं तो यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैंने उन्हें बधाई दी है। वसुंधरा राजे आगे भी राजस्थान की सियासत में सक्रिय बनी रहें इसके लिए मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।

सरकार में होगा फेरबदल

भजनलाल सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस बीच अब मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेजी से सियासत में घूम रही है। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री भजनलाल और भाजपा के चीफ मदन राठौड़ दिल्ली गए, जहां बताया जा रहा है कि उन्होंने 1 वर्ष की मंत्रियों की फीडबैक रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है। इस फीडबैक रिपोर्ट को फेरबदल के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चर्चा है कि भाजपा तीन स्तरों पर बड़े फेरबदल करेगी। इनमें पहला संगठन, दूसरा मंत्रिमंडल और तीसरा नगर निगम बोर्ड के विभिन्न पदों के लिए बदलाव किया जा सकता है।

एक अन्य इंटरव्यू में भाजपा प्रदेश प्रभारी अग्रवाल ने कहा था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की ही सरकार है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर वसुंधरा राजे का पूरा आर्शीवाद है। वे आज भी पार्टी के हर महत्वपूर्ण फैसले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अपने 10 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजे ने प्रशासनिक दृढ़ता और स्पष्टता के साथ काम किया है। वे आज भी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सरकार में तो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी दखल होता है। ऐसे में वसुंधरा राजे का सरकार में दखल ना हो, ये कैसे कहा जा सकता है। राजस्थान में इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं। इसीलिए वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा ने अलग-अलग दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। ऐसे समय पर राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान और ट्वीट यह संकेत दे रहे हैं कि भजनलाल कैबिनेट में वसुंधरा राजे गुट के नेताओं को भी जगह दी जा सकती है। हालांकि प्रदेश भाजपा प्रभारी का कहना है कि यह मुख्यमंत्री का डोमेन है। ये उनका फैसला है कि विस्तार होगा या नहीं होगा। अगर बदलाव होगा तो उसमें कौन-कौन शामिल होगा। राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत में जो भी फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा।

राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीते दिनों ईआरसीपी योजना उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे और उनके रिश्तों को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पिछले कई सालों से राजस्थान की राजनीति में यह बात चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन अचानक भजनलाल शर्मा का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई थी। वसुंधरा राजे समर्थक लगातार इस बात से नाराज है कि मैडम को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की तल्खी की खबरों के बीच 17 दिसंबर को जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई। उसके बाद से यह माना जा रहा है कि भाजपा में सबकुछ ठीक है। जयपुर के दादिया में हुए ईआरसीपी प्रोजेक्ट के कार्यक्रम के बाद एक और तस्वीर सामने आई है, जिससे सियासी हलकों में यह चलने लगा है कि मैडम का रुतबा फिर से बढ़ने वाला है। 17 दिसंबर को ईआरसीपी के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री मोदी की वसुंधरा राजे से मुलाकात हुई तो इसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर छा गई। इसमें प्रधानमंत्री मोदी वसुंधरा राजे आमने-सामने हैं और राजे को देखकर प्रधानमंत्री मोदी मुस्कराकर अभिवादन करते दिख रहे हैं। सियासी गलियारों में इस तस्वीर को मोदी और वसुंधरा के बीच की राजनीतिक दूरी की खबरों पर विराम लगा दिया है। उल्लेखनीय है कि बीते दिन ईआरसीपी को लेकर हुए कार्यक्रम में वसुंधरा राजे के पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर लगातार उनकी चर्चा हो रही है। मंच पर वसुंधरा राजे के पहुंचने का अंदाज और वहां कई दिग्गज नेताओं की ओर से उनके स्वागत अभिनंदन करने के दृश्य के बाद कई लोग अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिख रहे हैं कि मैडम का अभी भी रुतबा कायम है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

नीतीश कुमार का फ्यूचर प्लान...

दिल्ली में अनदेखी

इसी माहौल में पिछले हफ्ते नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा के दौरान हुई कथित अनदेखी की भी खबरें आ गईं। कहा गया कि दिल्ली में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी ने भी वक्त नहीं दिया। हालांकि, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐसी किसी संभावना के पक्ष में नहीं दिखते। उनका फोकस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। इस वक्त नीतीश कुमार के आने की संभावना कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच भ्रम और असमंजस पैदा कर सकती है। यह बात भी ध्यान देने लायक है कि केंद्र सरकार में भाजपा के पास बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार का साथ उसके लिए भी अहम है। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में हैं। इसलिए अभी से केंद्रीय सत्ता का समीकरण बिगाड़ने का विकल्प नीतीश कुमार भी शायद ही चुनना चाहेंगे।

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार नाम का एक ऐसा हीरो या पात्र मौजूद है, जिसके इर्द-गिर्द ही बीते 20 सालों से बिहार की राजनीति घूमती रही है। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए हो या महागठबंधन सभी को नीतीश कुमार की जरूरत महसूस होती है। या यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसा जोड़न है, जिसके बिना दही नहीं जमती है। शायद, यही वजह है कि नीतीश कुमार बीते 18-20 सालों से बिहार की कुर्सी पर चुंबक की तरह चिपक गए हैं। जानकार भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति में फिल्म कोई भी बनाए, लेकिन हीरो का रोल नीतीश कुमार के लिए पहले ही फिक्स हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नए साल में हीरो का रोल नीतीश कुमार निभाएंगे या साइड रोल करने वाले कोई कलाकर बाजी मार ले जाएगा?

बिहार में नए साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद छोड़कर साइड रोल यानी उपमुख्यमंत्री पद के लिए जो मारामारी चलती थी, शायद इस बार न देखने को मिले। क्योंकि, इस बार फिल्म बनाने वालों ने साइड रोल वाला किरदार ही हटा दिया है। ऐसे में देखना है कि नीतीश कुमार का फ्यूचर प्लान 2025 में कैसा रहने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो नीतीश कुमार की राजनीति का सूर्यास्त नजदीक आ गया है। इसकी झलक बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में दिखाई भी देने लगी है। लेकिन, लगता है कि नीतीश कुमार भी हार मानने वाले नहीं हैं। इधर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। तेजस्वी कभी बोलते हैं कि नीतीश कुमार थोड़े ही सरकार चला रहे हैं? दिल्ली में बैठे दो लोग और बिहार में बैठे दो लोग सरकार चला रहे हैं। तो कभी कहते हैं कि नीतीश सरकार टायर्ड और रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पर पहले कभी इस तरह के आरोप लगते थे तो जेडीयू नेता आरजेडी पर जोरदार हमला बोला करते थे। लेकिन, हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के हमले के बाद जेडीयू जोरदार तरीके से आरजेडी या तेजस्वी यादव पर हमला नहीं बोल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या बढ़ती उम्र और बीते कई महीनों से नीतीश कुमार की चुप्पी आरजेडी को मौका दे रही है? क्या वाकई में नीतीश कुमार दो साल पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे? क्या बिहार की सत्ता टायर्ड और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ-साथ राज्य के दो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के हाथों में है? या फिर दिल्ली में बैठे दो बड़े नेता बिहार को चला रहे हैं?

आपको बता दें कि 28 जनवरी 2024 को ही नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में आकर मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसे में तेजस्वी के इस बयान का मतलब क्या है? नीतीश कुमार को नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि वह जब एनडीए में थे तो आखिर घंटों तक उन्होंने भाजपा नेताओं को भनक नहीं लगने दिया था कि वह महागठबंधन में जा रहे हैं। राज्य के उस समय के मौजूदा उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद या फिर दिवंगत सुशील मोदी भी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन, नीतीश कुमार और ललन सिंह ने अचानक राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचकर तहलका मचा दिया। नतीजा कुछ ही घंटे में एनडीए की सरकार गिर गई और महागठबंधन के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में जनवरी 2025 एक बार फिर से नीतीश कुमार और बिहार की राजनीति में क्या अहम साबित होने वाला है? कुल मिलाकर हर नजरिए से नया साल नीतीश कुमार की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाला है। यह भी सत्य है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब उतना साथ नहीं दे रहा है, जितना दो साल पहले दिया करता था। ऐसे में मीडिया में पलटी मारने की लगातार उड़ती खबरों ने बिहार की सियासत को थोड़ा गर्मा तो जरूर दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी भी इस बार नीतीश कुमार को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रही है। बिहार की राजनीति के दो धुरंधर नेताओं की पुरानी केमिस्ट्री ने एक बार फिर से राजनीतिक सुगबुगाहट पैदा कर दी है। जहां राजद और इंडिया ब्लॉक के नेता लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार को फिर से साथ आने का निमंत्रण दे दिया, वहीं नीतीश ने भी सीधे खंडन करने के बजाय इसे हंसकर टाल दिया। इसके बाद कयासबाजी का वह दौर शुरू हुआ, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक राजनीति के सभी धड़ों के कान खड़े कर दिए। समकालीन राजनीति में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं, जो पिछले एक दशक में चार बार पाला बदलकर बिहार की सत्ता में बने रहे हैं। यही नहीं, वह प्रासंगिक भी बने हुए हैं। इसीलिए लालू प्रसाद ने एक बार फिर कहा कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ी बात यह है कि कोई भी प्रामाणिकता के साथ इस संभावना को नकारने की स्थिति में नहीं दिख रहा।

नीतीश को लेकर अटकलों को मजबूती बिहार में एनडीए खेमे के मौजूदा आंतरिक समीकरणों से भी मिल रही है। कुछ ही दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि बिहार में भाजपा के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई जाए। हालांकि जल्द ही उन्होंने इस बयान से किनारा कर लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। यह परसेप्शन पहले से बना हुआ है कि भाजपा बिहार की राजनीति में जदयू और नीतीश कुमार की अनिवार्यता जल्द से जल्द समाप्त करना चाहती है।

● **विनोद बक्सरी**

भारत के लिए चुनौती बना बांग्लादेश

बांग्लादेश में हालात खराब होते चले जा रहे हैं। इसके चलते दक्षिण एशिया में जो परिदृश्य बन रहा है, वह भारत के लिए चिंता का विषय है। पाकिस्तान तो 1947 से ही भारत विरोधी हिंसात्मक कार्रवाई कर रहा है। अफगानिस्तान को भारत ने बहुत आर्थिक मदद दी, परंतु उसका कोई विशेष सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बांग्लादेश को हमने 1971 में स्वतंत्र कराया। शेख हसीना के कार्यकाल में ऐसा लगा कि हमारी पूर्वोत्तर की सीमाएं अब सुरक्षित रहेंगी और इस पड़ोसी देश से अच्छे संबंध बने रहेंगे, परंतु यह अध्याय भी 5 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया, जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया और शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी।

बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन की अगुवाई जमाते इस्लामी, हिजबुत तहरीर और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अलावा कई इस्लामी संगठन कर रहे थे। अमेरिका का एक प्रभावी वर्ग भी आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहा था। लगता है हमारी खुफिया एजेंसी को इस षड्यंत्र की भनक नहीं लगी। बांग्लादेश में इस समय एक अंतरिम सरकार चल रही है, जिसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हैं। तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और विशेष तौर से हिंदुओं पर बराबर आक्रमण हो रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनके घरों में लूटपाट हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार 8 दिसंबर तक हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध 2,200 हिंसात्मक घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें हिंदुओं की हत्याएं भी शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार का ध्यान जब इन घटनाओं की ओर आकर्षित किया जाता है तो वह दलील देती है कि यह हमारा आंतरिक मामला है और घटनाएं सांप्रदायिक नहीं, बल्कि राजनीतिक है। क्या यह अजीब नहीं कि जब किसी देश में मोहम्मद साहब का कार्टून बनता है या कहीं कोई मस्जिद गिर जाती है, तब तो वह मामला वैश्विक हो जाता है और दुनियाभर के मुसलमान उस पर अपना विरोध प्रकट करते हैं, परंतु जब हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं और उनका उत्पीड़न होता है तो यह संबंधित देश का आंतरिक मामला हो जाता है?

बांग्लादेश में कुछ घटनाओं के पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि वहां का अल्पसंख्यक वर्ग ज्यादातर अवामी लीग का समर्थन करता है, पर यह कहना गले के नीचे नहीं उतरता कि उन पर आक्रमण के पीछे सांप्रदायिक दुर्भावना नहीं है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी हाल में ढाका गए और उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में विशेष तौर से मोहम्मद यूनुस से बात की, परंतु स्थिति में कोई परिवर्तन होता नहीं प्रतीत होता, उलटे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के लिए विशेष चिंता के तीन पहलू हैं। पहला तो यह कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। जमाते इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया गया है। पिछली सरकार ने जो कट्टरपंथी जेल में बंद कर रखे थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। अंतरिम सरकार का समर्थन कर रहा हिजबुत तहरीर एक कट्टर इस्लामी संगठन है, जो दुनियाभर में खलीफा का साम्राज्य स्थापित करने में विश्वास करता है। दूसरा यह कि बांग्लादेश का झुकाव ही नहीं, बल्कि लगाव भी पाकिस्तान से होता जा रहा है। मोहम्मद युनूस हाल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से जिस गर्मजोशी से मिले, वह देखने लायक था। पाकिस्तान से समुद्री रास्ते से बांग्लादेश को सामान भी जाने लगा है, जो वर्षों से बंद था। पाकिस्तानी गायक ढाका आमंत्रित किए जा रहे हैं। तीसरा यह कि चीन अब बांग्लादेश में अपना जाल और तेजी से फैला सकता है। उसकी बेल्ट एंड रोड एनिशिएटिव योजना को और गति मिल सकती है। इसके अलावा बांग्लादेश सैन्य सामग्री चीन से खरीदने जा रहा है।

बांग्लादेश की घटनाओं को देखते हुए भारत के समक्ष तीन आशंकाएं उभर रही हैं। पहली यह कि क्या बांग्लादेश में भी अफगानिस्तान की तरह कोई तालिबानी राज्य स्थापित हो जाएगा? दूसरी क्या बांग्लादेश फिर से पूर्वोत्तर के आतंकी-अलगाववादी संगठनों की शरणस्थली बन जाएगा? क्या बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? इस समय वहां हिंदुओं की आबादी 7.95 प्रतिशत है। एक समय वह 20 प्रतिशत से अधिक थी। स्थिति काफी विषम है, परंतु हमें उसका समाधान तो ढूंढ़ना ही पड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि अगर आपके पास आर्थिक और सैन्य शक्ति है तो आप किसी भी देश से निपट सकते हैं। भारत इन दोनों क्षेत्रों में अपनी सामर्थ्य तेजी से बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में कैसी भी सरकार बने, हमें उससे निपटने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं करना है, परंतु उसे यह मालूम होना चाहिए कि अगर उसने कोई भारत विरोधी कार्रवाई की तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

घुसपैठियों के खिलाफ अभियान, आधा-अधूरा समाधान

इन दिनों दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें निकाल बाहर करने का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत अभी तक दस बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी वापस नहीं भेजा जा सका है। कहना कठिन है कि दिल्ली पुलिस का अभियान कब तक जारी रहेगा और कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जा सकेगा, लेकिन यह ध्यान रहे कि पहले भी दिल्ली में इस तरह का अभियान चल चुका है। वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान का अभियान चल निकला है। वहां भी अतीत में इस तरह का अभियान चला था और उसका नतीजा भी ढाक के तीन पात वाला रहा था। यही कहानी असम की भी है, जहां इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की कवायद की जा रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और राज्य ऐसा करें, लेकिन यह तय है कि कुछ राज्य ऐसा नहीं भी करने वाले, जैसे कि बंगाल। इसी तरह झारखंड में भी यह काम नहीं होने वाला। विधानसभा चुनावों के समय झारखंड सरकार ने भाजपा के इन आरोपों का खंडन किया था कि बंगाल के रास्ते भारत में घुस आए बांग्लादेशी राज्य में बस गए हैं।

ANU SALES
CORPORATION
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
Dispensation
Aspiration
We Deal in Pathology
& Medical Equipment
BA200
BioSystems
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar,
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530
Email : ascbhopal@gmail.com

चीन पर कितना भरोसा?

पांच वर्षों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच उच्चस्तरीय वार्ता के बाद द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत मिले। इस वार्ता में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी शामिल हुए। वार्ता की यह पहल पूर्वी लद्दाख और अक्साई चिन सीमा पर 2020 से चले आ रहे सैन्य टकराव को सुलझाने के पश्चात आरंभ की गई है। उस समझौते के तहत चीन ने विवादित क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे हटाया है, जहां उसने भारतीय सेना को गश्त करने से रोका था। सैन्य निकासी के अलावा चीन ने आश्वासन दिया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के मूल हितों और प्रमुख सरोकारों को समझते हुए और ईमानदारी एवं सद्भावना के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। कूटनीतिक सरगर्मियों के मद्देनजर अहम सवाल यही है कि क्या चीन का भारत के प्रति वाकई कोई हृदय परिवर्तन हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो इसका कारण क्या है? बीते 12 वर्षों से चीन पर राज करते हुए तानाशाह राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा पर ध्यान दें तो यह असंभव है कि उन्होंने एशिया और विश्व में चीन के वर्चस्व और विस्तारवाद का सपना रातोंरात त्याग दिया है।

प्रमुख देश कूटनीति नामक उनकी अवधारणा के अनुसार चीन कभी भी अपने वैध अधिकारों और हितों को नहीं छोड़ेगा और पड़ोसी देशों के साथ विवादों में अपनी शक्ति एवं श्रेष्ठता के बलबूते हावी रहेगा। भारत के अलावा एक दर्जन से अधिक देशों के साथ चीन के अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद हैं और इन सभी के प्रति जिनपिंग के शासन में चीन ने दबंग व्यवहार अपनाकर धौंस देना जारी रखा है। ग्रे जोन और सलामी स्लाइसिंग रणनीतियों का उपयोग करते हुए चीन ने पड़ोसियों पर सैन्य एवं आर्थिक दबाव डालकर यही चेष्टा की है कि कमजोर देशों पर चीन की इच्छा थोपी जाए। उनके अतिराष्ट्रवादी चीनी स्वप्न का लक्ष्य एशिया में उस पुराने साम्राज्यवादी युग को पुन: स्थापित करना है, जहां चीन का कथित तौर पर प्रभुत्व था और पड़ोसियों को बीजिंग में सम्राट के सामने झुककर प्रणाम करना पड़ता था। शी जैसे कट्टर निरंकुश नेता का इतने भव्य एवं महत्वाकांक्षी स्वप्न को भुला देना नामुमकिन है। चीन को केवल महाशक्ति बनाना ही नहीं, बल्कि अमेरिका को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने और चीनी मूल्यों पर आधारित नई विश्व व्यवस्था कायम करने जैसे लक्ष्यों को साधने के लिए वह कोई कोर-कसर नहीं छोड़ने वाले। हालांकि उनकी यह राह आसान नहीं होगी। अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी चीन की इस राह में कांटे बिछाने के लिए पुरजोर प्रयास करेंगे। यह कोई संयोग नहीं है कि चीन ने भारत समेत जिन एशियाई देशों के साथ स्थलीय और समुद्री सीमाओं से जुड़े विवाद नहीं निपटाए, उनकी अमेरिका के साथ गलबहियां बढ़ी हैं। असल में चीन को संतुलित करने की दृष्टि से ही इन देशों का झुकाव अमेरिका की ओर बढ़ा है, जिससे चीन और चिढ़ता है। चीन यह चाहता है कि सीमाओं पर दबाव घटाने के बदले पड़ोसी देश अमेरिका से किनारा करें या अमेरिका के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उसके लिए मुश्किलें पैदा न करें। इसका अर्थ है कि पड़ोसियों को अपनी विदेश नीति स्वतंत्रता और सामरिक स्वायत्तता को सीमित करना होगा और चीनी प्रभुत्व वाली क्षेत्रीय व्यवस्था को स्वीकार करना होगा। इस प्रकार की शर्त किसी भी स्वाभिमानी देश विशेषकर भारत जैसी उभरती महाशक्ति को कतई स्वीकार्य नहीं हो सकती। अजीत डोभाल और वांग यी के बीच हालिया वार्ता विवादित सीमा प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक है और यह सिलसिला बिना किसी अंतिम सहमति के वर्ष 2003 से निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त, सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 2012 से अब तक 32 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें भाग लेने वाले भारतीय वार्ताकारों और राजनयिकों का मानना है कि चीन इस विवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का इच्छुक नहीं दिखता और वह भारत की ओर से प्रस्तुत किए गए मानचित्रों की बारीकियों में भी नहीं जाता। चीन लगातार थकाऊ वार्ताओं के माध्यम से संघर्ष को प्रबंधित करने का प्रयास करता है, परंतु अपने क्षेत्रीय दावों को नहीं छोड़ता।

वर्ष 2020 में गलवन घाटी में मुठभेड़ और उसके बाद करीब साठ हजार सैनिकों एवं भारी-भरकम हथियारों की तैनाती चीन को खासी महंगी पड़ी। भारतीय सेना ने जिस मुस्तैदी के साथ जवाबी कार्रवाई की और अतिरिक्त चीनी घुसपैठ के लिए सभी रास्ते बंद कर दिए, उसने शी की चिंताएं बढ़ा दी थीं। अमेरिका के साथ भारत की सामरिक साझेदारी भी बीते कुछ वर्षों के दौरान जिस प्रकार मजबूत होती गई, उसने भी चीन के माथे पर बल डालने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सत्ता में वापसी और उनके द्वारा छेड़े जाने वाले संभावित व्यापार युद्ध और सैन्य चुनौती भी शी की आशंका का कारण है। इसलिए और भी, क्योंकि चीन की आर्थिक वृद्धि सुस्त पड़ गई है। ऐसे में, भारत के प्रति नरम रवैये का प्रदर्शन कर शी चीन के लिए थोड़े समय के लिए सामरिक राहत की खोज में होंगे।

● **कुमार विनोद**

अमेरिका की मित्रता भारत के उत्थान के लिए अनिवार्य

देपसांग और देमचोक से चीनी सेना की वापसी शी की नाकामी का परिचायक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि उनके जैसे महत्वाकांक्षी तानाशाह आसानी से हार नहीं मानते। चीन भारत को झुकाने का इरादा तब तक मन में रखेगा, जब तक वह आश्वस्त न हो जाए कि भारत अमेरिका के संग मिलकर उसकी घेराबंदी करना नहीं छोड़ता। चूंकि अमेरिका की मित्रता भारत के उत्थान के लिए अनिवार्य है, इसलिए चीन के साथ भारत की अनबन और प्रतिस्पर्धा में कमी की अपेक्षा अवास्तविक है। भारत-चीन वार्ता के दौर सीमा पर उल्लंघित नियमों को बहाल करने में कमोबेश मददगार हो सकते हैं, लेकिन भू-राजनीतिक स्तर पर मैत्रीपूर्ण संबंध की संभावना दूर की कौड़ी है। जब तक चीन भारत के महाशक्ति बनने में अड़चनें डालता रहेगा, उससे दोस्ती की अपेक्षा काल्पनिक बनी रहेगी। कूटनीतिक बैठकों के समानांतर भारत को अपनी सैन्य तैयारियों और क्षमताओं को उन्नत करते हुए चीन से सतर्क रहने की नीति पर ही चलना होगा।

बच्चों पर रीति-रिवाज न थोपें

छोटी उम्र में बिना तर्क के बच्चों पर परंपराओं व रीति-रिवाजों को थोपना अंधविश्वासी बनाता है। इस से बच्चों की तर्कशीलता कमजोर होती है और वे रुढ़िवादी बनते हैं। 16 साल का सुगम परीक्षा देने जाने से पहले भगवान के सामने दीया जलाए और माथे पर तिलक लगाए बिना एग्जाम देने नहीं जाता। उस का विश्वास है कि ऐसा करने से उसकी परीक्षा अच्छी जाएगी और वह अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। परीक्षा के समय शुभ शगुन के लिए वह अपनी मां के हाथ से दहीचीनी भी जरूर खाकर जाता है। उसकी मां ने बचपन से जो भी रीति-रिवाज सिखाए हैं, उनका वह पूरी तरह से पालन करता है।

अक्सर अभिभावक अपने बच्चों को सुशासित बनाने के लिए तरह-तरह के दबाव उन पर डालते हैं। इससे बच्चे और बिगड़ जाते हैं।

26 साल की तिथि कॉर्पोरेट जॉब करती है। उसके घर में बहुत सारे नियम-कानून बने हुए हैं, जैसे कि गुरुवार को बाल नहीं धो सकते, नाखुन नहीं काट सकते। शनिवार को नॉनवेज नहीं खा सकते वगैरह। तिथि को इस बात से बहुत चिढ़ होती है कि ये सब क्या है। क्यों वह गुरुवार को अपने बाल नहीं धो सकती और शनिवार को नौनवेज नहीं खा सकती? लेकिन न चाहते हुए भी उसे वह सब करना पड़ता है। कहें तो ये सारे रीति-रिवाज उस पर जबरन थोपे गए हैं। परीक्षा देने जाते समय अतुल की बहन ने जब उससे आवाज लगाकर रुकने को कहा, तो वह अपनी बहन पर यह कहकर बरस पड़ा कि उसने उसे पीछे से क्यों टोका। अब देखना उसका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। और हुआ भी वही, अतुल का एग्जाम अच्छा नहीं गया। कारण जो भी रहा हो पर परीक्षा के अच्छा न होने का सारा इल्जाम उसने अपनी बहन पर लगा दिया कि उसने पीछे से टोका, इसलिए वह फेल हो गया।

अब यह तो कोरा अंधविश्वास ही है। फेल तो वह इसलिए हुआ क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। मगर सारा दोष उसने अपनी बहन पर मढ़ दिया कि उसके पीछे से टोकने के कारण वह फेल हो गया। वैसे, यह सीख अतुल को अपने पापा से ही मिली है। बाहर जाते समय जब कभी उसकी मां उसके पापा को पीछे से टोक देतीं तो वे यह कहकर गुस्सा हो जाते थे कि लो, पीछे से टोककर अपशगुन कर दिया न। अतुल ने जो भी सीखा अपने माता-पिता से ही सीखा। 23 साल की निधि कहती है कि उसकी मां बेमतलब के रीति-रिवाजों को बहुत मानती है और उस पर भी ऐसा करने का दबाव बनाती है। जब भी वह मासिकधर्म में होती है, उसे किचन से दूर कर दिया जाता है। यहां तक कि वह घर के पुरुषों के सामने तक नहीं जा सकती है। उनका कहना है कि तुम, बस, एक कोने में पड़ी रहो। अजीब-अजीब सी शंकाएं पाल बैठी हैं। निधि कहती हैं कि डर लगता है मुझे कि कहीं आगे चलकर मैं भी अपनी मां की जैसी न बन जाऊं।

बिहार के मिथिला क्षेत्र, जिसे सीता माता का मायका कहा जाता है, आज भी नई बहू के आने पर उसके घुटने को जलती रूई की बाती से दागा जाता है। इन रीति-रिवाजों और परंपराओं को लोग जानने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा करने के पीछे कारण क्या है। बस, पीढ़ी-दर-पीढ़ी वे निभाते चले आ रहे हैं। बेमतलब के बहुत से रीति-रिवाज हमारे भारतीय परिवारों में देखने को मिलते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता। एक अध्ययन में यह बात सामने आ चुकी है कि लगभग 8 वर्ष तक बच्चे का दिमाग काफी तेज दौड़ता है। उसे जो बताया जाए, वह बहुत अच्छे से सीखता है और पूरी जिंदगी उसी का अनुसरण करता है।

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड बिहेवियोरल साइंसेज में छपे एक लेख में कहा गया है कि अंधविश्वास और रीति-रिवाज की जड़ें हमारी प्रजाति की युवावस्था में हैं। संपत्ति के साथ माता-पिता अपने बच्चों को रीति-रिवाज और परंपराएं भी सौंपते हैं। लेकिन इन परंपराओं के पीछे क्या तर्क है, वे यह नहीं बताते। हमारे समाज में और भी बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो हमारी संस्कृति, तरक्की और विकास पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। रीति-रिवाज और परंपराएं तर्क को दबा देती हैं जिससे रूढ़िवादिता बढ़ती है। सतीप्रथा और बालविवाह जैसी प्रथाएं रूढ़िवादिता के कारण लंबे समय तक जारी रहीं। कई धर्मों में पशु-पक्षी की बलि की परंपरा आज भी जारी है। महिला जननांग विच्छेदन की प्रथा अभी भी कुछ समुदायों में प्रचलित है। जाति के नाम पर ऑनर किलिंग आज भी हो रही है। आज भी कुछ स्थानों पर रीति-रिवाजों और पवित्रता के नाम पर जातिगत भेदभाव जारी है। धर्म और रीति-रिवाज के नाम पर आज भी कुछ जगहों पर देवदासी प्रथा कायम है। रीति-रिवाजों के नाम पर बच्चों को अंधविश्वासी बनाना गलत है। अंधविश्वास किसी व्यक्ति या समाज की तार्किक सोच और विज्ञान से दूर रखने वाला है और यह बच्चों के मानसिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है।

● **ज्योत्सना**

रीति-रिवाजों और अंध-विश्वास में जकड़े लोग

माता-पिता को चाहिए कि बच्चों पर रीति-रिवाज न थोपें, बल्कि उन्हें तर्क से समझाएं, ताकि वे खुद सोच सकें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपना सकें और सही-गलत के बीच फर्क कर सकें। जब बच्चों को अंधविश्वास में फंसाया जाता है, तो उनकी मननशीलता, सोचने की क्षमता और स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति दब जाती है। रीति-रिवाज और अंधविश्वास में जकड़े लोग अपनी जिंदगी में बहुत सी बेड़ियां खुद डालते हैं। उनमें विश्वास की कमी आ जाती है। वे डर और भ्रम में जीने लगते हैं, जो उनके मानसिक विकास के लिए ठीक नहीं है। इसलिए बच्चों को सही ज्ञान, तर्क और सोचने की आजादी देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे समझदारी से अपनी दुनिया को देख, परख सकें और बेमतलब के रीति-रिवाजों से बचे रह सकें।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

शर्मिंदा

रेलवे स्टेशन के बाहर सुनील बस स्टैंड जाने के लिए किसी आटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था। तभी एक आटो रिक्शा वाला तीस रुपए में बस स्टैंड जाने के लिए तैयार हो गया। सुनील ने अपने दो भारी-भरकम बैग आटो रिक्शा में रखे और स्वयं भी आटो रिक्शा में सवार हो गया। आटो रिक्शा में सुनील अकेला ही था, किसी अन्य सवारी को नहीं आता देख उसने अपने एक बैग को आटो रिक्शा की सीट पर ही रख दिया था, ताकि पैरों में सामान आने से उसे आटो रिक्शा में बैठने से कोई दिक्कत-परेशानी न हो। यह सर्दी का मौसम था और सुनील ने अपने चेहरे को मफलर से ढक रखा था।

आटो रिक्शा वाला सुनील के अलावा अभी भी एक अन्य सवारी के इंतजार में ही था कि थोड़ी देर में एक लंबे व्यक्ति ने जो कि कंबल ओढ़े हुआ था, बस स्टैंड जाने के लिए उसी आटो रिक्शा को रुकवाया। आटो रिक्शा वाले ने आटो में उस व्यक्ति को बिठाया और गंतव्य की ओर चल पड़ा। लंबा व्यक्ति जिसने मोटा कंबल ओढ़ रखा था, आटो रिक्शा में उस साइड में बैठ गया, जिधर सीट पर सुनील का सामान से भरा हुआ भारी-भरकम बैग रखा हुआ था। आटो रिक्शा में सवार होते ही कंबल ओढ़े हुए उस व्यक्ति ने अपना दांया हाथ तेजी से बैग के ऊपर रख दिया और संभल कर बैठ गया।

इधर, आटोरिक्शा लगातार गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था कि तभी सुनील ने आटो रिक्शा में बैठे उस व्यक्ति की ओर देखते हुए थोड़ा गुस्से में कहा- भाईसाहब! जरा ध्यान से बैठें और हां बैग के ऊपर अपना भारी हाथ न रखें, दरअसल बैग में बच्चों के लिए कुछ टूटने वाला कीमती सामान रखा हुआ है और आपके हाथ के वजन से इसमें रखा सामान टूट सकता है। कंबल ओढ़े हुए वह व्यक्ति सुनील की इतनी बात सुनकर एकदम सकपका गया और उसने सुनील से कहा- ओह! भाईसाहब मुझसे गलती हो गई! मुझे नहीं पता था कि इसमें आपका कुछ टूटने वाला कीमती सामान रखा हुआ है। दरअसल, वो क्या है कि मेरा एक ही हाथ है न! आटो रिक्शा जब ऊबड़-खाबड़ सड़क पर तेजी से सरपट दौड़ता है न, तब कोई भी एकदम से आटो रिक्शा में अपना बैलेंस नहीं बन पाता है न, इसलिए थोड़ा सहारा लेने के लिए, भूलवश मैंने आपके सामान से भरे बैग पर अपना हाथ रख दिया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं शर्मिंदा हूं। उस व्यक्ति की यह बातें सुनकर सुनील उसे एकटक देखता ही रह गया। दरअसल, सुनील ने कंबल ओढ़े व्यक्ति को आटो रिक्शा में बैठते समय एकबारगी देखा जरूर था, लेकिन कंबल ओढ़े रहने के कारण उसे इस बात का अहसास ही नहीं हुआ था कि जो व्यक्ति आटो में उसके साथ बैठा था, उसका एक ही हाथ था। सुनील अब मन ही मन अपने-आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था।

- सुनील कुमार महला

नासूर

योगिता को अच्छी ससुराल मिली। हरीश के रूप में मन-माफिक नौकरीपेशा पति मिला। शादी के सालभर बाद मां बन गई। सबकुछ बढ़िया ही बढ़िया! परिवार बड़ा और संयुक्त था। सबके साथ सब कुछ अच्छा हो; जरूरी तो नहीं। हरीश का चचेरा भाई था नरेश। पढ़ा-लिखा तो था; पर बेरोजगार। उसे सरकारी नौकरी की चाहत थी। बेचारा हाथ-पांव मारता; पर सब व्यर्थ। उसकी बेकारी पर अक्सर योगिता फब्तियां कसती थी- क्यों नरेश! आजकल तुम्हारा इधर-उधर बहुत आना-जाना होता है।

क्या बात है भाई! नौकरी मिली? नौकरी मिलेगी, तब छोकरी मिलेगी। लगे रहो नरेश भाई।

नरेश योगिता को कभी मजाकिया लहजे में जवाब देता, तो कभी चुप रह जाता; पर बातें अंतस को लगती थी। हरीश को नरेश के प्रति योगिता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। समझाया एक दिन उसने- योगिता! नरेश की बेकारी की तुम खिल्ली मत उड़ाया करो।

क्यों..? बस मजाक ही तो करती हूं। योगिता तपाक से बोली।

नरेश को बहुत दु:ख लगता है तुम्हारा मजाक करना। मैं अच्छी तरह जानता हूं। हरीश ने कहा।

तुम्हें कैसे पता? योगिता बोली।

घायल की गति घायल जानता है। बेकारी शरीर के नासूर से अधिक पीड़ादायक होती है। एक लंबी सांस खींचते हुए हरीश ने कहा।

- टीकेश्वर सिन्हा 'गब्दीवाला'

मुझ सा नहीं होगा...

दिल पर चाहतों का वो असर
मुझ सा नहीं होगा
मिलेंगे लाख तुमको कोई मगर
मुझ सा नहीं होगा
भले ही और लोगों में
बहुत सी खास बातें हों
मगर दिल जीत लेने का हुनर
मुझ सा नहीं होगा
माना तुम भी लड़ते जा रहे
अपने मुकद्दर से
बेरंग जीवन का सफर
मुझ सा नहीं होगा
भले अरबों में होगा मोल
तेरी इस हवेली का
फिर भी कभी तेरा ये घर
मुझ सा नहीं होगा
ये सच है दौलतों का
एक खजाना पास है तेरे
पर तेरा दिल, तेरा जिगर
मुझ सा नहीं होगा
जिधर नजरें तुम्हारी हैं
उधर है स्वार्थ का डेरा
जज्बा कर गुजरने का उधर
मुझ सा नहीं होगा
भटकते हैं भले सब लोग
आकर इस जमाने में
गम में चूर, कोई दर-बदर
मुझ सा नहीं होगा
खबर मिलती नहीं कोई मुझे
अब इस जमाने की
मोहब्बत में कोई भी बेखबर
मुझ सा नहीं होगा
चाहो तो खुशी से ढूंढ़ लो
लेकर दिया भी तुम
जमाने में कोई भी हमसफर
मुझ सा नहीं होगा...

- विक्रम कुमार

लगन, मेहनत से महान बने रविचंद्रन अश्विन

बिशन सिंह बेदी, वीनू मांकड़, ईरापल्ली प्रसन्ना, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम हर दौर में महानतम फिरकी गेंदबाजों से सजी रही है। आधुनिक समय के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इस प्रथा को आगे बढ़ाने में भी कामयाब रहे और एक शानदार विरासत छोड़ने में भी। अश्विन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अपने करियर में कई बार बल्लेबाजों को कैरम बॉल से छकाने वाले खिलाड़ी ने इस बार अपने प्रशंसकों और क्रिकेट जगत को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रिकेट की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं, जो खेल प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन ऐसा ही नाम हैं।

रविचंद्रन अश्विन का जन्म 17 सितंबर 1986 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाले अश्विन के पिता रविचंद्रन तेज गेंदबाज थे। यही अश्विन के क्रिकेट के प्रति लगाव का कारण भी बना। क्रिकेट खेलने के साथ-साथ उनका पढ़ाई पर भी ध्यान था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अश्विन ने सूचना प्रौद्योगिकी में डिग्री ली। अश्विन का बचपन क्रिकेट के प्रति जुनून से भरा था। अश्विन हमेशा से एक गेंदबाज बनना नहीं चाहते थे। शुरुआती दिनों में वे बल्लेबाजी करते थे। समय के साथ उनकी पहचान ऑफ-स्पिन गेंदबाज के रूप में बनी। अश्विन की खासियत है कि वे गेंदबाजी के साथ-साथ अपनी रणनीति से भी बल्लेबाजों को खूब चकमा देते हैं।

तमिलनाडु की रणजी टीम में जगह बना पाना बड़ी चुनौती मानी जाती है। ऐसे में अश्विन के लिए पहला पड़ाव घरेलू क्रिकेट में एंट्री करना था। हालांकि, कड़ी मेहनत से उन्होंने यह भी जल्द ही हासिल कर लिया। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और इसी तरह 2010 में उन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। अश्विन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया और 2 विकेट झटके। इसके बाद इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने चेन्नई को आईपीएल जिताने में भी मदद की। फिर 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिसमें धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए कुल 9 विकेट चटकाए। पहली पारी में 3 और दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर उन्होंने सबको हैरान कर दिया। इस मैच के लिए अश्विन को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।

अश्विन ने अपने 14 साल लंबे क्रिकेट करियर में भारत की 2011 विश्वकप जीत और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी खिताबी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अश्विन ने 116 वनडे मैच खेले, जिसमें 156 विकेट लिए और 65 टी20 मैच खेले, जिसमें 72 विकेट लिए। हालांकि, टेस्ट में अश्विन के रिकॉर्ड स्वर्णिम युग की कहानी बयां करते हैं। अश्विन का टेस्ट करियर उपलब्धियों और रिकॉर्ड्स से भरा हुआ रहा है। वह न केवल भारत के बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ ऑफ-स्पिनरों में से एक हैं। उन्होंने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेलकर अनिल कुंबले के बाद भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों की सूची में खुद को शुमार किया। अश्विन की गेंदबाजी की विविधता और बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण पारियों ने उन्हें एक पूर्ण ऑलराउंडर के रूप में स्थापित किया।

रविचंद्रन अश्विन की महानता का अंदाजा इस बात से लगता है कि उन्हें 2016 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला था, जो साल विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के लिए जाना जाता है। अश्विन ने 2016 में 12 टेस्ट मैच खेले और 72 विकेट लेकर साल के सबसे सफल गेंदबाज बने। बल्लेबाजी में भी अश्विन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, उन्होंने 43.71 के औसत से 612 रन बनाए, जिसमें 2 शतक शामिल थे। भारत के सबसे महान स्पिनरों में से एक अश्विन को साल 2014 में प्रतिष्ठित अर्जुन अवॉर्ड से भी नवाजा गया। अश्विन के बारे में उनके तमिलनाडु के साथी अभिनव मुकुंद कहते हैं कि आज जिस मुकाम पर अश्विन हैं, ये केवल उनकी मेहनत का नतीजा है। बकौल अभिनव, अश्विन प्रतिभा के साथ पैदा नहीं हुए थे लेकिन क्रिकेट के प्रति जुनून और उनके परिश्रम ने आज अश्विन को खेल का महानायक बना दिया।

अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में भी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स जैसी टीमों के लिए खेलते हुए कई यादगार प्रदर्शन किए। आने वाले सीजन में उनकी घर वापसी हो रही है। अश्विन ने कहा भी है कि वह अभी और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अश्विन का करियर केवल उपलब्धियों और खुशी के पलों से ही भरा नहीं रहा है। उन्होंने कई संघर्षों का भी सामना किया। सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनकी जगह, उनकी फिटनेस पर सवाल उठाए गए। 2017 के बाद उन्हें वनडे और टी20 टीम से बाहर कर दिया गया। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपने प्रदर्शन से हर बार आलोचकों को गलत साबित किया। अश्विन की पत्नी ने उनके लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा भी है कि वे हमेशा पहले से बेहतर होने के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने अपनी तकनीक पर लगातार काम किया और खुद को अनोखा खिलाड़ी साबित किया। उनकी कैरम बॉल, फ्लिपर जैसी गेंदें विश्व के अनेक बल्लेबाजों को आज भी डराती हैं।

रविचंद्रन अश्विन का जीवन केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। वह अच्छे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। उनके प्रशंसक, तो यहां तक मानते हैं कि अश्विन में अंपायर बनने के सारे गुण हैं। न केवल गेंदबाजी-बल्लेबाजी, बल्कि नियमों की अच्छी समझ अश्विन को क्रिकेट में इतना सम्मान दिलाने का कारण रही है। खुद पर विश्वास और अपने खेल के प्रति सच्ची लगन ने उन्हें आज इस मुकाम तक पहुंचाया। अश्विन काफी समय से यूट्यूब पर भी सक्रिय हैं। वह अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर युवाओं को भी प्रेरित करते रहते हैं। गाबा टेस्ट के बाद अश्विन के संन्यास की घोषणा दुनिया के लिए भले अचानक घटने वाली घटना हो, लेकिन अश्विन पहले से यह सब प्लान कर चुके थे। इस घोषणा में न्यूजीलैंड से घर में मिली करारी शिकस्त का दुख भी था और एक बेहतरीन करियर के समाप्त होने की मायूसी भी। अश्विन ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी गेंदबाजी ने कई बार भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। वह सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा हैं, जिन्होंने दिखाया कि मेहनत और धैर्य से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कैसे एक खिलाड़ी हर काम में अव्वल हो सकता है, कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का अपनी जिद, समर्पण, मेहनत और दिमाग से क्रिकेट के खेल का महान खिलाड़ी बन सकता है। अश्विन की कहानी अपने आप में अद्भुत है।

● **आशीष नेमा**

10वीं क्लास में ऐसा क्या हुआ था, जो बुरी तरह टूट गईं ऐश्वर्या राय, फूट-फूट कर बहाए थे आंसू

ऐश्वर्या राय हमेशा चर्चा में रहती हैं। सालों से वे इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। फैंस उनसे जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात जानना चाहते हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐश्वर्या राय से जुड़ा दिलचस्प किस्सा। ये किस्सा तब का है जब ऐश्वर्या स्कूल में थीं। पढ़ाई कर रही थीं। सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक्ट्रेस फूट-फूट कर रोईं। पर आखिर क्यों?

बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज थीं। ऐश्वर्या राय भी हमेशा टॉप करती थीं। उन्होंने इस बारे में साल 2000 में दिए एक इंटरव्यू में बताया था। वो स्कूल में हेड गर्ल थीं। हर कोई उनकी तारीफ करता था। पढ़ाई-लिखाई के लिए ऐश्वर्या के माता-पिता ने कभी उन पर प्रेशर नहीं बनाया। पर फिर भी वो हमेशा टॉप करती थीं। लेकिन जब वो 10वीं क्लास में पहुंची तो ऐसा नहीं हुआ। सभी ने सोचा था कि ऐश्वर्या ही टॉपर होंगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। 10वीं क्लास में ऐश्वर्या की 7वीं या 8वीं रैंक आई थी। जैसे ही ऐश्वर्या को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इतना कि वो फूट-फूटकर रोने लगीं। इसे देख ऐश्वर्या के दोस्तों और पैरेंट्स ने उनकी मदद की। 12वीं क्लास में ऐश्वर्या को पीसीबी में 90 प्रतिशत नंबर आए थे। इन नंबरों से एक्ट्रेस को बॉम्बे के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला।

किस स्कूल से की थी ऐश्वर्या ने पढ़ाई?

विद्या मंदिर हाई स्कूल से ऐश्वर्या ने स्कूलिंग की। जय हिंद कॉलेज और डीजी रुपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में भी उन्होंने एडमिशन लिया। लेकिन वो कॉलेज ड्रॉपआउट हैं। ऐश्वर्या ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इसके 3 साल बाद 1997 में तमिल फिल्म इरुवर में एक्ट्रेस को देखा गया था। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म और प्यार हो गया रिलीज हुई।

माधुरी दीक्षित का नाम सुनते ही चौंक गए थे अनिल कपूर, फिल्म ने रच दिया था इतिहास

साल 1992 में आई फिल्म बेटा की रिलीज से पहले काफी बवाल हुआ था। फिल्म में रिलीज से पहले काफी बदलाव भी किए गए थे। लेकिन अनिल कपूर को जब बदलाव के बाद माधुरी के बारे में बताया गया तो उनके होश ही उड़ गए थे। फिल्म के निर्देशक इंद्र कुमार ने एक यूट्यूब टॉक शो पर खुली बातचीत में खुलासा किया था कि, जब मैंने बेटा का पहला हिस्सा देखा, तो मैंने सोचा था कि फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। मैं संतुष्ट नहीं था। लोगों को भी इस फिल्म की सफलता पर शक था। लेकिन इस फिल्म में रिलीज से पहले काफी बदलाव किए गए थे। इन बदलावों के बाद बड़ी चुनौती अनिल कपूर को बदलावों के बारे में बताना था, खासकर जब नई स्क्रिप्ट माधुरी दीक्षित के किरदार पर ज्यादा फोकस हो गई थी। कहानी सुनने के बाद अनिल कपूर ने स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है? बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी तो तुमने बैंड ही बजा दी। अब फिल्म का नाम बेटी रख देंगे, बेटा नहीं। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट होगी। फिल्म में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ने कमाल का काम किया था। इतना ही नहीं उस दौर में अनिल कपूर और माधुरी की जोड़ी बेस्ट जोड़ी बन गई थी।

मनोज बाजपेयी को देख खौफ में आ गई लड़की, भीखू म्हात्रे से है जुड़ा किस्सा

मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या मनोज बाजपेयी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इसमें वह भीखू म्हात्रे के किरदार में नजर आए थे। हाल ही में मनोज बाजपेयी ने बताया कि कैसे उन्होंने आइकॉनिक रोल को निभाने के लिए मानसिक तौर पर तैयारी की थी। एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी ने बताया मैं एक शॉप में एंटर कर रहा था और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय कोई बाहर आ रहा है, कांच का दरवाजा था और मैं बस धड़धड़ाते हुए शॉप में घुस गया। मैं अपने दिमाग में एक गैंगस्टर की तरह जी रहा था क्योंकि मैं हमेशा सोचता रहता था। मैं सिर्फ भीखू म्हात्रे के बारे में ही सोच रहा था। उन्होंने आगे कहा, जब मैं अंदर जा रहा था तो एक लड़की से टकरा गया, जो शॉप से बाहर आ रही थी। उसने कहा- एक्सक्यूज मी? और मुझे नहीं पता, लेकिन अनजाने में मैंने उसकी ओर देखा और फिर मुझे उसकी आंखों में डर दिखा। हम लगभग 10 सेकंड तक एक-दूसरे को देखते रहे और मैं उसकी आंखों में डर देख सकता था। अचानक वह मुड़ी और तेजी से भाग गई। उस समय मेरी यही मानसिक स्थिति थी।

यह गीत क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा है। ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाएं या गाना गाएं या फिर मौसम को बेईमान बताएं ठंड का अधिक प्रकोप होने से ठंड में कोई ये काम करे या ना करें मुझे इससे कोई मतलब नहीं, परंतु नहाने पर मैंने तो अपने लिए प्रतिबंध लगा दिया और यह सूचना सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर भेज दी थी।

ठंड में नहाना अनुकूल नहीं

ठंडी हवाओं के चलते ठंड में नहाने का मनोरथ बहुत अच्छे से अच्छा है लेकिन, ठंड के दिनों में यह मनोरथ बिल्कुल अनुकूल नहीं लग रहा है। समझ गए ना, ठंड में नहाने के परिणाम घातक रूप में प्राप्त हो सकते हैं?

किसी ने जरूर कहा कि, ठंडे-ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या न आए गाना चाहिए, हो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा बेईमान है आज मौसम। यह गीत क्या कहना चाहता है समझ में नहीं आ रहा है। ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाएं या गाना गाएं या फिर मौसम को बेईमान बताएं ठंड का अधिक प्रकोप होने से ठंड में कोई ये काम करे या ना करें मुझे इससे कोई मतलब नहीं, परंतु नहाने पर मैंने तो अपने लिए प्रतिबंध लगा दिया और यह सूचना सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म पर भेज दी थी। सूचना देखते ही परिवार व दोस्तों ने चार वेद, 18 पुराण के साथ-साथ कई धार्मिक ग्रंथों में नहाने के फायदे बताकर ज्ञान चंद गूगल वाले से ज्यादा ज्ञानी बनकर मेरे साथ तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और मेरे साथ राजनीति का खेल खेल रहे हैं।

ठंड का सम्मान करना ठीक है लेकिन सम्मान की जगह सम्मान है, नहाना अलग बात है, क्योंकि ठंड के दिनों में नहाते समय ठंडे पानी से ठंड ना लगे इसके लिए कुछ घरेलू टोने-टोटके अपना रहा हूं, जैसे जल के पास बैठकर कुछ देर तक ताकते रहना, स्पर्श स्नान करना, छींटा स्नान, चक्षु स्नान, दर्शन स्नान करके अपना काम निकाल रहा हूं और सबकी बाज जैसी नजरों से स्वयं को बचा रहा हूं। ठंड के दिनों में न नहाने के तरीके और बचने की राहों में तुम्हारे द्वारा बताए गए टोटके मेरे लिए सौ फीसदी कारगर साबित हो रहें हैं और मेरे हिसाब से ठंड के दिनों में न नहाने वाले को सिकंदर कहते हैं। मेरे द्वारा अपनाए गए टोटके अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर आप सुधी जन उपयोग करके सजग रहकर सावधान रहें तो बेहतर रहेगा।

पहला टोटका- सोमवार के दिन ठंड हो या न हो फिर भी अत्यधिक ठंड बताकर न नहाने का झूठा ही सही जोर-जोर से हल्ला मचाकर अपने आपको घरवालों के सामने ऐसा दिखना कि मैं नहाकर आ गया हूं और कुछ देर के लिए धूप में खड़े हो जाओ और ये मधुर गीत गुनगुनाते हुए बताना कि, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं।

दूसरा टोटका- मंगलवार के दिन मंगल भवन अमंगल हारी ठंड के दिनों में तेज हवाओं का प्रकोप जारी इस दिन ठंडे पानी से बिना कोई दंगल किए सिर्फ स्पर्श स्नान करके सहस बदन तुम्हरों यश गावें का काव्यात्मक भाव मन में धारण करने से स्नान पूर्ण मान लेना चाहिए।

तीसरा टोटका- बुधवार के दिन बुद्ध की तरह शांत रहकर परिवार से कोई युद्ध ना करें ठंड में अपने आप को बचाएं रखना और न नहाने का बुद्धि पूर्ण तरीके से तर्क पर तर्क देकर नहाने से बचने का भरसक प्रयास करें जैसे चुनाव जीतने के लिए नेता कौन-कौन से प्रयोग, रणनीति, चापलूसी आदि करता है।

चौथा टोटका- गुरुवार के दिन अपने आप को घर में गुरु ठंडेश्वर के परम भक्त की तरह मानते हुए नहाने से बचने के लिए मौनत्व भाव धारण करते हुए देर सवेर तक सोते रहे तो भी कोई बात नहीं और अगर कोई आवाज लगाएं तो उनसे कह देना ठंड के मौसम में ठंडेश्वर गुरु का ध्यान कर रहा हूं अत: आज नहाने की छुट्टी है।

पांचवां टोटका- शुक्रवार के दिन बीते चार दिनों में नहीं नहाने के जो उपाय अपनाएं हैं उन उपाय के प्रति ठंड का भरपूर शुक्रिया अदा करके अपने मन मस्तिष्क को ठंड की तरह ठंडा रख खुशी जाहिर कर सकते हैं और ठंड के दिनों में नहाने का जो संकल्प है उसे संकल्प के प्रति निष्ठावान बनकर अपने भाव के प्रति निश्चित रहे।

छठा टोटका- शनिवार के दिन अगर कोई परिवार का सदस्य, मित्र कहे की ठंड की दिनों में क्यों नहीं नहा रहे हो तो तुरंत कह देना कि ठंड के मौसम में शनि की साढ़ेसाती जैसी बुरी हवाएं लगी हुई हैं। अत: क्षमा चाहता हूं मुझे नहाने के लिए कोई बाध्य नहीं करें। संविधान द्वारा प्रदत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मानव अधिकार आयोग के साथ अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता हूं। अत: कोई अपना मुंह ना खोलें मुझे मजबूर न करें।

सातवां टोटका- रविवार के दिन छुट्टी का दिन है, आराम का दिन है, मौज-मस्ती करने का दिन होता है, इस दिन भी अगर कोई नहाने का बोले तो उनसे बोल देना कि ठंड के मौसम में नहाने की छुट्टी है। अत: सजग रहें सावधान रहें ठंड से बचें, नहाने से बचें रहे।

ठंड के मौसम में ना नहाकर अपने आप को समाज में सबसे बड़ा पानी बचतक बताना चाहिए और सभी को ठंड में न नहाने के टोने-टोटके, घरेलू नुस्खे बताना चाहिए और अगर किसी के पास इस तरह से कोई ओर टोटके हों तो वह एक-दूसरे को बताने से तनिक भी नहीं चूकना चाहिए। यह टोटके मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाए गए हैं, इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि ऐसे अचूक टोटके मेरे मित्र के द्वारा बताए गए हैं, जिन्हें में आपको बता रहा हूं। समझ गए ना, मैं क्या कहना चाहता हूं।

● **प्रकाश हेमावत**

डॉ. मोहन यादव

देश का दिल
लिख रहा
विकास का
नया अध्याय

नरेन्द्र मोदी

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश

अनंत संभावनाएँ

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट

24 25 फरवरी 2025, भोपाल

समिट की रूपरेखा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर-कमलों से शुभारंभ

- सेक्टोरल समिट
- थीमेटिक सेमिनार
- एग्जीबिशन एंड एक्सपो
- प्रवासी मध्यप्रदेश

पंजीकरण करने के लिए स्कैन करें।

www.investmp.in

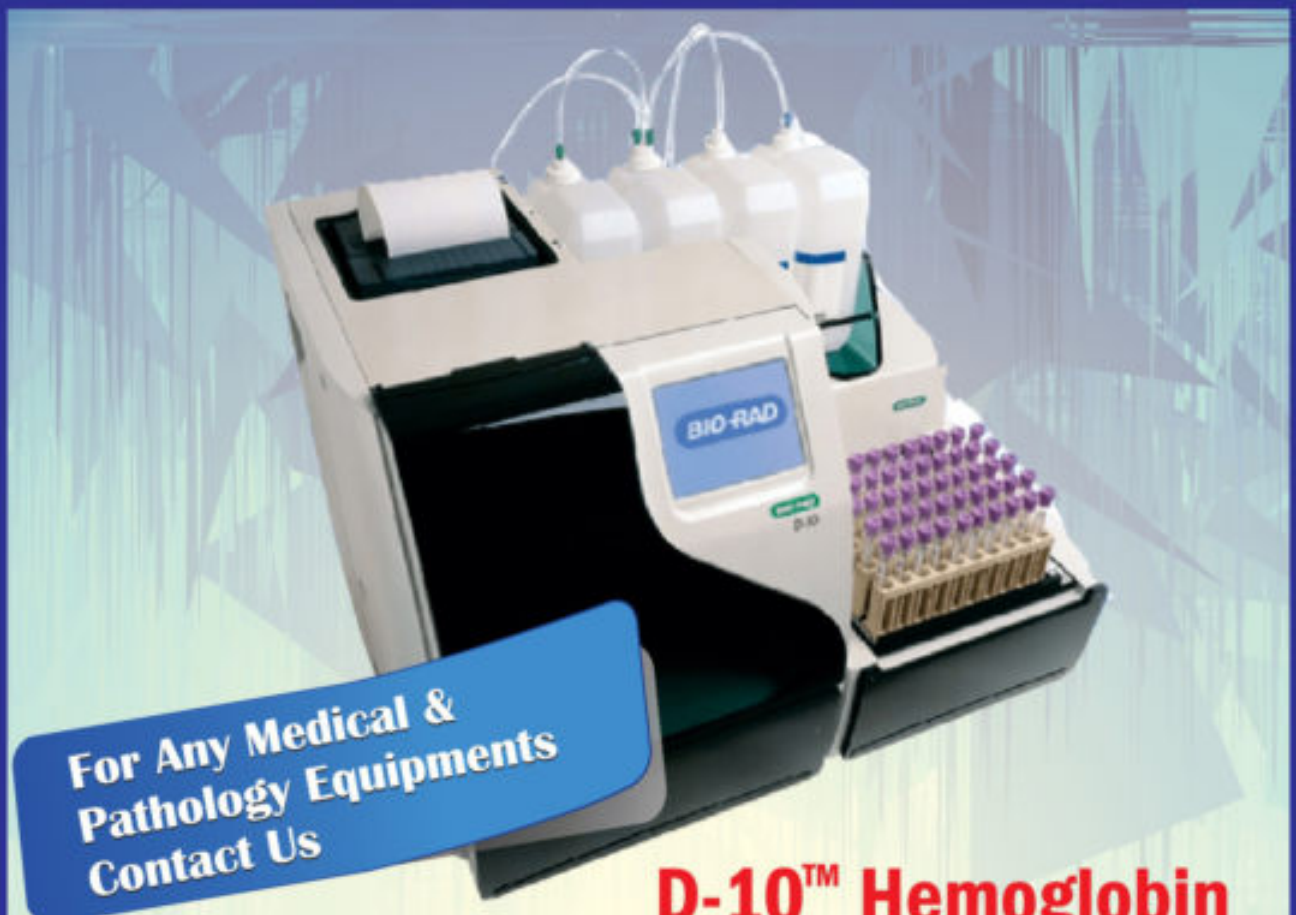

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687